हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

13 मार्च, 2001 (प्रथम बैठक)

खण्ड 1, अंक 7

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 13 मार्च, 2001

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(7)18
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7)23
विशेषाधिकार के भंग का प्रश्न तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं	(7)24
14 मार्च, 2001 को दूसरी बैठक	(7)25
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
बेरी कस्बे की सफाई की समस्या संबंधी	(7)29
वक्तव्य—	
उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी मुख्य संसदीय सचिव द्वारा	(7)29
तथाकथित विशेषाधिकार भंग की सूचना/उस पर निर्णय	
वाक आऊट	(7)36
सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र	(7)37
वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा	(7)37
बैठक का समय बढ़ाना	(7)62
वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)63
बैठक का समय बढ़ाना	(7)67
वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)67
बैठक का समय बढ़ाना	(7)69
वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)69

123

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh * LIBRARY

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 13 मार्च, 2001

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9-30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मेम्बर्ज अब सवाल होंगे।

Thermal Power Project in Yamunanagar

***359. Dr. Jai Parkash Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state the latest position of Yamunanagar Thermal Power Plant Project togetherwith the amount spent on its project report and acquisition of land alongwith the date from which the said land has been acquired ?

मुख्य मंत्री (श्री औम प्रकाश चौटाला) : एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

यमुनानगर ताप बिजली परियोजना दो चरणों में स्थापित की जानी प्रस्तावित है। चरण-1 के अन्तर्गत, एक कोयले पर आधारित 500 मैगावाट ताप बिजली केन्द्र की स्थापना करना प्रस्तावित है। इस परियोजना की स्थापना के लिए अंतिम प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए दस्तावेज वर्तमान समय में हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के विचाराधीन है।

परियोजना के दूसरे चरण में एक 500 मैगावाट गैस पर आधारित ताप बिजली केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 2004 से आगे गैस अथारिटी आफ इंडिया/गेल के माध्यम से रीगैसीफाईड एल०एन०जी० की उपलब्धता की सूचना दे दी है। दिनांक 13-2-2001 को हरियाणा तथा बिजली मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए हाल ही के एम०ओ०यू० में बिजली मंत्रालय ने यमुनानगर थर्मल (गैस/एल०एन०जी० पर आधारित) के क्रियान्वयन में सहायता देने का आश्वासन दिया है तथा निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय ताप बिजली निगम/एन०टी०पी०सी० इस परियोजना की सम्भाव्यता का अध्ययन प्रारम्भ करे।

इस परियोजना के लिए भूमि अभिग्रहण करने तथा सलाह सेवाओं जिसमें परियोजना रिपोर्ट तैयार करना शामिल है, पर लगभग 14 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

अब तक परियोजना के लिए 1107.87 एकड़ भूमि अभिग्रहण की गई है। वर्ष-अनुसार

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

अधिग्रहण की गई भूमि निम्न प्रकार से दी जाती है

वर्ष	क्षेत्र
1983-84	177.89 एकड़
1984-85	273.24 एकड़
1985-86	359.78 एकड़
1986-87	296.96 एकड़
कुल	**1107.87 एकड़**

Dr. Jai Parkash Sharma : Sir, I would also like to know about M.O.U. and the budget allocated, if at all, in this Budget ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : स्पीकर सर, इस परियोजना पर अब तक जो खर्चे हुए हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार है-भूमि पर खर्च 925.06 लाख रुपये, निरीक्षण एवं सर्वेक्षण पर 61.13 लाख रुपये, शैड व कार्यालय आदि के निर्माण पर 752.33 लाख रुपये, सलाह सेवाओं पर 482.08 लाख रुपये खर्च हुए हैं जिनका कुल जोड़ 2220.60 लाख रुपये है। जो जमीन एक्वायर की गई है वह 1107.87 एकड़ हैं। ईयर वाईज कितनी-कितनी अधिग्रहण की गई है इसकी डिटेल पटल पर रखी सूची में है। स्पीकर सर, अगर ये गांव वाइज अधिग्रहण की गई जमीन के बारे में पूछेंगे तो मैं इनको गांव वाइज डिटेल भी बता सकता हूं।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि यमुनानगर ताप परियोजना का कार्य कब शुरू हुआ, कितने मैगावाट की यूनिट लगनी थीं और किस-किस एजेन्सी ने कितने कितने समय तक कार्य किया? जिन एजेंसियों ने इस परियोजना के तहत कार्य किया, क्या वे एजेंसियां उस कार्य को करने के लिये सक्षम थीं? अगर थीं तो उसका ब्यौरा दें।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, यह परियोजना 1981-82 में बनाई गई थी और 420 मैगावाट की क्षमता की इस परियोजना को राजकीय क्षेत्र में स्थापित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं योजना आयोग ने स्वीकृत किया जो कि बिजली बोर्ड ने बनानी थी। बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए 1987 में यह निर्णय लिया गया कि इस परियोजना की क्षमता को 420 मैगावाट से बढ़ाकर 840 मैगावाट करके यह काम एन.टी.पी.सी. को दे दिया जाए। सात साल तक एन.टी.पी.सी ने काम भी किया। एन.टी.पी.सी. ने अपने हाथ में यह काम लेकर 752.33 लाख रुपये खर्च भी किये जैसे कि स्टोरेज, स्टाफ क्वार्टर्ज तथा शैडज आदि का काम उनके द्वारा किया गया। उसके बाद एन.टी.पी.सी. ने यह इच्छा जाहिर की या फिर उनसे लिखवा लिया कि एन.टी.पी.सी. इस परियोजना पर काम नहीं कर सकती। उसके बाद यह काम आइजनबर्ग नाम की कम्पनी को दिया गया और 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हाराव ने फरीदाबाद से कांग्रेस अधिवेशन के दौरान रिमोट कन्ट्रोल द्वारा इसका उद्घाटन किया। आइजनबर्ग के हाथों में यह काम तो दे दिया गया लेकिन वे इस काम को करने के लिये किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सके। उसके बाद 1994 में आइजनबर्ग के हाथों में दिये हुए इस काम में परियोजना की क्षमता को भी 840 मैगावाट से घटाकर 760 मैगावाट कर दिया गया जबकि यह एजेन्सी इस काम को करने के लिये सक्षम भी नहीं थी।

इसलिये सरकार ने 1996 में उस एम०ओ०यू० को रद्द कर दिया। फिर 1996 के पश्चात् यह

फैसला लिया गया कि इस कम्पनी को काम देने का जो तरीका था उसमें पारदर्शिता नहीं थी। साथ ही राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस परियोजना को बनाने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के जरिए प्रस्ताव मांगे जाएं क्योंकि पहला समझौता ज्ञापन पत्र के जरिए हुआ था जोकि पारदर्शी विधि से नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के जरिए प्रस्ताव मांगने के लिए तीन सलाहकार कम्पनियों तकनीकी, आर्थिक एवं कानूनी की दिसम्बर, 1997 से मार्च, 1998 के दौरान नियुक्त किया गया। इन सलाहकार कम्पनियों ने अप्रैल, 1998 में कार्य आरम्भ कर दिया। जुलाई, 1998 में सलाहकार कम्पनियों की मदद से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कम्पनियों का चयन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार किए गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कम्पनियों से उनकी काबलियत के बारे प्रस्ताव मांगे गए। इस विज्ञापन के जवाब में 11 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कम्पनियों ने अपने दस्तावेज भिजवाए जोकि सितम्बर, 1998 में खोले गए और उनमें से 10 कम्पनियों को इस परियोजना के निर्माण के लिए प्रस्ताव मांगने हेतु समृद्ध पाया गया। इन सभी कम्पनियों को मार्च, 1999 में इकट्ठा बुलाया गया ताकि इनके प्रस्ताव मंगवाने के लिए बातचीत की जा सके और प्रस्तावों के मूल्यांकन में कोई मुश्किल न आए। इन कम्पनियों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित दस्तावेजों में उचित फेर बदल की गई। हरियाणा राज्य सरकार ने इस मामले पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया ताकि इस समिति की सिफारिशों को मंत्रिपरिषद् के सम्मुख रखा जा सके। मंत्रिपरिषद् की सिफारिशों पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने इन दस्तावेजों को स्वीकृति दे दी और यह आदेश दिए कि इस सारी प्रक्रिया को कानूनी रूप से सही और स्पष्ट रखने के लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्वीकृति के लिए भेजा जाए। इन दस्तावेजों को सितम्बर 1999 में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्वीकृति के लिए भेजा गया। आयोग द्वारा भेजी गई टिप्पणियों पर जवाब जून, 2000 तक आ चुके थे। इस बारे में आयोग के साथ 1 अगस्त, 2000, 8 अगस्त, 2000 व 11 सितम्बर, 2000 को विचार विमर्श भी किया गया। आयोग का अंतिम निर्णय अभी अपेक्षित है। अध्यक्ष महोदय, यह तो फर्स्ट फेज की बात हुई है। अध्यक्ष महोदय, 1981 से लेकर हमारी सरकार आने से पहले भी और सरकारें रहीं लेकिन उन सरकारों के दौरान आयोग का कोई फैसला नहीं आया लेकिन 1987 में जब हमारी सरकार थी तब इस बारे में कार्यवाही हुई थी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक दूसरे फेज की बात है उस बारे में मैं बताना चाहूंगा। इस दौरान हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 3 जनवरी, 2001 को केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से बातचीत की गई और इस परियोजना को जल्दी क्रियान्वित करने बारे सोच विचार किया गया। 2 फरवरी, 2001 को मुख्य मंत्री महोदय द्वारा केन्द्रीय पैट्रोलियम एवं गैस मंत्री से बातचीत की गई। जिसमें इस परियोजना के लिए तरल प्राकृतिक गैस उपलब्ध करवाने के बारे आश्वासन दिया गया। केन्द्रीय मंत्री ने यह स्वीकार किया कि इस परियोजना के लिए 2004 के बाद गैस उपलब्ध करवा दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, 13 फरवरी, 2001 को केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार एवं हरियाणा राज्य सरकार के बीच ज्ञापन पत्र पर प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार द्वारा यह आश्वासन दिलाया गया कि इस परियोजना के चरण 2 यानि 500 मैगावाट क्षमता के लिए गैस अथवा तरल प्राकृतिक गैस पर आधारित प्लांट को शीघ्र पूरा करने में पूरा सहयोग दिया जाएगा। साथ ही एन०टी०पी०सी० को आदेश दिए गए कि वह तीन महीने के अन्दर इस परियोजना को बनाने के बारे अपनी रिपोर्ट पेश करे। इस प्रकार वर्तमान सरकार ने न केवल इस परियोजना को लागू करने बारे उचित कदम उठाए हैं बल्कि इसकी क्षमता को बढ़ाकर 1000 मैगावाट करने के लिए दो चरण में कार्य करने के बारे में पहल की है। पहले चरण में कोयले पर आधारित 500 मैगावाट की अतिरिक्त क्षमता के लिए एन०टी०पी०सी० द्वारा निर्माण करवाने हेतु प्रयास जारी रहेगा। इन दोनों

[श्री रामपाल माजरा]

चरणों का कार्य वर्ष 2004 तक पूरा होने की आशा है। इतनी तेजी से और इतनी गम्भीरता से किसी पहली सरकार द्वारा इस परियोजना को क्रियान्वित करने बारे कदम नहीं उठाए गए।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैंने सवाल पूछा था कि इस कार्य को एच०एस०ई०बी० ने भी नहीं किया और न ही यह काम एन०टी०पी०सी० को दिया गया था। मैंने सवाल पूछा था कि जिस आइजनबर्ग कम्पनी को यह काम दिया गया था, क्या उस कम्पनी की इस काम को करने की क्षमता थी और दूसरे क्या यह कम्पनी ब्लैकलिस्टिड थी या नहीं। कृपया मंत्री जी इस बारे में जानकारी दें।

मुख्य मंत्री (श्री औम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हरियाणा में बिजली का संकट है। यह संकट नहीं होना था अगर पुरानी सरकारें इस बारे में संभीरता से निर्णय लेती। जैसा कि सदन में बताया गया है कि 1981-82 से यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट बनाने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए बाकायदा 1107 एकड़ भूमि भी अधिग्रहण कर ली गई थी। यह काम एन०टी०पी०सी० को दे दिया गया था। शायद कृष्ण पंवार को ध्यान नहीं रहा कि एन०टी०पी०सी० ने इसको बनाये जाने की असमर्थता जाहिर नहीं की थी। बाकायदा इस पर काम शुरु हो चुका था और वहाँ पर मकान व चारदीवारी आदि भी बन गई थी। वहां पर करोड़ों रुपया खर्च हो चुका था। इसी बीच में सत्ता परिवर्तन हो गया। कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। विपक्ष के नेता मुख्य मंत्री के पद पर आसीन हो गए। उन्होंने इस सारे सिस्टम को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। उस वक्त की सरकार ने इस प्लांट को एन०टी०पी०सी० से बनवाने की बजाये एक ऐसी कम्पनी से बनवाने का निर्णय लिया जिसको टैक्नीकल जानकारी नहीं थी। यह कम्पनी आईजनबर्ग के नाम से थी। इस कम्पनी का काम तो बीच में कमीशन खाने का था। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसके पूरे बिस्तार में जाऊंगा तो बहुत सारा समय लग जायेगा। वहां पर कई अधिकारी इसको मान्यता प्रदान कराने के लिए भेजे गये और उसके बाद सौदे तय हुए। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार विकास के कामों को बड़ी गति दिया करती थी। उनके पास समय का बहुत बड़ा अभाव था इसलिए उस वक्त के प्राईममिनिस्टर ने इसका शिलान्यास रिमोट कन्ट्रोल से किया था। वहां पर न तो कोई पावर पैदा हुई और न ही इसका कोई वजूद रह पाया। जब हमारी सरकार दुबारा सत्ता में आई तो हमने इस पर बड़ी गम्भीरता से निर्णय लिया। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि बिजली का एक अहम् मुद्दा है। हरियाणा प्रदेश एक विकासशील प्रदेश है। आज हमारे यहां पर बिजली की बड़ी आवश्यकता है। आज सदन में मुझे कहते हुए बड़ा फख्र हो रहा है कि मौजूदा प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पिछले महीने की 13 तारीख को हरियाणा प्रदेश को 500-500 मैगावाट के तीन प्लांट गिफ्ट में दिये हैं। इनके जो एम०ओ०यू० साईन हुए हैं उनमें एक यमुनानगर का प्लांट शामिल है, दूसरा हिसार में है और तीसरा फरीदाबाद में सैकेण्ड फेज का है। अब इनकी आधारशिला रिमोट कन्ट्रोल से नहीं रखी जावेगी। हम इनको जल्दी से जल्दी तैयार करायेंगे ताकि हरियाणा प्रदेश बिजली के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हो बल्कि यहां पर सरपलस बिजली भी पैदा हो।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर बोलते हुए मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि पिछली सरकार ने यमुनानगर थर्मल प्लांट का काम किसी ऐसी कम्पनी को दे दिया जिसको इसकी टैक्नीकल जानकारी भी नहीं थी। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस कम्पनी ने इजराईल में व चाईना में 3-3 हजार मैगावाट के प्लांट लगाये थे या नहीं। दूसरी बात में यह कहना

चाहूंगा कि इस मामले में एन०टी०पी०सी० के साथ बैठकर बाकायदा विचार-विमर्श किया गया था। एन०टी०पी०सी० ने जब यह कहा कि हम इसको नहीं बना सकते तब बाद में सारी बातों को बड़ी गहराई से देखते हुए इस आईजनबर्ग कम्पनी को इस प्लांट का काम करने के लिए दिया गया था। जब भी इस बारे में कोई फैसला हुआ है चाहे वह 1983 में था या 1986 या 1987 में था इस प्रदेश का मुख्य मंत्री भजन लाल था। अध्यक्ष महोदय, इनके जमाने में इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई चाहे वह जमीन एक्वायर की कार्यवाही थी चाहे आगे की कार्यवाही थी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब यह सत्ता पक्ष में हुआ करते थे तब भी इनकी आदत सदन को गुमराह करने की थी और अब भी वे इससे बाज नहीं आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आईजनबर्ग नाम की कम्पनी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। क्या हरियाणा सरकार अपना अस्तित्व एक ऐसी कम्पनी को दे दे जिससे चौधरी भजन लाल ने सौदेबाजी की हो। (विघ्न) अगर इन की कारगुजारी को बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। (विघ्न एवं शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, यह क्वैश्चनज आवर है। आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) चौधरी भजन लाल जी की कोई बात रिकार्ड न की जाए। (विघ्न) चौधरी साहब, आप बैठिए। अपना भाषण बजट पर कर लीजिए। आप क्वैश्चन आवर का टाईम क्यों खराब कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी भजन लाल जी से केवल एक बात पूछना चाहूंगा कि वह सदन को बताएं कि क्या आईजनबर्ग कम्पनी ब्लैकलिस्टिड है या नहीं है?

चौधरी भजन लाल : आज का तो हमें पता नहीं है लेकिन उस समय ग्लोबल टैंडर में जितनी कम्पनियां आईं उनमें इससे बढ़िया कोई कम्पनी नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : आप कम्पनी का नाम तो बताएं। आपने कम्पनी का नाम एक बार भी नहीं लिया है। (विघ्न)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने यह बात मान तो ली है कि यह कम्पनी ब्लैकलिस्ट हो गई। (विघ्न) जैसे आपने कहा कि एन०टी०पी०सी० ने काम करने से इन्कार कर दिया। एन०टी०पी०सी० ने इन्कार क्यों किया क्योंकि इन्होंने उनको विवश किया। इन्होंने जो एक्सटरनल एड लेनी थी इसमें इन्होंने उनको को-आप्रेट नहीं किया इस वजह से आपने उनको आउट किया। आईजनबर्ग कम्पनी केवल एक कन्सलटैंट ऐजेंसी का काम करती है। जैसे एक आदमी सी०ए० है वह कोई निर्माण का काम नहीं करता है। जैसे लाईजिनिंग का काम है। अच्छे शब्दों में या सोफिस्टिकेटिड लैंग्वेज में उसे कमिशन एजैंट कहा जाता है जो कि वास्तव में दलाली का काम है। यह सही बात है कि यह काम वे लोग करते थे। अध्यक्ष महोदय, दलाली वाली बात मैं यहां नहीं कहता कि इन्होंने दलाली खाई या किसी और ने दलाली खाई हम तो यह कह रहे हैं कि वे काम दलाली का करते थे। दलाली कोई और खा गया होगा। दूसरे उसके बाद टारगेट उनको दिया गया था फाईनैंशियल कलोजर के लिए तो विपक्ष के नेता जी ये उस समय उसे पूरा नहीं कर सके। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि चौधरी बंसी लाल जी ने तरले किये। चौधरी बंसी लाल के टाइम में 1996 में तो इस एग्रीमैंट को टर्मिनेट किया गया था। इसमें साफ लिखा गया है Government also

---

* Not recorded as ordered by the chair.

[प्रो० सम्पत सिंह]

decided since the M.O.U. route lacked transparency इसके अन्दर ट्रांसपरेंसी नहीं थी। ट्रांसपरेंसी का मतलब पारदर्शिता है। इसका मतलब पारदर्शिता है। इसका मतलब यह है कि उसके अन्दर कहां क्या था क्या नहीं था। क्या कोई गड़बड़ थी या कोई घोटाला था या क्या मामला था। केवल यही कारण दर्शाया गया है एग्रीमैंट को टर्मिनेट करने का। जैसे कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 500 मैगावाट गैस बेसड प्लांट का एम०ओ०यू० 13-2-2001 को प्रधान मंत्री जी की प्रैजैंस में साईन किया गया और जो अचीवमैंट हरियाणा सरकार ने प्राप्त की है वह बहुत ही सराहनीय है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इससे पहले जैसे कि माननीय श्री रामपाल माजरा जी ने बताया है ओरिजनल 500 मैगावाट का जो कोल बेसड है वह ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसके ग्लोबल टैंडर तो हो गये हैं हरियाणा रैगुलेटरी इलैक्ट्रिसिटी कमिशन बना हुआ है उसके पास केस गया हुआ है वह केस जल्दी ही डिसाइड हो जाएगा। 500 जमा 500 मैगावाट कोल बेसड का एक्सट्रा है और 1000 मैगावाट पावर का प्लांट यमुनानगर में लगेगा (विघ्न)

Construction of P.H.C. At Majri

***313. Shri Jasbir Singh Mallour :** Will the Minister of State for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a P.H.C. in village Majri of the Naggal constituency on the 4 acres of the land said to have been transferred to the Health Department for the purpose by the said Village Panchayat ; if so, the time by which it will be constructed ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डॉ० एम०एल०रंगा) : जी हां, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण शिवालिक विकास बोर्ड अम्बाला द्वारा करवाया जा रहा है। जिसके लिए ग्राम पंचायत माजरी द्वारा 32 कनाल भूमि उपलब्ध करवाई गई है। भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम स्थानान्तरण हो चुकी है। शिवालिक विकास बोर्ड द्वारा इस भवन का निर्माण करवाया जायेगा।

श्री जसबीर मलौर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत माजरी में पंचायत ने चार एकड़ जमीन की रजिस्टरी करवा दी है। वहां पर पिछले कई सालों से पी०एच०सी० पंचायत की बिल्डिंग में चल रही है उस पी०एच०सी० में 14 गांवों के लोग जाते हैं और वहां पर लोगों के बैठने के लिए भी जगह नहीं है। जो चार एकड़ की जमीन की रजिस्टरी की गई है वहां पर लोगों ने नाजायज कब्जा करना शुरू कर दिया है। क्या मंत्री जी वहां पर जल्दी से जल्दी पी०एच०सी० बनवाने का कार्य करेंगे।

डॉ० एम०एल०रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि शिवालिक विकास बोर्ड ने इसके निर्माण के लिए 35 लाख रुपया ईयर मार्क कर दिया है। हम सम्बन्धित जिलाधीश महोदय, के माध्यम से उसका यथाशीघ्र निर्माण करने के लिए कह देंगे।

श्री रमेश राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि 1991 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी उन दिनों घरौंडा में 25 बैड का अस्पताल बनाने के लिए चौधरी भजन लाल जी के द्वारा नींव पत्थर रखा गया था। यह अलग बात है कि वहां पर कोई काम नहीं हुआ और कांग्रेस के लोग उसको देखकर शर्मिंदा हुए हैं। आज उस पत्थर पर कालिख पोत

दी है और अब उसका पता ही नहीं चलता है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि वहां पर वह पत्थर ही रहेगा या वहां पर उस अस्पताल को बनवाने का कष्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह सवाल रैलेवैंट नहीं है।

श्री सूरज मल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि 1987-88 में जब चौधरी देवी लाल जी की सरकार थी तब उन्होंने उस वक्त मुरथल गांव में 30 बैड का अस्पताल स्वीकार किया था और उसका काम भी शुरू हो गया था। लेकिन गवर्नमैंट बदलने के बाद वहां पर काम बंद कर दिया गया था और आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री जी से बात की थी लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है जबकि उन्होंने मंजूरी दे दी थी। क्या अब उस अस्पताल का कार्य दोबारा से शुरू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा?

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि पिछले 7-8 सालों में 25 ऐसे अस्पताल थे जिनके नींव पत्थर रख दिए गए थे या दीवारें खड़ी कर दी गई थीं और इस बीच में वे अधूरी ही पड़ी हुई थी। हमारी सरकार के आने के बाद एक साल के अन्दर 17 अस्पतालों को बनाकर उनका उद्घाटन कर दिया गया है। जहां तक ये मुरथल की बात कर रहे हैं अगर वहां पर पी०एच०सी० के बारे में मुख्यमंत्री जी ने या चौधरी देवी लाल जी ने पी०एच०सी० बनाने की बात कही है तो उस बारे में चैक करवाकर विचार कर लिया जाएगा।

श्री रामबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि हैली मण्डी में 14.3.1984 को एक अस्पताल नोटिफाई हुआ था और सेठ कल्याण दास ने 25 बैड की बिल्डिंग बनाकर दान दी थी और स्वास्थ्य विभाग ने उसको टेकओवर किया था। उसकी इनआगुरेशन 8-11-1985 को की गई थी। लेकिन आज तक सरकार ने उस अस्पताल को टेकओवर नहीं किया है, न ही उसको आज तक पी०डब्ल्यू०डी० ने टेकओवर किया है और न ही उसकी मरम्मत की गई है। यह रिकार्ड की बात है। अध्यक्ष महोदय, 12-12 बैड का अस्पताल गोड़ा कलां और पटौदी में जो हैं वह इनके अन्डर काम कर रहा है उसको 25 बैड के हास्पिटल का स्टेटस दिया जाए। क्या मंत्री जी उस अस्पताल को जल्दी से जल्दी पी०डब्ल्यू०डी० से टेकओवर करवाने की कृपा करेंगे।

डॉ० एम०एल०रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि हैलीमण्डी का अस्पताल श्री बिहारी लाल जैन जी ने दान दिया था। उनके दान देने के बाद 1994 में 95,000 रुपए उसकी मरम्मत के लिए मन्जूर किए गए थे और भिजवाए भी गए थे। उसके एक साल के बाद 1 लाख 27 हजार रुपए फिर से मरम्मत के लिए दिए गए थे और उसको पी०डब्ल्यू०डी० ने टेकओवर कर लिया था। इसमें अगर दोबारा से मरम्मत की आवश्यकता होगी तो हम उसको दोबारा से देख लेंगे।

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पी०एच०सी० बनाने के लिए सरकार ने क्या नार्म्ज रखे हैं?

डॉ० एम०एल०रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित साथी को बताना चाहूंगा कि पी०एच०सी० बनाने के लिए नोर्म्ज यह हैं कि कम से कम दो एकड़ जमीन का प्रावधान हो और तीस हजार की आबादी सराउंडिंग एरिया में होनी चाहिए तथा दस किलोमीटर की दूरी तक

[डा० एम०एल० रंगा]

कोई दूसरी पी०एच०सी० नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह नोर्म्ज हरियाणा सरकार के नहीं बल्कि भारत सरकार के हैं। इन नोर्म्ज को पूरा करने के लिए जनगणना होती रहती है और समय-समय पर ये नोर्म्ज रिवाइज किए जाते रहते हैं। आज के दिन जनगणना के हिसाब से जहां पर पी०एच०सी० होनी चाहिए वहां पी०एच०सी० है, जहां पर सी०एच०सी० होनी चाहिए वहां सी०एच०सी० है और जहां पर सब सैंटर्ज होने चाहिएं वहां सब सैंटर्ज हैं।

श्री चन्द्र भाटिया : आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे फरीदाबाद में बी०के० होस्पीटल के साथ-साथ एक दूसरी बिल्डिंग पहले बनकर तैयार हो गयी थी। मैंने पिछले सत्र में इस बारे में पूछा था कि हमारे फरीदाबाद में जिस तरीके से बी०के० होस्पीटल बना हुआ है क्या उसी तरीके से दो बिल्डिंगज बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तो उस समय मंत्री महोदय ने इसका जवाब हाँ में दिया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आज भी क्या ये दोनों बिल्डिंगज वहां पर बनाने का सरकार का इरादा है, अगर है, तो कब तक ये बनकर तैयार हो जाएंगी?

डॉ०एम०एल०रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि आज के दिन हमारे चार होस्पीटलज निर्माणाधीन हैं। ये चार होस्पीटल हैं—बी०के० होस्पीटल फरीदाबाद, एक पंचकूला का, एक रोहतक का और एक मांढीखेड़ा का। फरीदाबाद में एक ब्लाक बनने के लिए विचाराधीन है और जब भी धन का जुगाड़ हो जाएगा उसका काम चालू कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद में इसी साल के अंदर दो नये होस्पीटलज जो तीस बिस्तरों वाले हैं उनका शिलान्यास मुख्य मंत्री जी कर चुके हैं। इनके लिए भारत सरकार से पैसा आ चुका है और अब ये निर्माणाधीन हैं।

डॉ० सीताराम : अध्यक्ष महोदय, कालांवाली शहर में जो पी०एच०सी० है वह बहुत बढ़िया है। सरकार के पास इस बारे में एक केस भेजा गया है कि इसको जनरल होस्पीटल का दर्जा दिया जाए। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने कालांवाली होस्पीटल का जिक्र किया है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमें अभी तक इस प्रकार का पूर्ण रूप से प्रस्ताव नहीं मिला है लेकिन जब भी इस तरह का प्रस्ताव आएगा उसको नोर्म्ज के हिसाब से देखकर विचार कर लिया जाएगा।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, यूरोपियन कमीशन ने हिन्दुस्तान में स्वस्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए एक हजार करोड़ रुपये देने की बात कही थी। इसका जिक्र पिछले वर्ष के गवर्नर्स ऐड्रस में भी था कि पचास जिलों में से हरियाणा के तीन जिले भी कवर किये गये हैं। इन तीन जिलों में एक जिला अम्बाला भी था। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यूरोपियन कमीशन द्वारा इस तरह का जो पैसा दिया जाना था उसकी क्या प्रगति हुई है क्या वह पैसा आ गया है, अगर आ गया है तो कब तक अम्बाला जिले में काम आरम्भ कर दिया जाएगा?

डॉ० एम०एल०रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित साथी को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले सत्र के दौरान बताया गया था कि जब पूरे हिन्दुस्तान के जिलों की बारी आयी तो तीन जिले हरियाणा प्रदेश के चुने गए। ये जिले हैं अम्बाला, यमुनानगर और करनाल। अम्बाला में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए एक करोड़ 15 लाख की स्वीकृति आ चुकी है।

10-00 बजे उसमें से 20 लाख रुपया अम्बाला के लिए आ गया है और वह केवल अम्बाला कैन्ट और अम्बाला सिटी के लिए है। उस पर समिति बनी हुई है, वह इस पर विचार करेगी और विचार करके जो-जो आवश्यकताएं होंगी, उनको पूरा किया जायेगा। बिल्डिंग का प्रावधान इसमें नहीं है आगे जब पैसा आएगा तो उसमें बिल्डिंग का भी और दूसरा प्रावधान भी रखा गया है। भारत सरकार की कोई भी स्कीम आती है तो हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी उस स्कीम के लिए पूरा पैसा लेने की कोशिश करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी से मीटिंग करते हैं और जो पैसा ले सकते हैं, वह हमने लिया है। भारत सरकार से पिछले साल में पूरे हिन्दुस्तान में किसी स्टेट को 30 व्हीकल और किसी को 40 व्हीकल दिए गए हैं लेकिन हरियाणा को 100 से ज्यादा व्हीकल दिये गये हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे सारे प्रदेश में जहां हुड्डा ने सैक्टर डिवैलप किए हैं और गवर्नमैंट की दूसरी जमीनें होस्पीटल या नर्सिंग होम बनाने के लिए सरकार ने सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई हैं। दिल्ली के साथ लगते जो जिले हैं वहां जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम हैं, उनकी सेवा भावना नहीं है और जो टर्म्ज एंड कंडीशन हैं उनके अनुसार किसी भी नर्सिंग होम के अन्दर मरीजों की सेवा नहीं की जाती है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बिसला जी, आप क्वेशचन पूछें। यह कोई क्वेशचन नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात रख रहा हूँ। जब किसी मरीज को बुखार होता है तब भी उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं और उसका 50 हजार रुपये का बिल बना देते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं क्या मंत्री महोदय ऐसे नर्सिंग होम्ज का सर्वे कराएंगे ताकि आम आदमी को लुटने से बचाया जा सके। क्या ऐसा कोई कार्यक्रम सरकार की नजर में है?

डॉ० एम०एल०रंगा : अध्यक्ष महोदय, बिसला जी ने जो बताया है, यदि ऐसा कोई अस्पताल उनको ध्यान में है तो वे बताएं ताकि उसके ऊपर नजर रखी जाए और वहां के रेट मंगाए जाएं। उसके लिए हमारे पास इंस्पैक्टर हैं, डी०एच०ओ० हैं दूसरे अधिकारी भी हैं और आगे से इस प्रकार की शिकायत पर पूरा गौर किया जायेगा।

Construction/Upgradation of Schools

*** 435. Smt. Anita Yadav :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Govt. High School, Village Khanpur Khurd to 10+2 level ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह) : नहीं, श्रीमान जी।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न खानपुर खुर्द के दस जमा दो स्कूल के बारे में है और उसका जवाब मंत्री जी ने 'न' में दिया है क्या फ्यूचर में स्टूडैंट्स के कैरियर को देखते हुए आपकी सरकार में इस तरह की कोई बात विचाराधीन है। स्टूडैंट्स स्कूल के लिए दूर-दूर तक पैदल जाकर अपना सारा समय खो देते हैं यदि खानपुर खुर्द में जमा दो का स्कूल हो जाए तो स्टूडैंट्स का समय बचाया जा सकता है और उनके कैरियर को बचाया जा सकता है।

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्टूडैंट्स के वैलफेयर का सबसे ज्यादा ध्यान हम

[चौधरी बहादुर सिंह]
रखते हैं माननीय सदस्या खानपुर खुर्द का जिक्र कर रही हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो स्कूल के नॉर्म्स फिक्स किए हुए हैं वह पूरे करवाकर प्रस्ताव भेज दें और अगर बजट का प्रोविजन होगा तो इस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो फारमैलिटीज या नॉर्म्ज रखे हैं, वह सारे पूरे हैं, कई बार इसका रिजोल्यूशन भी सरकार तक पहुंचाया जा चुका है लेकिन आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

चौधरी बहादुर सिंह : इस बारे में कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है इसका प्रस्ताव भिजवा दें, प्रस्ताव आते ही इस पर विचार कर लिया जाएगा।

---

33 KV Sub-station in Beri Constituency

*** 391. Dr. Raghubir Singh Kadian :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under considration of the Government to complete the 33 K.V. sub-station at Jhajgarh in Beri Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which it is likely to start functioning ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : (क) तथा (ख) एक नया 33 के.वी. उपकेन्द्र जहाजगढ़ में पहले ही दिनांक 19-1-2001 से चालू हो चुका है तथा कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, इस 33 के.वी. के सब-स्टेशन की फाउंडेशन 1994 में रखी गई थी और इसकी कंपलीशन 2001 में होनी थी जिसको लगभग सात साल हो गए हैं। इस बारे में बजट ऐस्टीमेट पास हुआ था और जो पेमेंट हुई उसमें कितना ऐसकेलेशन था और कितना बजट प्रोविजन था।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, इस सब-स्टेशन की आधारशिला 1994 में रखी गई थी उसके बाद 1995 में प्रदेश में बाढ़ आ गई थी और इस सब-स्टेशन की मशीनरी छः फीट पानी में डूब गई थी। उसके बाद इस सब-स्टेशन को ऊपर उठाने के लिये रिमाईन्ड्ड प्लान बनाई गई। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस सब-स्टेशन को ऊपर उठाकर बनाया गया है ? या इसे बाढ़ से बचाने के लिए क्या-क्या मेजर अपनाए गए हैं।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : स्पीकर सर, यह ठीक है कि इस सब-स्टेशन की आधारशिला 1994 में रखी गई थी और धन का प्रावधान करने का काम महकमे पर छोड़ दिया गया था। जैसा कि विदित है उस समय इस सब स्टेशन की आधारशिला तो रख दी थी लेकिन धन का प्रावधान नहीं किया गया और इसको बीच में ही लटका दिया गया। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन हमारी सरकार ने आर.इ. सी. से लोन लेकर इस सब-स्टेशन को बनाने का काम

युद्धस्तर पर किया और सात महीने में इस सब-स्टेशन को बनाने का काम कर दिया। 19 जून 2000 को यह सब-स्टेशन बनकर तैयार हो गया और इसका काम चालू हो गया। पहले तो इसको चालू करने की भी समस्या हो रही थी। (विघ्न)

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बड़ौदा हल्के के बुटाना गांव में 33 के.वी. का सब-स्टेशन बनने के लिये मंजूर हुआ था लेकिन उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसका काम कब शुरू किया जायेगा।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि वे इसके लिए अलग से नोटिस दे दें तो इनको उसका जवाब दे दिया जाएगा। यह प्रश्न तो स्पेसिफिकली श्री रघुबीर सिंह कादियान जी का था।

श्री बलवंत सिंह मायना : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस सब-स्टेशन से किन-किन गांवों को फायदा होगा।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, इस सब-स्टेशन को बनाने में 78 लाख रुपये की लागत आई है और इसमें 14.74 किलोमीटर लम्बी लाइन बिछाई गई है। इस सब-स्टेशन से लगभग दस गांवों का फायदा होगा जिसमें जहाजगढ़, माजरा, मारोत, ढाणी, इस्लामगढ़, गवालीसन, पलड़ा, चौड़, खेड़ी खुर्द, खातीवास शामिल हैं। इन गांवों को अब बिना रुकावट के बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि तोशाम में 1995 में 132 के.वी. का जो सब-स्टेशन बनना शुरू हुआ था वह कब तक पूरा हो जाएगा?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, माननीय सदस्य इसके लिए अलग से नोटिस भेज दें तो इनको जवाब भेज दिया जायेगा। वैसे 1995 में सत्ता में कांग्रेस की ही सरकार थी।

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कैथल हल्के के गांव क्योडक में 33 के०वी० का सब-स्टेशन बनाने के लिए मंजूर हुआ था वह कब तक बनकर तैयार हो जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी जब कैथल में आये थे तो उन्होंने इस सब-स्टेशन का जल्दी बनाने का आश्वासन दिया था।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, ठीक है क्योडक गांव में जब माननीय मुख्य मंत्री जी गए थे तो लोगों ने सब-स्टेशन बनाने की मांग मुख्य मंत्री जी के सामने रखी थी।

अध्यक्ष महोदय, यह बात आप भी जानते हैं और सारा सदन यह जानता है कि जहां आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय के मुंह से विकास मील के पत्थर के बारे में शब्द निकले हैं, वे टल नहीं सकते और कोई बात तो टल भी सकती है। वहां की हमने सर्वे रिपोर्ट मांगी है, वहां जमीन की एलोकेशन के बारे में पंचायतों के प्रस्ताव मांगे हैं, ज्यों ही प्रस्ताव आ जाएंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी और जैसा कि लीला राम जी ने पावर स्टेशन बनाने के लिए कहा है तो पावर स्टेशन बना देंगे।

———

Upgradation of Schools

***461 Shri Krishan Lal :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under considration of the Govt. to upgrade the following schools-

[Shri Krishan Lal]

(a) from Govt. High School Buwana Lakhu (Panipat) to Government Senior Secondary School ;

(b) from Government High School Urlana Kalan (Panipat) to Government Senior Secondary School ;

(c) from Government High School Shahpur (Panipat) to Government Senior Secondary School ;

(d) from Government High School Dahar (Panipat) to Government Senior Secondary School ;

(e) from Government High School Sutana (Panipat) to Government Senior Secondary School ;

(f) from Government High School Nangal Kheri (Panipat) to Government Senior Secondary School ;

(g) from Government High School Madlauda (Panipat) to Government Senior Secondary School ; and

(h) from Government High School Dharamgarh (Panipat) to Government Senior Secondary School ; if so, the time by which the above said schools are likely to be upgraded ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह) : नहीं, श्रीमान जी।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन राजकीय उच्च विद्यालयों को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तक अपग्रेड करने के लिए प्रत्येक स्कूल को अलग-2 कितनी लैंड और कितनी बिल्डिंग एलोकेट की जाएगी जिन स्कूलों के नार्म्स पूरे होते हैं, क्या उनको अपग्रेड करेंगे ? और जिन स्कूलों के नार्म्स पूरे नहीं होते उन स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए क्या कोई मामला सरकार के पास विचाराधीन है ? स्पीकर सर, इन 8 स्कूलों में से 6 स्कूल आपकी कांस्टीच्यूंसी में पड़ते हैं और 2 स्कूल असन्ध कांस्टीच्यूंसी में पड़ते हैं।

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि राजकीय उच्च विद्यालय बुवाना लाखू, उरलाना कलां, शाहपुर, डाहर, सुताना, नंगल खेड़ी, मडलौडा तथा धर्मगढ़, इन 8 स्कूलों को अपग्रेड करने का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है। अगर माननीय साथी कहते हैं कि इनके नार्म्स पूरे हैं तो हम डी०ई०ओ०, पानीपत को कह देंगे कि इन स्कूलों की इंस्पैक्शन करवाकर रिपोर्ट भेजें। अगर इन स्कूलों के नार्म्स पूरे होंगे तो इनको कंसीडर करके और बजट में प्रोविजन करके इन स्कूलों को अपग्रेड कर दिया जाएगा।

श्री अमर सिंह ढांडे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार का सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम "सरकार आपके द्वार" में आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की थी मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन पंचायतों ने हाई कोर्ट के निर्देशानुसार नार्म्स पूरे करके सम्बन्धित डी०सी० और डी०ई०ओ० को रिपोर्ट भी भेज दी है तो क्या उन स्कूलों में इस सत्र से क्लॉसिज शुरू हो जाएंगी।

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि क्लॉसिज के बारे में तो हम अभी नहीं कह सकते लेकिन जिस स्कूल की ये बात कर रहे हैं, वह कहां का है। इसके लिए कागज वगैरह यानि नार्म्स देखने पड़ते हैं और कागज देखने के बाद बताया जा सकता है कि क्लॉसिज कब शुरू की जाएंगी ?

श्री अध्यक्ष : बुवाना लाखू, उरलाना कलां, शाहपुर के स्कूलों को 27.3.91 को अपग्रेड किया गया था लेकिन सरकार के परिवर्तित होने के बाद ये लिस्ट रद्द कर दी गई। क्या ये स्कूल दोबारा से अपग्रेड होंगे यदि इनके नार्म्स पूरे हैं तो ये कब तक अपग्रेड होंगे ?

चौधरी बहादुर सिंह : अगर इन स्कूलों के नार्म्स पूरे हैं तो बजट में प्रावधान करवाकर इनको अपग्रेड कर दिया जाएगा।

श्री बलवंत सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जहां तक नार्म्स की बात है तो क्या डी०सी० जिले वाइज इस प्रकार की रिपोर्ट मांगने का काम करेंगे किस-2 जिले में किस-2 गांव के स्कूलों के नार्म्स इस बारे में पूरे होते हैं ?

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इसके लिए हमें डी०सी० से रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है। हर जिले में डी०ई०ओ० होता है, हम उनको कह देंगे कि सारे स्कूलों का इंस्पैक्शन कराके रिपोर्ट भेजें।

Construction of Local Bus Stand at Ambala Cantt.

***411. Shri Anil Vij :** Will the Minister for Transport be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under considration of the Government to construct a local Bus Stand for local buses at Ambala Cantt; and

(b) if so, the time by which it is likely to be materialized ?

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार) :

(क) नहीं श्रीमान जी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है कि प्रश्न ही पैदा नहीं होता, उस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि अम्बाला छावनी में लोकल बसों के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं है। स्टेशन और बस स्टैंड के पास सारा दिन पैसेंजर इधर-उधर घूमते रहते हैं। इसलिए क्या इस पर सरकार कोई विचार करेगी ?

श्री अशोक कुमार : स्पीकर सर, अंबाला छावनी में 12.7.1999 को नये बस अड्डे का उद्घाटन हुआ था और जो लोकल बसें हैं वे अंबाला शहर और महेशनगर से होती हुई अंबाला छावनी पहुंचती हैं। वहां पर 9 बसें लगातार चलती हैं और एक बस 8 चक्कर लगाती है। इस तरह से टोटल 72 चक्कर एक दिन में लगते हैं। इसलिये अभी अंबाला छावनी में स्थानीय बसों के लिए स्थानीय बस

[श्री अशोक कुमार]

अड्डा बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगी उस वक्त बना दिया जाएगा।

श्री बलवंत सिंह मायना : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि रोहतक का बस स्टैंड बहुत पुराना बना हुआ है और यह शहर के अन्दर है। क्या सरकार के पास इस बस स्टैंड को शहर से बाहर बनाने की कोई योजना है?

श्री अशोक कुमार : स्पीकर सर, मैं मेरे माननीय साथी मायना साहब को बताना चाहूंगा कि रोहतक के बस स्टैंड को शहर से बाहर लाने की सरकार की योजना है।

श्री जय प्रकाश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि करनाल में जो सैक्टर 12 का एक नया बस अड्डा बनना प्रस्तावित है वह कब तक बनाया जाएगा?

श्री अशोक कुमार : स्पीकर सर, वैसे तो यह मामला अंबाला छावनी के बारे में था लेकिन फिर भी मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि करनाल के सैक्टर 12 में नया बस अड्डा बनाने के बारे में हम हुड्डा से बातचीत कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसे जल्दी बनाया जाये।

श्री सूरजमल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमारे यहां जो बसें हरियाणा रोडवेज की चण्डीगढ़, अंबाला और करनाल से चलती हैं वे मुरथल व बहालगढ़ आदि जगहों पर नहीं रुकतीं और दिल्ली के नजदीक होने के कारण अंबाला और चण्डीगढ़ की तरफ से आने वाली बसें भी नहीं रुकतीं। जिससे हमारे यहां के जो डेली यात्री हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मुरथल और बहालगढ़ में बस स्टाप बनवा दें और यहां पर हरियाणा रोडवेज की बसों को रोकने की हिदायतें जारी कर दें ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो।

श्री अशोक कुमार : स्पीकर सर, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जहां पर भी जरूरत होती है हम वहां पर बस क्यू शैल्टर या बस स्टाप बनवा रहे हैं और जनता को किसी तरह की परेशानी न हो इसकी हम पूरी पूरी कोशिश भी करते हैं। हमने सभी जी०एमज० को इस बारे में हिदायतें जारी की हुई हैं कि रास्ते में जहां भी बस स्टाप आये वहां पर ड्राईवर बस रोके और इस बारे में हिदायतें ड्राईवरों को भी जारी की हुई हैं। मेरे माननीय साथी बहालगढ़ और मुरथल के बारे में लिखित में हमें दे दें हम इसका सर्वे करवा लेंगे और वहां पर बस स्टाप बनवा देंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मंत्री जी ने अभी बताया था कि रोहतक के पुराने बस स्टैंड को रोहतक से बाहर बनाने की योजना है। इस बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह बस स्टैण्ड समयबद्ध योजना से बनाया जाएगा। अगर बनाया जाएगा तो कब तक बनाया जाएगा?

श्री अशोक कुमार : स्पीकर सर, मैं हुड्डा साहब को बताना चाहूंगा कि यह बस स्टैण्ड जल्दी से जल्दी बनाया जाएगा और जहां तक समयबद्ध योजना की बात है इसके लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया है कि कब तक बनाया जाएगा।

श्री राजेन्द्र सिंह खिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा रोडवेज की जो डीलक्स बसें दिल्ली से शिमला वाया चण्डीगढ़ जाती हैं वे बहुत अच्छी बसें हैं और लोग इन बसों में चलना पसंद भी करते हैं। लोगों की बहुत पुरानी मांग है कि ये बसें

आगरा के लिए भी चलें। आगरा में पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट भी आते हैं और इससे हरियाणा रोडवेज को फायदा भी होगा। हमारे हरियाणा रोडवेज की बसें पूरे हिन्दुस्तान में सबसे अच्छी हैं यदि डीलक्स बसें आगरा से चण्डीगढ़ वाया दिल्ली चला दी जायें तो यह बहुत अच्छा होगा और लोगों की पुरानी मांग भी पूरी हो जाएगी तथा यह रूट फायदेमंद भी होगा। इसलिये मैं मंत्री जी से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि लोगों की मांग को मध्यनजर रखते हुए उनकी मांग को पूरा करें।

श्री अशोक कुमार : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम कांग्रेस के साथी प्रश्न काल के दौरान तो आराम से बैठा करें। इनमें से कई सदस्य तो मंत्री भी रह चुके हैं। ये बीच में टोका-टाकी करते रहते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री अशोक कुमार : स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश के अन्दर जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में यह सरकार आई है तब से हमने यह नहीं सोचा कि किन किन रूटों से ज्यादा कमाई हो रही है या ज्यादा रिसीट आ रही है बल्कि इस बात को ध्यान में रखा कि जहां-जहां लोगों की जरूरत थी वहां पर बसें चलाई जायें। पिछली सरकार ने तो अंधाधुध ईंटर स्टेट के परमिट जारी करके गांवों के रूटों की बसें बंद कर दी थीं जिसकी वजह से मैक्सी कैब और दूसरे अनऑथोराइज्ड वाहनों को बढ़ावा मिला। हमारी सरकार आने के बाद हमने ऐसे उन 150 रूटों पर ज्यादा सुविधायें देने का निर्णय लिया है जिन गांवों के रूटों पर पिछली सरकार ने यह सुविधायें बंद कर दी थी। इसलिये माननीय साथी अगर कोई ऐसी सुविधा जरूरी समझते हैं तो लिखकर दे दें और अगर लोगों की जरूरत होगी तो जरूरत के हिसाब से बस सुविधा दे देंगे।

तारांकित प्रश्न सं० 536

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री भगवान सहाय रावत सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Subzi Mandi at Jhajjar

***593. Shri Darao Singh :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the time which the Subzi Mandi at Jhajjar is likely to be shifted to the new subzi mandi?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह संधू) : नई सब्जी मण्डी, झज्जर में दुकानों और बूथों का निर्माण कार्य मार्च 2003 तक पूरा होने की संभावना है। तत्पश्चात् पुरानी सब्जी मण्डी को नई सब्जी मण्डी में स्थानान्तरित करने के लिये आवश्यक पग उठाये जाएंगे।

श्री दरियाव सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि नई सब्जी मण्डी कब तक शिफ्ट हो जाएगी यहां सब्जी मण्डी से रोजाना कलकत्ता और बम्बई जैसे लम्बे-लम्बे रूटों के लिये 100-100 ट्रक लगातार जाते रहते हैं इसलिये काफी रश हो जाता है।

सरदार जसविंदर सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, इस मण्डी को स्थानांतरित करने के लिये हमने समय भी नियत कर दिया है। मार्च 2003 तक नई सब्जी मण्डी का काम पूरा कर दिया जाएगा।

श्री रामबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि गुड़गांव में जो सब्जी मण्डी का निर्माण किया जाना था जिसके लिये प्लाट भी औक्शन किये जा चुके हैं और इसे दस साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक यह सब्जी मण्डी नहीं बनी है। वर्तमान अनाज मण्डी में किसान और व्यापारी अपना कारोबार कर रहे हैं जिसके कारण उनको बड़ी भारी दिक्कत है। क्या इस सब्जी मण्डी को बनाये जाने के बारे में कोई कार्यवाही की जाएगी?

सरदार जसविंद्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह एक अलग सवाल है फिर भी मैं माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि पिछली दोनों सरकारों ने सिवाय पत्थर रखने के और कोई काम नहीं किया। फिर भी माननीय सदस्य अलग से सवाल दे दें उसके बारे में हम जल्दी कार्यवाही करेंगे।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि जो छछरौली मण्डी है वहां सबसे ज्यादा अनाज आता है और वह अभी तक पूरी नहीं बनी है। मुख्य मंत्री जी ने भी इस मण्डी के निर्माण का कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया था लेकिन यह अभी तक पूरी नहीं बनी है जिसके कारण किसानों को भारी दिक्कत है। पिछली बार भी किसानों को अपना सारा धान सड़कों पर डालना पड़ा था जिसकी वजह से उनको काफी नुक्सान उठाना पड़ा था।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार की भरपूर कोशिश है कि किसी किसान को अपनी सब्जी या दूसरा अनाज मण्डी में ले जाने के लिए 10 किलोमीटर से दूर न जाना पड़े। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की घोषणा करके आए हैं तो उस बात पर जल्दी गौर करके उस मण्डी का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, शायद सारे हरियाणा में अंबाला छावनी एक ऐसा शहर होगा जिसमें अलग से अनाज मण्डी नहीं है, लेकिन अब इस सरकार ने वहां पर मण्डी बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। वहां पर मण्डी के लिए 80 एकड़ जमीन एक्वायर करने के लिए सैक्शन चार का नोटिस हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वहां पर मण्डी बनाने के काम को एक्सपीडाइट करवाने के लिए क्या सरकार टाइमबाउंड योजना बनाने पर विचार करेगी ताकि वहां पर समय सीमा के अंदर ही मण्डी बनकर तैयार हो जाए?

सरदार जसविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खुद कहा है कि वहां पर मण्डी बनाने के लिए जमीन एक्वायर करने के लिए सैक्शन चार का नोटिस हो चुका है। लेकिन जो सैक्शन—6 का नोटिस होता है उसकी भी प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी होती है। सैक्शन 6 का नोटिस होने के बाद उस मण्डी को बनाने का काम जल्दी शुरू करवा दिया जाएगा।

———

Construction of Hospital Building at Sadhaura

***383 Shri Balwant Singh Sadhaura :** Will the Minister of State for Health be pleased to state —

(a) Whether the Government is aware of the fact that the Building of Civil Hospital, Sadhaura is in dilapidated condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under considration of the Government to construct a new building for the above said hospital?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० एम०एल० रंगा) :

(क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

डॉ० एम०एल०रंगा : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य के दो प्रश्न हैं। पहले प्रश्न का जवाब यह है कि मुझे यह ज्ञात है कि सढौरा पी०एच०सी० की बिल्डिंग की हालत जीर्ण-शीर्ण है तथा दूसरे प्रश्न का जवाब यह है कि इसके निर्माण के लिए सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री बलवंत सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, सढ़ौरा होस्पीटल की बिल्डिंग जर-जर हालत में है और यह बिल्डिंग 5-6 साल पहले अनसेफ डिक्लेयर की गई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वहां पर होस्पीटल की बिल्डिंग बनाने के लिए कितने धन का प्रावधान किया गया है और वह कितने समय में बन कर तैयार हो जाएगी।

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो पी०एच०सी० हैं वह 1980 से चल रही है। उसकी बिल्डिंग जीर्ण-शीर्ण हालत के बारे में हमारे पास 1998 में रिपोर्ट आई थी। उसके बाद उसकी बिल्डिंग के नव निर्माण के बारे में हमारे पास प्रस्ताव आ गया। हमने उसका एस्टीमेट नारायणगढ़ के पी०डब्ल्यू०डी० ऑफिस से बनवाया। उसका डिजाईन तैयार हो गया है और शिवालिक विकास बोर्ड को उसका निर्माण करने के लिए कहा गया है। उन्होंने अपने बजट में 35 लाख रुपये ईयरमार्क किया है और यह कहा है कि जब उनके पास धन की उपलब्धता होगी उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमने भारत सरकार की संस्था जो आर०सी०एस० स्कीम के तहत नई बिल्डिंग बनाती है को प्रार्थना की और उन्होंने ओ०टी० और एक लेबर रूम बनाने के लिए 6 लाख 85 हजार 410 रुपये मंजूर कर दिए हैं। वह पैसा आने पर उसका काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा।

श्री रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, चरखी दादरी में 1980 में सिविल अस्पताल बनाने का काम शुरू किया गया था लेकिन बाद की सरकारों ने उस काम को वहीं पर रोक दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस अस्पताल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य पुनः चालू करने के बारे में क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

डॉ०एम०एल०रंगा : वैसे तो चरखी दादरी का होस्पीटल जहां नया बना था वहां शिफ्ट कर दिया गया है और वहां पर वह सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अलावा वहां पर कोई नया निर्माण करने का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में एक खानक गांव है वहां पर कल से कम 200 स्टोन क्रैशरज हैं और उन पर कम से कम 15000 के करीब लेबर काम करती है। वहां पर हमारे सांसद श्री अजय सिंह चौटाला जी गए थे और उन्होंने वहां पर अस्पताल बनाने के बारे में आश्वासन दिया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके आश्वासन के बारे मे कोई कार्यवाही चल रही है या नहीं?

डा० एम०एल०रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैंने सम्मानित सदस्य को पहले भी इस बारे में बताया

[डॉ० एम०एल० रंगा]

था और आज फिर बता देता हूँ। पी०एच०सी बनाने के लिए 30 हजार की आबादी का क्राइटेरिया रखा हुआ है। वहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं वे बाहर के हैं हरियाणा के नहीं हैं। वे मजदूर हरियाणा की जनगणना में हैं या नहीं इस बात का पता कर लिया जाएगा। यदि वे हरियाणा की जनगणना में हैं और वहां पर पी०एच०सी० खोलने के लिए आबादी का क्राइटेरिया पूरा है तो वहां पर पी०एच०सी० जरूर बना दी जाएगी।

श्री कपूर चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, शाहबाद मारकण्डा का जो होस्पीटल है वह 1912 से पहले का बना हुआ होस्पीटल है। वह हरियाणा में सबसे पुराना होस्पीटल है। उस होस्पीटल में 30 बैड हैं। वहाँ का स्टाफ पूरा है। वह जी०टी० रोड पर होने के कारण उसमें डेली एक्सीडैंटस् के केस आते हैं। लेकिन उस होस्पीटल में डाक्टरों के बैठने के लिए पर्याप्त कमरे नहीं हैं। कुछ कमरों में सूअर घूमते रहते हैं। उस होस्पीटल की बिल्डिंग बिल्कुल जर-जर हो चुकी है। डॉक्टर भी किराए पर दूर-दूर रहते हैं। वहां पर एस०एम०ओ० भी नहीं रह सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार उस होस्पीटल की तरफ ध्यान देगी।

डॉ० एम०एल०रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि वहां पर जहां तक डॉक्टरों के रिहायशी मकानों के बनाने की बात है जब भी सरकार के पास धन उपलब्ध हो जाएगा उस समय उस बारे में विचार कर लिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैंबर्ज, अब क्वैश्चनज आवर समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

I.T.I. In Ratia

*468 **Shri Jarnail Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under considration of the Government to open I.T.I. in Ratia; if so, the details thereof?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : महोदय, रतिया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Opening of Government College in Guhla

*455. **Shri Amar Singh Dhanday :** Will the Minister of State for Education be pleased to state —

(a) Whether there is any scheme under considration of the Government to open Govt. College in Guhla, District Kaithal; and

(b) if so, the time by which it is likely to start functioning?

शिक्षा मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह) :

(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) (क) के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं उठता।

Government Girls Senior Secondary School in Datrath

*** 448. Shri Ram Kumar Katwal :** Will the Minister of state for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government Girls Senior Secondary School (10+2) at village Darath in Rajond Constituency ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह) : हां श्रीमान जी जब बजट उपलब्ध हो जाएगा, स्कूल का स्तर बढ़ा दिया जाएगा।

Shagan

*** 579 Dr. Sita Ram :** Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state the criteria adopted for providing of Rs. 5100/- to the persons belonging to Harijan Category under the Shagan Scheme?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री रिसाल सिंह) : श्रीमान जी, मानदण्ड निम्न प्रकार से अपनाया जाता है :—

1. लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
2. वह हरियाणा के अनुसूचित जाति परिवार की स्थाई निवासी हो।
3. यह अनुदान राशि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति के परिवारों को दी जाती है।
4. यह अनुदान अनुसूचित जाति की ऐसी महिलाओं को भी दिया जाएगा जो विधवा हैं या तलाकशुदा हैं और दोबारा शादी करने जा रही हैं।
5. यह अनुदान परिवार में केवल दो लड़कियों की शादी तक उपलब्ध होगा।

Repair of hospital building

*** 282 Shri Dharam Pal :** Will the Minister of State for Health be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under considration of the Government to repair the hospital building of Nilokheri alongwith its boundary wall ; and

(b) if so, the time by which the said repair works in the hospital building is likely to be completed ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डॉ०एम०एल०रंगा) :

(क) जी हां।

(ख) भवन की मरम्मत का कार्य जल्दी ही शुरु हो जाएगा।

Number of Murders/Dacoties/Kidnappings/Theft etc.

*400 **Shri Puran Singh Dabra**
Shri Karan Singh Dalal } : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of cases of murders, dacoities, kidnappings, theft etc. registered in the State during the calander year 1991-2000, separately ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरण

वर्ष 1991 से 2000 के दौरान हत्याओं डकैतियों, अपहरणों चोरी इत्यादि के पृथक-पृथक दर्ज कुल मामले

वर्ष	हत्या	डकैती	अपहरण/अपनयन	चोरी
1991	591	40	253	3656
1992	600	57	285	3894
1993	615	86	277	4051
1994	668	47	317	4165
1995	704	60	410	4710
1996	602	38	429	4856
1997	616	41	402	4856
1998	828	75	507	5984
1999	836	113	546	6619
2000	794	104	469	6400
योग	6854	661	3895	49191
कुल योग	60,601			

Post lying vacant in Medical College, Rohtak

* **522. Shri Shadi Lal Batra :** Will the Minister of State for Medical Education be pleased to state —

(a) the total number of sanctioned posts in Group A, B, C and D departmentwise in Medical College, Rohtak;

(b) total number of posts out of the post referred in para (a) above, lying vacant and since when, togetherwith the time by which these are likely to be filled up; and

(c) the details of the grant (plan and non-plan) given to the Medical College, Rohtak during the years 1998-99,1999-2000 and 2000-2001?

"Interim Reply"

Dr. M.L. Ranga

D.O. No. 53-M.H. 2001

Minister of State for Health, Medical Education & Ayurveda Departments, Haryana, Chandigarh.

Dated 12-3-2001

Subject : Starred Assembly Question No.522-Extention in time for furnishing reply.

Respected Shri Kadian Sahab,

Starred Assembly Queôtion No. 522 asked by Sh. Shadi Lal Batra, MLA is due for reply on the 13th of March, 2001. The question pertains to number of sanctioned posts in various categories department-wise and those lying vacant alongwith the date from which they have been lying vacant in PGIMS, Rohtak. Some time will be required to collect this information. It is, therefore, requested that an extention of 15 days may kindly be granted for furnishing reply to this question.

With regards,

Yours sincerely,
(Dr. M.L. Ranga)

Shri Satbir Singh Kadian,
Speaker,
Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh.

Procurement of Wheat and Paddy

***556 Diwan Pawan Kumar :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the quantity of wheat and paddy purchased through the different State Govt. agencies i.e. Hafed, Food and Supplies Deptt., FCI, Confed, Agro Industries Corporation and other Departments from 1991 to 2000; and

(b) the steps taken by the Government to purchase wheat in the coming Rabi season ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्रीमान् जी,

(क) विवरणी सदन के पटल पर रखी है।

(ख) आगामी रबी सीजन के दौरान गेहूं की खरीद के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध किए जा रहे हैं, इनमें बारदाना, पोलीथीन कवर, लकड़ी के चौखटे इत्यादि, भारतीय रिज़र्व बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट प्राप्त करना और गेहूं के भंडारण के लिए पल्लियों का निर्माण शामिल है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

विवरणी

राज्य की खरीद संस्थाओं ने वर्ष 1991 से 2000 तक गेहूं तथा धान की खरीद समर्थन मूल्य पर निम्न प्रकार से की है—

गेहूं (आंकड़े लाख टनों में)

वर्ष	खाद्य विभाग	हैफड	खाद्य निगम	एग्रो	वेयर हाऊस	कान्फेड	योग
1991-92	4.44	8.00	1.45	2.16	2.29	—	18.34
1992-93	3.34	5.36	1.62	1.44	1.30	0.64	13.70
1993-94	7.58	13.22	5.52	2.49	3.30	2.44	34.55
1994-95	6.58	11.70	4.31	2.47	3.02	2.41	30.49
1995-96	7.21	11.65	3.87	3.01	2.89	2.39	31.02
1996-97	4.24	7.74	2.67	2.14	1.96	1.47	20.22
1997-98	6.04	9.26	1.73	2.14	1.86	1.87	22.90
1998-99	7.08	11.67	4.73	2.40	3.10	2.60	31.58
1999-00	8.43	14.11	6.26	2.98	3.97	2.95	38.70
2000-01	10.18	19.19	4.12	3.91	3.89	3.68	44.97

धान (आंकड़े लाख टनों में)

वर्ष	खाद्य विभाग	हैफड	खाद्य निगम	एग्रो	वेयर हाउस	कान्फेड	योग
1991-92	—	—	0.51	—	—	—	0.51
1992-93	—	0.02	0.41	—	—	—	0.43
1993-94	—	0.08	0.81	—	—	—	0.89
1994-95	—	0.68	3.23	—	—	—	3.91
1995-96	—	0.48	2.07	—	—	—	2.55
1996-97	—	0.26	1.60	—	—	—	1.86
1997-98	0.22	0.26	0.84	0.11	0.11	0.07	1.61
1998-99	0.16	0.34	0.48	0.03	0.09	0.02	1.12
1999-00	0.68	1.32	0.82	0.15	0.27	0.19	3.43
2000-01	2.60	5.99	1.56	1.33	1.11	1.01	13.60

Upgradation of High School

***551. Shri Dina Ram :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the High School, Kailram into 10+2 school ; if so, the time by which it is likely to be upgraded ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी।

Shortage of Drinking Water

***331. Shri Ram Kishan Fauji :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Govt. is aware of the fact that there is an acute shortage of drinking water in District Bhiwani for the last one year ; and

(b) if so, the reasons thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) जी नहीं।

(ख) जिला भिवानी में, मुख्यत: पश्चिमी यमुना नहर तथा भाखड़ा मेन नहर प्रणाली से नहरी पानी कम मिलने के कारण पीने के पानी की कुछ कमी है। वास्तव में, जिला भिवानी में वर्ष 2000-2001 के दौरान नई योजनाओं को शुरू कर के तथा पहले से चल रही योजनाओं को पूरा कर के, जल वितरण में सुधार किया गया है।

Recovery of Outstanding Electricity Bills

***349. Shri Bhupinder Singh Hooda :** Will the Chief Minister be pleased to state the amount of outstanding electricity bills recovered from 1.1.2000 to 30.6.2000 and 1.7.2000 to 31.12.2000 separately ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : दिनांक 1-1-2000 से 30-6-2000 तथा दिनांक 1-7-2000 से 31-12-2000 तक वसूल की गई बकाया बिजली बिलों की राशि क्रमश: 210.00 करोड़ रुपए और 163.38 करोड़ रुपए थी।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Number of Escaped Undertrials

21. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state the number of undertrials/offenders/convicts escaped from jails in the State during the year 2000-2001 ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : 17 (हवालाती बंदी = 16, कैदी = 1, कुल = 17)

Upgradation of Schools

22. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Boys High School, Aherwan of Palwal Sub-Division to Senior Secondary School in near future ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह) : हां, श्रीमान् जी, जब बजट उपलब्ध हो जायेगा, स्कूल का स्तर बढ़ा दिया जाएगा।

Construction of Mini Secretariat at Faridabad

23. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a Mini Secretariat for the office of D.C. and other civil officers in the City of Faridabad in near future ; if so, the location thereof togetherwith the estimated expenditure to be incurred thereon ?

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : जी हां। लघु सचिवालय कम्पलैक्स का प्रशासकीय खण्ड वर्तमान लघु सचिवालय कम्पलैक्स में 12.50 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत से निर्मित किया जाना है।

Number of Vehicles provided to M.D.

24. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister for Co-operation be pleased to state the number of vehicles provided to M.D. Sugar Mills, Palwal for his official personal use, togetherwith the description and limit of Kms. prescribed for plying of such vehicle ?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भड़ाना) : श्रीमान जी, पलवल सहकारी चीनी मिल के प्रबन्ध निदेशक को मिल के कार्य हेतु एक अम्बैसडर कार नं० एच०आर०-जे०-0119 मुहैया कराई गई है। तथापि मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार प्रबन्ध निदेशक, चीनी मिल, पलवल अपने निजी कार्यों हेतु मिल के वाहन का 500 किलोमीटर प्रतिमास की सीमा तक नि:शुल्क प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं।

विशेषाधिकार के भंग का प्रश्न तथा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने रूल्ज आफ प्रोसिजर एण्ड कन्डैक्ट आफ बिजनैस इन दा हरियाणा लेजिस्लेटिव असैम्बली के रूल 279 के तहत ब्रीच आफ प्रिविलेज का नोटिस दिया था, उसके बारे में आपने क्या निर्णय लिया ?

श्री अध्यक्ष : अभी वह अन्डर कन्सीडेशन है और कॉमेंटस के लिए भेज दिया गया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक काल अटैंशन मोशन हरियाणा में लड़के और लड़कियों का जो गैप बढ़ रहा है उस बारे में दिया था उसका क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष : वह गवर्नमैंट को कॉमेंटस के लिए भेज दिया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कालिंग अटैंशन नोटिस दिया था कि फरीदाबाद की नहर में जो पानी आता है उसमें कारखानों का गन्दा पानी आता है जिसे पशु भी पीते हैं। वह पानी नीचे जल स्रोत के माध्यम से जमीन में भी जा रहा है। वहां पर पीलिया की बीमारी के काफी केसिज़ हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में आपने क्या निर्णय लिया ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। इसे भी गवर्नमैंट के पास कॉमेंटस के लिए भेज दिया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, मैंने तीन और कालिंग अटैंशन नोटिस दिए थे, उनके बारे में भी आप बता दीजिए कि उनका क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठ तो जायें, अभी मैं आपको बता देता हूँ। Calling Attention Notice regarding mixing of sewerage water with drinking water has been admitted for 15th March, 2001 and the other Calling Attention Notice regarding abnormal increase in house tax has been disallowed. (noise and interruptions)

कैप्टन अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक और कालिंग अटैंशन मोशन बिजली के बारे में भी दिया था, इसका क्या हुआ?

Mr. Speaker : Your Calling Attention Notice regarding increase in power tariff and inadequate supply of power has been disallowed. (Noise & interruptions) Please take your seats. Now, the Finance Minister will move a motion. (noise & interruptions) आप सभी लोग शान्तिपूर्वक बैठ जायें। अब वित्त मंत्री जी बोलेंगे।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्मत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैम्बर्ज़ बजट पर बोलने के लिए भी कालिंग अटैंशन मोशन के नोटिस देने लग गये। इसलिए हमने मैम्बर्ज़ की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि मैम्बर्ज़ को अधिक से अधिक बोलने का टाईम मिल सके और वे अच्छे सुझाव दे सकें तो अच्छी बात होगी। यदि मैम्बर्ज़ की तरफ से अच्छे सुझाव व सकारात्मक सुझाव आयेंगे तो सरकार उनको मानेगी भी बशर्ते वे स्टेट के हित में भी हों और जनता के हित में भी हों। हम मैम्बर्ज को बोलने की पूरी ऑफर दे रहे हैं। (शोर एवं विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आप अभी बैठें। (विघ्न)

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh * LIBRARY

14 मार्च, 2001 को दूसरी बैठक

वित्त मंत्री (प्रो० सम्मत सिंह) : स्पीकर सर, दलाल साहब की आदत बन गई है ये जब चाहते हैं तभी बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक प्रस्ताव हाउस के सामने रखा था कि 13 तारीख को सिंगल सिटिंग की बजाए डबल सिटिंग रख ली जाए। I want to move a motion to give more opportunities to the members of this house to speak in the public interest. हमारी राय है कि कल भी सिटिंग डबल कर ली जाए। बजट पर डिटेल के लिए एक सिटिंग की बजाए दो सिटिंग कर ली जाएं। (विघ्न) सिटिंग को बढ़ाने पर भी इनको ऐतराज हो रहा है (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।******

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी की कोई भी बात रिकार्ड न की जाए। (विघ्न)

प्रो० सम्मत सिंह : Speaker Sir, on persistent demand made by many members belonging to the various parties of the House to speak on the budget, I want to make a suggestion to have more sitting on 14th March, 2001. स्पीकर सर, मैं 14 तारीख को सैकिण्ड सिटिंग करने के लिए आपकी इजाजत से मोशन मूव करना चाहता हूँ ताकि बजट पर ज्यादा से ज्यादा मैम्बर्ज बोल सकें।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप मोशन मूव करें।

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move —

That the House on Wednesday the 14th March, 2001 shall have a second sitting and shall meet at 2.00 P.M. again and will adjourn at 6.30 P.M. without the question being put.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the House on Wednesday, the 14th March, 2001 shall have a second sitting and shall meet at 2.00 P.M. again and will adjourn at 6.30 P.M. without the question being put.

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सम्मत सिंह जी ने मोशन मूव किया है कि कल भी डबल सिटिंग की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मैम्बर्ज़ को बजट पर बोलने का मौका मिल सके। अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इनकी कोई ऐसी मन्शा तो नहीं कि कल ही हाउस खत्म करना चाहते हैं। (विघ्न) दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ, स्पीकर सर, इससे पहले भी आपने शायद आठ तारीख को डबल शिफ्ट की थी और उसके बाद भी 6.30 बजे तक दूसरी शिफ्ट थी। उसके बाद भी टाईम बढ़ाया गया था। डबल सिटिंग के बाद भी टाईम बढ़ाना ठीक नहीं लगता क्योंकि सवेरे 9.30 बजे से लेकर शाम साढ़े छः बजे तक बैठे-बैठे काफी थकावट भी हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, मैं भी तो बैठता हूँ और साथ ही मुख्य मंत्री जी और दूसरे सभी मंत्री और विधायकगण भी तो बैठते ही हैं। (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ता : मेरी सबमिशन यह है कि यह आपका और सरकार का अधिकार है कि जब तक चाहें सैशन को चलाएं चाहे सिंगल शिफ्ट करें या चाहे डबल सिटिंग कर दें लेकिन सैकिण्ड सिटिंग में 6-30 बजे के बाद समय एक्सटैंड करके रात तक न बिठाएं, हम कोई बंधुवा मजदूर तो नहीं हैं। (विघ्न एवं शोर)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, ये तो आपके आर्डर्ज़ की उल्लंघना कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं अभी लीडर ऑफ दी हाउस बोल रहे हैं । इनके बाद आपको बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं जो बोलने जा रहा हूं उसके बोलने के बाद सम्मानित सदस्य के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। जब ये पार्लियामैंटरी एफेयरज़ मिनिस्टर हुआ करते थे और हम अपोजिशन में हुआ करते थे तो जब भी हम कुछ बोलने के लिए खड़े हुआ करते थे तो इनको बहुत ही आपत्ति हुआ करती थी। अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रदेश इस बात के लिए आपकी सराहना करता है कि आपने खुले मन से सबको बोलने का समय दिया है। चौधरी भजन लाल जी चाहते थे कि 13-14 तक सिटिंग्स होनी चाहिए। गुप्ता जी सोचते हैं कि हम भागना चाहते हैं। मैं इनको यह कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है अगर आप चाहते हैं तो सैशन को 16 तारीख तक बढ़ा लेते हैं। अगर और समय बढ़ाना चाहते होंगे तो वह भी बढ़ा देंगे। सम्मत सिंह जी इस बारे में कल

मोशन मूव कर देंगे, 15 को भी मूव कर देंगे अगर उसके बाद भी आप 19 या 20 तारीख तक का समय बढ़वाना चाहेंगे तो फिर से मोशन मूव कर देंगे। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी कर्ण सिंह दलाल जी को भी बोलने का मौका देना चाहिए वे भी एक पार्टी के लीडर हैं, उनकी नैशनल पार्टी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उनको भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। जहां तक टाईम का सवाल है तो इस बात से हम भी सहमत हैं और इसमें किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए। इस वजह से ज्यादा लोगों को ज्यादा बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि 16 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख तक बढ़ा लेते हैं तो इसमें इनकी चालाकी है। जब हमने इनको कहा था कि समय बढ़ाना चाहिए तब तो हमारी बात नहीं मानी लेकिन आज राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर सब बोल चुके हैं उस पर थैंक्स हो चुका है और ज्यादा से ज्यादा लोग बोल चुके हैं तो अब ये समय बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये जो रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है वे ** हैं।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी ने जो ********** शब्द कहे हैं इनको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो डबल सीटिंग कर रहे हैं यह ठीक बात है लेकिन सैशन 6.30 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए उसका समय आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, कल की सीटिंग को जो डबल करने के लिए कहा गया है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी कहा है कि अगर और समय बढ़ाना चाहेंगे तो और समय भी बढ़ा दिया जाएगा। उसके लिए मेरा अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन आ रहा है और उसके कारण इनको भी दिक्कत महसूस हो रही है आप इनके अधिवेशन के बाद 1-2 दिन का समय बढ़ा दें। इससे इन लोगों को भी बोलने का मौका मिल जाएगा और सरकार की स्थिति का भी पता चल जाएगा कि ये कितना समय सदस्यों को बोलने के लिए देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब आप बैठें। सदन किसी पार्टी विशेष के अधिवेशन और दूसरे कार्यक्रमों का ध्यान नहीं रखता। सैशन भी चलता रह सकता है और किसी पार्टी का अधिवेशन भी चलता रह सकता है। यह सदन किसी पार्टी विशेष का सदन नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, अभी विपक्ष के नेता ने भी कहा कि डबल सीटिंग करने को वे एप्रीशिएट करते हैं मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन दलाल साहब कहते हैं कि डबल सीटिंग नहीं होनी चाहिए। ये इकलौती पार्टी के इकलौते दलाल हैं या लाल हैं। स्पीकर सर, जब बी०ए०सी० की मीटिंग थी तो उसमें ये सारी बातें तय हो गई थीं। उस दिन सात और आठ तारीख को डबल सीटिंग की बात भी हो गई थी। उसके बाद जो टेंटेटिव प्रोग्राम रखा गया था उसमें भी 16 तारीख शामिल थी। स्पीकर सर, उस समय विपक्ष के नेता के सुझाव पर 16 तारीख का सैशन न करके सात और आठ तारीख को डबल सीटिंग रखने को मान लिया गया था। इसी तरह फिर इन्होंने सुझाव दिया था कि तेरह और चौदह तारीख की डबल सीटिंग की जाए। स्पीकर सर, जब बी०ए०सी० की रिपोर्ट पर डिसकशन हो रही थी उस समय यह नहीं सोचा गया था कि समय को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी।

---

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

[प्रो० सम्पत सिंह]

उस समय यही सोचा गया था कि अगर समय को बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो बढ़ा लिया जाएगा। अब समय को बढ़ाने की जरूरत समझी गई क्यों कि बहुत से मैम्बर्ज बजट पर बोलना चाहते हैं सरकार भी इनके सुझावों को इन्वाइट करके मानना चाहती है। इसलिये हाऊस की इजाजत से कल की सीटिंग डबल की जा रही है। विपक्ष के नेता हमारे एम०एल०एज० के बारे में कटाक्ष कर गये और वे उनके बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल कर गए जैसे वे अपने समय में उनके बारे में करते थे। उन्होंने कहा कि एम०एल०एज० ये हैं वे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के लोगों के विचार सामने आएं। इन्होंने कहा कि ट्रैजरी बैंचिज के लोगों को ये बोलने नहीं देते हैं लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि ट्रैजरी बैंचिज के लोगों की सहमति से ही ये सारे का सारा काम होता है इसलिए इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तक अगर दिक्कत होती थी तो यह कि विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। स्पीकर सर, सरकार हाऊस में ही नहीं विपक्ष के लोगों की बात सुनने को तैयार है बल्कि सदन से बाहर भी वे किसी भी विभाग से संबंधित, किसी भी मंत्री से संबंधित मुख्यमंत्री जी को अपनी समस्याओं के बारे में लिखकर दे सकते हैं। सरकार उनकी शिकायतों पर गौर करेगी। जब सरकार बोलने के लिए इनको समय दे रही है तो भी इनकी दिक्कत हो रही है। स्पीकर सर, जब से ये असैम्बली बनी है तब से यह कभी नहीं कहा गया होगा कि विपक्ष के लोग ज्यादा से ज्यादा बोलें। अब तक तो यही होता था कि ट्रैजरी बैंचिज के लोग ही ज्यादा बोलते थे और विपक्ष के लोगों को कम समय बोलने के लिए दिया जाता था। अब तो यह हमारी सरकार द्वारा हैल्दी ट्रैडीशन डाली गई है और इनको ज्यादा समय बोलने के लिए दिया जा रहा है। अब जैसा मांगे राम जी और दूसरे साथियों ने कहा कि हम थक जाते हैं या हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप हमारे तो बंधुआ नहीं हो लेकिन पब्लिक के आप जरूर बंधुआ हो क्योंकि उनसे आप मेंडेट लेकर आए हैं। इसलिए उनके प्रति तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उनकी बातों को यहां पर बताया जाए। अगर पब्लिक इंट्रस्ट में आपको रात के बारह बजे तक भी बैठना पड़े तो बैठना चाहिए। चुनावों के दौरान भी तो आप लोग रात के समय में उनसे वोट लेने के लिए जाते हैं। अक्सर ट्रैजरी बैंचिज यह कोशिश करती है कि सैशन जल्दी खत्म हो लेकिन यहां पर आज यह हालात हैं कि अपोजिशन सैशन जल्दी खत्म करना चाहता है और ट्रैजरी बैंचिज सैशन बढ़ाना चाहती है। विपक्ष के नेता ने हमारी बात को एग्री किया इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं लेकिन अगर दलाल साहब होते तो दो सीटिंग्स भी नहीं होती।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि लीडर ऑफ दी हाऊस ने कहा कि अगर डबल सीटिंग को हम नहीं मानते हैं तो सैशन आगे तक बढ़ाया जा सकता है। हम इनके सुझाव को मानते हैं कि बजाए डबल सीटिंग के 19, 20, 21 तारीख को भी सैशन बुला लिया जाना चाहिए। सरकार तीन दिन और सैशन बुला लें और डबल सीटिंग न करें।

प्रो० सम्पत सिंह : चाहें तो डबल सीटिंग भी रखें।

चौधरी भजन लाल : हम चाहते हैं 19, 20, 21 तीन दिन तक सैशन का समय बढ़ा दीजिए।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई नैशनल डे है तो बात अलग है पार्टी विशेष के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है।

Mr. Speaker : Quetion is —

That the House on Wednesday, the14th March, 2001 shall have a second sitting and shall meet at 2.00 P.M. again and will adjourn at 6.30 P.M. without the question being put.

The motion was carried.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बेरी कस्बे की सफाई की समस्या संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a calling attention notice from Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A. regarding problem of cleanliness of Town Beri. I admit it. Dr. Raghubir Singh Kadian may read his notice.

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, रूलज के मुताबिक मेरा पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देने का हक है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब आप बैठिए। Dr. Raghubir Singh Kadian may read his notice.

Dr. Raghubir Singh Kadian : Sir I want to draw the attention of this August House towards a matter of urgent public importance that the inhabitants of Town Beri have shown thier great resentment as they are facing big problem of the cleanliness of the town because in this town of 25000 population, no Municipal Committee/Panchayat is functioning for the last one year. If above problem is not sorted out timely and properly there is apprehension that some mishappening/ spreading of any diseases may cause danger to many human lifes.

Therefore, I request the Goverment to take immidiate steps in this regard and make a statement on the floor of the House.

वक्तव्य—

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी मुख्य संसदीय सचिव द्वारा

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : हरियाणा राज्य में मार्च 2000 में 29 नगरपालिकाओं, जिनमें नगरपालिका बेरी भी शामिल थी, के भंग होने पर सरकार ने उनके स्थान पर मई 2000 में 36 ग्राम पंचायतें गठित की थीं। भंग नगरपालिका बेरी के स्थान पर दो ग्राम पंचायतें, बेरी खास व बेरी दोपाना के नाम से स्थापित की गई हैं। इन ग्राम पंचायतों में अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं जिसके लिए सरकार ने राज्य चुनाव आयोग से शीघ्र चुनाव करवाने का अनुरोध किया हुआ है।

जब तक इन दो ग्राम पंचायतों के चुनाव सम्पन्न नहीं करवाए जाते, सफाई व्यवस्था तथा गांववासियों को अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी, बेरी को प्रशासक नियुक्ति किया हुआ है। उक्त दोनों ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था जारी रखने के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत में छः सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं जो कि प्रतिदिन गांव में गलियों, नालियों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई का कार्य कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के प्रशासक अर्थात् खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पड़ी कुरड़ियों को उठवा दिया गया है ताकि ग्राम सभा क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रखी जा सके। सिविल सर्जन, झज्जर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सभा क्षेत्र में पानी से होने वाली अथवा अन्य संक्रामक बीमारी का कोई

[श्री राम पाल माजरा]

प्रकोप इस समय नहीं है। पीने के पानी के कुओं में सप्ताह में दो बार नियमित रूप से क्लोरिनेशन किया जा रहा है। गन्दी गली-सड़ी सब्जी/फल बेचने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। घर-घर जाकर हैलोजन की गोलियां बांटी जाती हैं ताकि बीमारियों से बचा जा सके। इसी प्रकार उपनिदेशक, पशुपालन विभाग झज्जर की रिपोर्ट अनुसार पशुओं में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं फैली है और संक्रामक बीमारीयों से बचाने के लिए टीके (वैक्सीनेशन) लगाए गए हैं।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपल कमेटी, बेरी जो है वह सन् 1878 में बनी थी और आजादी से पहले मेरे हिसाब से जो बेरी टाऊन है उसकी बहुत बड़ी अहमियत थी, वहां बहुत बड़ा बाजार था। इसमें माता भीमेश्वरी देवी जी का बहुत बड़ा मंदिर है।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप क्वेशचन पूछें। आप तो ब्रीफ हिस्ट्री बता रहे हैं।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : उस मंदिर में हर छः महीने में 3-4 लाख श्रद्धालु वहां आते हैं और मेला लगता है। इस नगर पालिका में 44 गांव के लोग आते हैं। इसे तहसील का दर्जा दिया हुआ है। यहां दो सीनीयर सैकण्डरी स्कूल हैं, दो प्राइमरी स्कूल हैं, 11 प्राइवेट स्कूल हैं और जी०वी०आई० और आर०जी०बी०आई की शिक्षा संस्थाएं चल रही हैं, पांच नर्सिंग होम चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी जो तकलीफ है वह सरकार से पूछें।

श्री धीरपाल सिंह : आपको दो प्रश्न पूछने का अधिकार है।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। काल अटैंशन मोशन में बैकग्राउंड तो बताई ही जाती है। स्पीकर सर, मैं अर्ज कर रहा था कि इसमें 16 धर्मशालाएं, 84 मंदिर हैं, बहुत बड़ा बाजार है, काठ मण्डी, सब्जी मण्डी, गऊशाला आदि हैं। हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल जी भी इसी हल्के से रहे हैं और इस समय तीन विधायक उस हल्के के इस सदन में हाजिर हैं।

श्री अध्यक्ष : पंडित जी के नाम से रोहतक मैडिकल कॉलेज है।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : बेरी बाजार की गलियां सड़ रही हैं वहां कीचड़ भरा पड़ा है।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब आप सवाल पूछें। आप तो वहां का इतिहास बताने लग गए।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, बेरी की म्यूनिसिपल कमेटी घाटे में नहीं चल रही थी बल्कि राजनीतिक भेदभाव के चलते इस म्यूनिसिपल कमेटी को तोड़ा गया है। इस कमेटी का 1998-99 में कुल एक्सपेंडीचर 13 लाख रुपये था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी आप बैठिए, अब पार्लियामेंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर जवाब देंगे।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने अपने कालिंग अटेंशन मोशन में यह कहीं नहीं पूछा कि बेरी म्यूनिसिपल कमेटी को क्यों तोड़ा गया है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि बेरी में दो पंचायतें बन गई हैं और उन पंचायतों के चुनाव होने हैं। सरकार ने चुनाव आयोग को इस बारे में लिख दिया है। माननीय सदस्य ने बेरी म्यूनिसिपल कमेटी को तोड़ने के बारे में लोगों की रिजेंटमेंट के बारे में कहीं पर भी अपने कालिंग अटेंशन मोशन में जिक्र नहीं किया। आप इस बारे में डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं और वहां की हिस्ट्री बताने में लगे हुए हैं।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी को पता होना चाहिए कि कालिंग अटेंशन मोशन में एक प्वाईंट ही दिया जा सकता है दो-तीन प्वाईंट नहीं दिए जा सकते। स्पीकर सर, मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार जनहित को मद्देनजर रखते हुए बेरी म्यूनिसिपल कमेटी को दोबारा रिवाइव करने के लिए कोई स्कीम रखती है।

मुख्य मंत्री (श्री ओ३म प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय सदस्य का यह प्रश्न नहीं बनता है लेकिन इनकी जानकारी के लिए और पूरे सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इस बारे में मैंने सदन में एक दिन पहले भी कहा था कि प्रदेश में 29 म्यूनिसिपल कमेटियों को तोड़ने का निर्णय जनसंख्या के आधार पर लिया गया था। मैंने पहले भी कहा था और अब पुनः दोहरा रहा हूं कि जनगणना का कार्य पूरा होने के बाद अगर वहां की जनसंख्या बढ़ती है तो जो निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा उस निर्णय से इस सदन को पूरी तरह अवगत करवा दिया जाएगा।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, बेरी हल्के में माता भीमेश्वरी देवी जी के मेले के समय 6 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई थी। मेले के बाद वहां पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। सारा बेरी हल्का सड़ रहा है । वहां पर किसी प्रकार की हैल्थ हजार्ड हो सकती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाये हैं।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने बेरी में मेले लगने के बारे में प्रश्न पूछा था जब मेला लगता है तो डी०सी०, एस०डी०एम० द्वारा अलग-अलग इंतजाम किए जाते हैं। जहां तक म्यूनिसिपल कमेटियों के इलैक्शंज़ की बात है। इसके बारे में माननीय सदस्य कादियान साहब ने हाईकोर्ट में एक रिट दायर की थी। अध्यक्ष महोदय, ये साथी चाहे सफाई को गहराई से लें न लें लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय ने महत्मा गांधी के जन्म दिवस पर पूरे प्रदेश के काबिल वजीरों को साथ लेकर, उनकी ड्यूटी लगाकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम द्वारा सिरसा से शुरू किया था। फतेहाबाद और हिसार मुख्य मंत्री महोदय स्वयं गए थे उन्होंने काबिल वजीरों की अलग-अलग ड्यूटी लगाकर पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान को पूरे सप्ताह तक चलाया था। यह दूसरी बात है कि कादियान साहब इसमें आपकी तरफ के लोगों के गल्ले साफ हो गए थे। इस सरकार ने स्वच्छता और सफाई को अहम स्थान दिया है। बेरी में न ही कोई बीमारी है और न ही कोई गंदगी है। अगर वहां कोई बीमारी या गंदगी होगी भी तो हमारी सरकार इस बारे में पूरी तरह से सतर्क है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ये पांच आदमियों की एक कमेटी बना लें और जांच करवा लें अगर बेरी में गंदगी हुई तो ये रिजाइन कर दें और अगर वहां सफाई हुई तो मैं रिजाइन कर दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

पशुपालन राज्य मंत्री (चौ० मो० इलियास) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे माननीय साथी रघुबीर सिंह कादियान जी, जो बेरी हल्के का नेतृत्व कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सही मायने में ये अपने हल्के से परिचित नहीं हैं क्योंकि बार-2 यह पूछा गया है कि बेरी में किस-2 चीज का मेला लगता है। माननीय सदस्य ने सिर्फ कहा है कि बेरी में माता का मेला लगता है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं और कादियान जी भी इसको बतायेंगे जबकि इन्होंने जानबूझ कर इसे छुपा

[चौ० मो० इलियास]

लिया है लेकिन मैं तो बताऊंगा ही कि बेरी में गधों का भी मेला लगता है। (शोर एवं व्यवधान) मुझे लगता है कि इनको अपने हल्के की पूरी जानकारी नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वहां पर सारे गधे बाहर के ही होते हैं बेरी के नहीं होते। (शोर)

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, माननीय पशुपालन मंत्री महोदय जी ने कहा है कि मुझे बेरी हल्के के बारे में पता नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री जी को हमारे हल्के की चिन्ता है, यह बहुत अच्छी बात है। बेरी में माता भीमेश्वरी देवी का मेला लगता है। इस मेले के साथ साथ एक मेला और लगता है और अगर मैं उसका नाम लेता तो लोग उठकर चले जाते। वहां गधों का मेला भी लगता है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपका निकास बेरी से है, मैं आपको बता दूं कि वहां गधों का मेला इसलिए आरगेनाइज होता है, शायद किसी को हिस्ट्री का न पता हो तो मैं बता दूं। अध्यक्ष महोदय, चारों तरफ से और आपकी तरफ से भी वहां गधे आते हैं और खच्चर भी आते हैं, जिनको म्यूल्ज भी बोलते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रघुबीर जी, मेला गधों का लगेगा तो गंदगी तो फैलेगी ही।

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, वहां पर केवल बेरी हल्के के गधे नहीं होते। वहां पर पूरे देश प्रदेश के गधे आते हैं और उनकी खुली बोली लगती है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पशु पालन मंत्री इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने अपने दायित्व का पूरे ढंग से निर्वहन किया है। जबकि यह जिम्मेवारी रघुबीर सिंह कादयान जी की थी। कादयान जी ने जब मेले का जिक्र किया तो जिस किस्म का भी मेला होता है उसके बारे में भी बताना चाहिये था, संकोच नहीं करना था। इन्होंने बताया भी लेकिन पशु पालन मंत्री जी के मजबूर करने पर कि किस तरह का मेला लगता है। इसलिए कादयान जी को पशुपालन मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

तथाकथित विशेषाधिकार भंग की सूचना/उस पर निर्णय

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे रूलिंग चाहूंगा कि क्या जीरो ऑवर में प्वाइंट ऑफ आर्डर होता है?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि प्रश्न काल के दौरान प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं होता, जीरो ऑवर में होता है। ये बहुत पुराने मैम्बर इस सदन के हैं इन्हें इस बात का पता होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आपको एक प्रिविलेज मोशन दिया था और आपने कहा है कि ये मोशन एग्जामिन हो रहा है। उसका फैसला आपने लेना है। पहले आप मेहरबानी करके उसके बारे में डिसीजन दें ताकि बजट पर बहस हो सके।

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब तक प्रिविलेज मोशन का डिसीजन नहीं होगा तब तक बजट पर बहस नहीं होगी।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of breach of

privilege from Shri Bhajan Lal, Shri Bhupinder Singh Hooda, Capt. Ajay Singh Yadav and Shri Raghubir Singh Kadian, regarding the leakage of Budget. Although the notice has been addressed to me, which, according to the Rule 279 of the Rules of Procedure and Conduct of Buisness in the Haryana Legislative Assembly, is required to be addressed to the Secretary Haryana Legislative Assembly. But without going into the technical defects, I have considered this notice. This matter has been raised yesterday, i.e. on 12-3-2001 by various members of the Oposition Benches in the House and the matter was settled there. However, after through considration and after going through the relevant rules, practice and procedure, I withhold my consent to raise this matter on the floor of the House as the matter is not of breach of privilege and there is no leakage of Budget at all.

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * *।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, जो कुछ भी कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। कैप्टन साहब, जब लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने इस रूलिंग को कबूल कर लिया है तो आप क्यों खड़े हो रहे हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये अपने लीडर को लीडर नहीं मानते इसीलिए उनके मानने के बाद भी ये बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग आ गई उसे विपक्ष के नेता ने भी मान लिया है। जब विपक्ष के नेता ने आपकी रूलिंग को मान लिया है तो उसके बाद कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होना चाहिए। (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने नहीं माना है। मैं तो कह रहा हूं कि यह गलत है। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, भजन लाल जी ने ही कहा है कि इन्होंने आपका निर्णय मान लिया है। (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जब पन्द्रह मैम्बर्ज खड़े हो जाएं तो मोशन मूव हो सकती है। (शोर)

कैप्टन अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, सैक्शन-278 में लिखा हुआ है ****** (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, 278 में कोई चीज अनिवार्य नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ********** ।

श्री अध्यक्ष : कप्तान साहब, आप बैठिए। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। (शोर)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, कोई मोशन मूव नहीं हुआ है। आपकी रूलिंग को विपक्ष के नेता ने मान लिया है उसके बाद मोशन मूव करने का कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी की पार्टी के सदस्य इनकी बात नहीं मान रहे हैं और बार-बार खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के नेता अपने सदस्यों पर कन्ट्रोल तो कराएं। (शोर)

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने आपकी रूलिंग मांगी है आपने रूलिंग दी भी है और इन्होंने उस रूलिंग को माना है। कोई मोशन मूव नहीं हुआ। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेहरबानी करके मैम्बरों की बात सुनें तो सही हमने आपकी रूलिंग सुन ली है लेकिन आप इनकी बात तो सुनें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, अभी आप सब बैठिए। आपको बजट पर बोलने का समय मिलेगा। उस वक्त आप बोल लेना। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मोशन पर डिस्कशन तभी होती है जब उसे आप अलाउ कर देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष के नेता ने आपकी रूलिंग को मान लिया है। जब ये विपक्ष के नेता होने के रूप में आपकी बात मानते हैं तो पता नहीं इनकी पार्टी के लोगों को क्या तकलीफ है, वे इनकी नहीं मानते हैं। जहां तक विपक्ष के नेता उठकर गला दबाने की बात कह रहे हैं तो गला तो इनकी पार्टी के सदस्य ही इनका दबा रहे हैं। (शोर) ये लोग इनका गला पीछे से दबा रहे हैं। इसलिए ये भी खड़ा होने पर मजबूर हो गए। जब ये लोग आपको अपना नेता नहीं मानते हैं तो फिर हम क्या करें। (शोर) हर पार्टी का एक नेता होता है। (शोर) कोई भी इस सदन का नेता हो,चाहे विपक्ष का नेता हो या फिर किसी और पार्टी का नेता हो वह अगर खड़ा होकर कोई बात मान लेता है तो फिर उस पर डिस्कशन नहीं होती। जैसा कि आपकी रूलिंग आई जिसे विपक्ष के नेता ने मान लिया है इसलिए इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं होती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई मैनडेटरी नहीं है। No motion has been moved. आप बैठ जाएं।

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, आप रूल तो देखें।

श्री अध्यक्ष : सारे रूल्ज देखकर ही मैंने अपनी रूलिंग दी है। (शोर)

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। (शोर) आप हमारी बात तो सुनें। (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य कुछ कहना चहते हैं इसलिए आप उनकी बात सुनें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : मैं इस बारे में अपनी रूलिंग दे चुका हूं इसलिए आप सभी बैठ जएं। (शोर)

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। कृपा करके आप मेरी बात सुनने का कष्ट करें। स्पीकर साहब जहां तक क्वैश्चन ऑफ बीच ऑफ प्रिविलेज का सवाल है वह हमने रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनैस इन दी हरियाणा लैजिस्लेटिव

असैम्बली के रूल 281 को तहत आपके दफ्तर में दाखिल किया है और रूल 281 के तहत आपको अपनी रूलिंग देने के पूरे अधिकार हैं कि आपको यह मंजूर नहीं है। आपने अपनी रूलिंग दे दी लेकिन रूलिंग देने के बाद प्रिविलेज मोशन पर जिन जिन माननीय सदस्यों के सिगनेचर हैं उनको ऑब्जैक्शन रेज करने का पूरा हक है। मैं उन प्रिविलेज का नोटिस देने वाले सदस्यों में से हूं तो मेरा हक है इसलिए मुझे अपना ऑब्जैक्शन रेज करना है इसलिए मैं यह पढ़ना चाहता हूं। मैं रूल 281(2) पढ़कर सुनाता हूं जो इस प्रकार है :—

'If objection to leave being granted is taken,.....(Interruptions)

श्री अध्यक्ष : वह जब है यदि स्पीकर अपनी कन्सैंट दे चुका हो। मेरी तरफ से कन्सैंट नहीं दी गई तो आगे उस पर डिस्कशन करने का क्वैश्चन ही पैदा नहीं होता। पहले आप रूल 278 पढ़ें उसमें लिखा है :—

"A member may, with the concent of the Speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member of the House or of a Committee thereof."

I have not given my consent. (interruptions)

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, मैं रूल 281 (2) कोट कर रहा हूं और आप दूसरा रूल कोट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पहले रूल 278 आएगा उसके बाद दूसरा आएगा। आप रूल्ज की सीक्वेंस देखें। पहले आप रूल 278 पढ़ें।

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, आप कष्ट करके रूल 281 (2) पढ़ें।

श्री अध्यक्ष : जब वह बात रूल 278 पर ही फिनिश हो गई तो आगे किसी और रूल को पढ़ने की आवश्यक्ता ही नहीं है।

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, रूल 281 (2) के तहत ऑब्जैक्शन रेज करने का जो तरीका है उसके तहत अगर प्रिविलेज मोशन का नोटिस देने वाला मैम्बर ऑब्जैक्शन करना चहता है तो उसको लाजमी तौर पर मानना पड़ेगा। Because word " shall" is clearly written in the Rule instead of word "would". So, it is mandatory to grant the leave. (Interruptions)

Mr. Speaker : No, it is wrong interpretation of the Rule.

Rao Inderjit Singh : Sir, please give me time to read the Rule 281 (2) which says:

"(2) If objection to leave being granted is taken, the Speaker shall request those members, who are in favour of leave being granted to rise in their places and if not less than fifteen members rise accordingly, the speaker shall intimate that leave is granted. If less than fifteen members rise, the Speaker shall inform the member that he has not the leave of the House."

It all depends upon the members who rise or not. But here fifteen members in their seats.

Mr Speaker : But the consent has not been given.

Rao Inderjit Singh : But you have to give the consent.

Mr. Speaker : No, It is not mandatory. This question arises, if I gave the consent. But when I have not given my consent, the question dose not arise to further discuss this matter. (Interruptions) Please listen to me . I am reading out from Chapter XXIX ''Procedure in Financial Matters'' from the book ''Practice and Procedure of Parliament, Lok Sabha Secretariat'' by Kaul & Sakdher abuot the leakage of Budget. At page 631 it is mentioned —

''Quetion of Privilege.

Leakage of Budget proposals before they are presented to Lok Sabha dose not constitute a breach of privilege of the House.''

So, it makes clear that there is no leakage of Budget proposals. So, I have already ruled out it. Once the Speaker has given his ruling about it, then the question of breach of privilege dosn't arise again. (Interrutions)

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, मेरे पास भी हरियाणा विधान सभा की रूल्ज ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनैस इन हरियाणा लैजिस्लेटिव असैंबली की किताब है उसमें मैंने जो रूल कोट किया वही लिखा है।

Mr. Speaker : Please don't misinterpret the rules.

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमारा यहां हाऊस में बैठने का क्या फायदा है ? (शोर)

वाक आऊट

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनको स्टेज पर बोलने के लिए कहें तो ये वहां से भाग जाते हैं। (शोर एवं विघ्न) कभी ये खूंखार रैली करते हैं तो कभी मारा-मार रैली करते हैं। (शोर एवं विघ्न) यहां पर बैठकर तो ये कोई बात कर नहीं सकते। स्पीकर साहब, इन्होंने जाना है। (शोर एवं विघ्न) मतलब की जब भी कोई बात की जानी होती है तो ये चले जाते हैं।

चौधरी भजन लाल : हम जा तो रहे हैं, लेकिन वापस आएंगे। अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रहे इसलिए हम ऐज ऐ प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं। (इस समय उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण सदन से वाक-आउट करके चले गए। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : आप पहले मेरी बात तो सुनें। (विघ्न) यदि आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते तो मैं भी ऐज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करता हूं।

(इस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया के एक सदस्य, श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक आउट करके चले गए।)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय,ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ये विपक्ष के भाई यहां पर ड्रामा कर रहे हैं। यहां बजट पर तो इनके पास बोलने के लिए कुछ है

नहीं। अखबारों में अपना नाम छपवाने के लिए वाक आउट करके चले गए हैं।

सदन की मेज पर रखे गए कागज़-पत्र

Mr. Speaker : Now a minister will lay the papers.

Finace Minister (Prof.Sampat Singh) : Sir, I beg to lay on the table

1. The report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2000 No. 2 (Civil) of the Government of Harayana in pursuance of the provisions of clause (2) of Artical 151 of the Constitution of India.
2. The report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2000 No. 1 (Revenue Receipts) of the Government of Harayana in pursuance of the provision clause (2) of Artical 151 of the Constitution of India.

वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the general discussion on the Budget for the year 2001-2002 will take place. Sh. Jasbir Singh mallour may speak.

श्री जसबीर सिंह मलौर (नग्गल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने कल सदन में पेश किया है उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस बजट से प्रदेश में एक खुशी की लहर दौड़ी है क्यों कि यह कर रहित बजट है। इसमें हरियाणा प्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया है। इसीलिए इसको सभी ने सराहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्रामीण विकास का जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने के लिए व हमारे आज के जननायक चौधरी देवीलाल जी के सपनों को पूरा करने के लिए पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं। वह काम हमारी सरकार ने करके दिखाया है। हमारी सरकार ने पंचायती संस्थाओं को वित्तीय अधिकार दिए हैं ताकि ग्रामीण विकास के कार्य अधिक से अधिक हो सकें। पहले जो पंचायत 25000 रुपये तक का काम करवा पाती थी अब वे 1 लाख 25 हजार रुपये तक का अपना काम करवा सकती है। जो पंचायती राज संस्था पहले 1 लाख रुपये तक के काम करवा सकती थी अब वह 3 लाख रुपये खर्च करके अपना काम करवा सकती है। इसी प्रकार से जिला परिषद को भी 5 लाख रुपये तक का खर्च करने का अधिकार दिया गया है। हमारे मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक बहुत बढ़िया काम ''सरकार आपके द्वार'' का जो कार्यक्रम चलाया है वह बहुत ही अच्छा रहा है। इससे विकास के कामों में भी तेजी आई है। और पंचायतों को और अधिक अधिकार दिए हैं ताकि कम पैसों में अधिक विकास कार्य हो सकें।

अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की है कि जो खिलाड़ी इन्टरनैशनल लैवल पर गोल्ड मैडल लेकर आएगा उसको एक करोड़ रुपये, जो सिल्वर मैडल लेकर आएगा उसको 50 लाख रुपये और जो कांस्य पदक लाएगा उसको 25 लाख रुपये की राशि इनाम के तौर पर सरकार उस खिलाड़ी को देगी। ऐसी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए की है। जिससे हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों का मनोबल ऊँचा हुआ है। उसके परिणामस्वरूप यमुनानगर निवासी कर्णम मल्लेश्वरी को सरकार ने 25 लाख रुपये का पुरस्कार देकर

[श्री जसबीर सिंह मलौर]

सम्मानित किया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी ने हरियाणा प्रदेश का नाम सारे संसार में ऊँचा किया। अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव और अम्बाला में हॉकी के लिए आधुनिक एस्ट्रोटर्फ चार करोड़ रुपये की लागत से बनवाने का जो फैसला हमारी सरकार ने किया है उस पर जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके अथक प्रयासों के कारण प्रदेश में 1100 पुरानी बसों को बदलने की योजना तैयार की गई है और अब तक 450 बसें खरीदी जा चुकी हैं जो कि सड़कों पर आ चुकी हैं जिससे हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए परिवहन की सहूलियत मिली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि ''सरकार आपके द्वार'' प्रोग्राम के तहत जो नग्गल विधान सभा क्षेत्र में पिछले दिनों जो खुला दरबार लगाया था तो वहां पर विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने विकास के कामों के लिए पैसा देने का काम किया। मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से 27 सड़कों के निर्माण के लिए 4 करोड़ 64 लाख रुपये मेरे हल्के में आये हैं तथा विकास कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है। खुले दरबार लगाकर गांवों के जो सामूहिक कार्य थे, चाहे वह रिटेनिंग वाल की बात हो चाहे हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लिए चौपाल बनाने की बात हो, शमशान घाट का रास्ता हो, शैड बनाने की बात हो, गांव की फिरनी में पानी की निकासी के लिए पक्के नाले बनाने की बात हो स्कूलों के नये कमरे बनाने की बात हो या हर गांव में वृद्ध आश्रम बनाने की बात हो, चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी ने जो घोषणा की है उससे हरेक को बड़ा आराम मिलेगा। मेरे हल्के के लगभग 25 प्रतिशत काम पूरे हो चुके हैं और नई सड़कों का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि मेरा विधानसभा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 20 सालों से जिस किसी को नग्गल हल्के का प्रतिनिधित्व मिलता रहा है वह विकास की जगह विनाश कार्यों में लगा रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे हल्के की काफी समस्याएं हैं जो कि चैंडिग रहती हैं। पी.डब्ल्यू.डी. की जो रोड्ज हैं उनकी हालत बड़ी खस्ता है मैं उनके बारे में थोड़ा विवरण यहां पर देना चाहूंगा। जैसे अम्बाला-जगाधरी रोड से पिलखनी, अम्बाला जगाधरी रोड से साहपुर, अम्बाला-जगाधरी रोड से ब्राह्मण माजरा, अम्बाला-हिसार रोड से डेलू माजरा वाया मल्लौर, इस्माइलाबाद से जझेरी, बारा से शाहपुर, अम्बाला-हिसार रोड से मोहड़ी वाया जलबेड़ा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जो जलबेड़ा रोड है वहां राधा स्वामी सत्संग घर है और साथ ही बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा लखनौर साहब भी पड़ता है जहां पर गुरु गोबिन्द सिंह जी के नानके और मामे वगैरह रहते थे। वहीं पर उन्होंने अपना बचपन बिताया था वहां पर गुरुद्वारों में बड़ा रश रहता है। अम्बाला-हिसार रोड पर जलबेड़े तक 12 फुट से बढ़ाकर 18 फुट तक रोड की जाए और एक अन्य सड़क महेश नगर से बबियाल है। बबियाल गांव में 10 हजार के लगभग वोट हैं और बड़ी भारी आबादी है। महेश नगर शहर में होने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। इस रोड की हालत बहुत ही खस्ता हुई पड़ी है मोहड़ी से दलाना, नन्योला से सराला पंजाब बार्डर तक, नयोला से गुड़ मण्डी पंजाब बार्डर तक, मोहड़ा से बड़ोली, जनसूई हैड से निहारसी, बलाना से दुरला, बलाना से खालदी, बकनौर से निहारसा, बकनौर से महमूदपुर तक सड़क बननी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के कई गांव ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं उन गावों की पंचायत एक है और उनको वहां आना-जाना पड़ता है उनकी सोसाइटी है और स्कूल के बच्चों को भी पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। बरसात के दिनों में बीस-बीस किलोमीटर का

चक्कर काट कर उन गावों के लोगों को आना पड़ता है और अगर इनकी सीधी सड़क बन जाए और सीधे गांवों में एक या डेढ़ किलोमीटर का रास्ता सीधा गांव तक है। मेरे हल्के में घोल माजरा गांव है उसकी दूसरी पंचायत पड़ती है, वह दुराना सोसाइटी में पड़ता है। मुझे खुद भी जब वहां जाना पड़ता है तो वाया शाहबाद होकर जाना पड़ता है क्यों कि वहां का कोई भी सीधा रास्ता नहीं है। घोल माजरा से दुराना नयी सड़क का निर्माण करवाया जाए ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो। एक सड़क है मल्लोर से बकनौर वाया धाधरु। धाधरु गांव की पंचायत बकनौर गांव में पड़ती है उनका भी हाई स्कूल वहां पर है जिस कारण वहां पर आना जाना पड़ता है, बकनौर गांव में इनकी सोसाइटी भी पड़ती है और किसानों को भी वहां आना पड़ता है। कोई सीधा रास्ता न होने की वजह से वाया मठेरी शेखां 20 किलोमीटर का रास्ता तय करके गांव बकनौर जाना पड़ता है इसलिए बकनौर से मल्लोर सड़क बनाने का भी प्रयास किया जाए। गांव दीवाने आम से राष्ट्रीय मार्ग न० 1 तक की जगह विलेज सोसाइटी की पंचायत में आती है उनका भी गांव के साथ लिंक रोड नहीं है तथा उनको भी चक्कर काट कर जाना पड़ता है। एक मेरी राय है कि महेश नगर से बबियाल टांगरी बांध से ऐसा बाईपास बनाया जाए ताकि बबियाल, जहां की आबादी 20 हजार है वहां के लोगों को रास्ते की दिक्कत न हो।

एक हरीपुर से घसीटपुर तक की सड़क बनावई जाए। हरीपुर की पंचायत घसीटपुर में पड़ती है। उनका भी कच्चा रास्ता पड़ता है उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। बरसात के दिनों में वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती हैं। इसलिए हरीपुर से घसीटपुर तक की सड़क बनवाई जाए। पिछले दिनों मेरे हल्के की जो मेजर सड़कें हैं उनके बारे में यहां कहा गया था। टेपला से अकबर पुर के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों कारगिल की लड़ाई में एक जवान मनजीत सिंह शहीद हो गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए थे और उन्होंने वहां पर सड़क का नाम शहीद मनजीत सिंह रखने की घोषणा की थी तथा उस सड़क का नाम शहीद मनजीत सिंह रखा गया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वह दो सौ मीटर की सड़क है। यह सड़क जब चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे उनके वक्त में मार्किटिंग बोर्ड की तरफ से अकबर पुर से टेपला तक की सड़क की मंजूरी हुई थी उस सड़क पर मिट्टी भी डाल दी गई थी। लेकिन उसके बाद दूसरी सरकार आई और उसने बदले की भावना से उस सड़क को रुकवाने का काम किया। उस सड़क पर अभी भी मिट्टी गिरी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या शहीद मनजीत सिंह सड़क को टेपला से अकबरपुर तक पक्का करवाने का कष्ट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में सरकार आपके द्वार प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी ने चार स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की थी। वे चार स्कूल दानीपुर, मौदीयानोखेड़ी, घोरा और बनेढ़ा गांवों में है। इन स्कूलों के नार्म्स पूरे न होने की वजह से इनका केस ऑब्जेक्शन लगकर वापिस आ गया था। हमने उन ऑब्जेक्शंज को दूर करके केस को दोबारा से डायरैक्टर एजूकेशन के पास भेज दिया है। अब आप उन स्कूलों को दोबारा से अपग्रेड करवाने का कष्ट करें। गांव माजरी के बारे में मेरा प्रश्न लगा हुआ था कि पी.एच.सी. सैंटर पहले से ही बना हुआ है वहां पर डॉक्टर्स, नर्सिज, सफाई कर्मचारी और दूसरे जो भी कर्मचारी होते हैं वे सब हैं। लेकिन उसको पंचायत घर में चलाया जा रहा है। 14-15 गांवों के लोग वहां पर आते हैं और उन सबको बड़ी भारी दिक्कत होती है। आदरणीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 35 लाख रुपये उसके लिए मंजूर हो गए हैं और वह जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा। मैं फिर से यह कहना चाहूंगा कि इसको जल्दी से बनवाने का कष्ट करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरा हल्का फ्लड इफैक्टिड है। वहां पर जब भी बरसात होती है तो नग्गल सबसे पहले डूबता है। मुख्यमंत्री जी वहां जाकर आए थे और इन्होंने वहां पर देखा भी था कि एस.वाई.एल. का वहां पर औरी प्वाईंट है वहां पर पंजाब की तरफ से बरसात के दौरान

[श्री जसबीर सिंह मलौर]

बाढ़ का पानी एस.वाई.एल. के जरिए आ जाता है और वहां पर जो एस.वाई.एल. बनी हुई है वह चारों तरफ से टूटी हुई है जिसके कारण वह बाढ़ का पानी उस इलाके में फैल जाता है उसको बंद करवाने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में शूगर मिल नहीं है। फ्लड इफैटिड एरिया होने की वजह से गेहूं, धान और सरसों की फसलें पानी में डूब जाती हैं और खराब हो जाती हैं। गन्ना एक सख्त किस्म है यह ज्यादा पानी से खराब भी नहीं होता अगर मेरे हल्के में शूगर मिल लगा दी जाए तो मेरे हल्के के किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। आज वहां के किसान आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हो गए हैं उनको ऐसा करने से फायदा मिल सकता है। टांगरी नदी मेरे हल्के में पड़ती है। मदोसाव से गुराना के रास्ते पर उस नदी पर पुल बनवाया जाए। इस पुल के बारे में मैंने पिछले दिनों भी मांग रखी थी। अध्यक्ष महोदय, हमारे हल्के में जो गन्ना है उसको शाहबाद मिल तक ले जाने के लिए सीधा एक ही रास्ता है अगर वहां पर उस पुल का निर्माण करवा दिया जाए तो वहां पर 40 गांवों के लोगों को फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, जब चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे तो उनके वक्त में 66 के.वी. का सब-स्टेशन मंजूर किया गया था। वहां जो छोटे किसान थे उनको बदले की भावना 3-3 और 4-4 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली गई थी और वहां पर 66. के.वी. का सब-स्टेशन लगवाया गया था। उसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की थी कि उसको वहां से चेंज किया जाए। अब मुझे पता चला है कि उसको वहां से दुखेरी बदल दिया गया है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस सब-स्टेशन को दुखेरी की बजाए दूराना में या औझला में लगाया जाए क्योंकि वहां पर लोगों को ज्यादा दिक्कत है। अगर दुलेरी के सब-स्टेशन को दुराना में या औझला में लगा दिया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। स्पीकर सर, चौढ़मस्तर में 66 के.वी. का सब-स्टेशन है और उसका बहुत ज्यादा एरिया पड़ता है। उसको एक्सटैंड करके 132 के.वी. का किया जाए और उसके ट्रांसफामर्ज को आगुमैंट करके आठ की बजाए सोलह किए जाएं। उनके कंडक्टर भी चेंज किये जायें जब भी कभी 66 के.वी. का सब-स्टेशन का ब्रेक डाउन होता है तो उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं रहता है। इसके साथ ही लखनऊशाह में 66 के.वी. के सब-स्टेशन की ज्यादा जरूरत है वहां पर हमारे 35-40 गांव पड़ते हैं वहां पर बिजली की वोल्टेज भी बहुत कम आती है जिसकी वजह से किसानों की मोटरें बहुत ज्यादा जलती हैं। अगर यह सब-स्टेशन लग जाता है तो किसानों की मोटरें नहीं जलेंगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर 66 के.वी. का सब-स्टेशन लगाया जाए। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो सुल्लर ड्रेन मंजूर की गई है उसके लिए जल्दी से जल्दी पैसा प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाया जाए। अगर यह ड्रेन बन जाएगी तो वहां पर 18-20 गांवों को डूबने से बचाया जा सकेगा। इसी तरह से उदयपुर ड्रेन के बारे में भी एक ऐस्टीमेट बनवाकर भेजा जा चुका है लेकिन मुझे पता लगा है कि उसको रिजैक्ट कर दिया गया है। मैं चाहूंगा कि संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर इस बारे में देखें। मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर पंजाब की तरफ से जो पानी आता है वह हमारे हल्के के किसानों को बहुत नुक्सान पहुंचाता है इसलिए मेरा अनुरोध है कि उदयपुर ड्रेन को बनवाने का कष्ट करें ताकि किसानों को उसका फायदा हो। पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरे हल्के में गए थे वहां के लोगों ने अपनी एक समस्या के बारे में बताया था। उनकी समस्या यह है कि जो वहां एस.वाई.एल. कैनाल और नरवाना ब्रांच है उसके अंदर नीचे से एक साईफन की जरूरत है ताकि वहां से पानी जा सके। मुख्यमंत्री जी वहां के लोगों से कहकर आए थे कि इस साईफन को बनवाने के बारे में इंजीनियर्ज से सर्वे करवा लेंगे। इसलिए अब मेरा अनुरोध है कि इसका जल्दी सर्वे करवाकर वहां साईफन बनवाया जाए। इस बारे में एक ऐस्टीमेट

बनवाकर महकमे को भेज दिया गया है इसलिए कृप्या यह बनवाने का सरकार कष्ट करे ताकि वहां के गांव डूबने से बच सकें। धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश जिंदल (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, सरकार जो यह बजट लायी है उसमें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया गया है जो कि बहुत अच्छी बात है। किन्तु मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि साल में दस बारह बार जो दूसरे टैक्स लगाए जाते हैं क्या वे टैक्स नहीं हैं? सरकार ने पहले भी अलग-2 ढाईए के टैक्स लगाए हैं जिससे तेली, धोबी, मनिहार आदि लोग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा सरकार ने हाउस टैक्स भी बहुत ज्यादा लगाया है जिससे शहरी आदमी को बड़ी भारी समस्या हो रही है। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ये सब टैक्स नहीं हैं? अध्यक्ष महोदय, टैक्स लगाने की भी एक सीमा होती है। हिन्दुस्तान में शायद हरियाणा पहली स्टेट है जहां पर इस तरह के टैक्स लगाए गए हैं। ये टैक्स जनता के ऊपर बड़ा भारी बोझ हैं क्योंकि जनता इनके कारण त्राहि-2 कर रही है। वित्त मंत्री महोदय बता दें कि ये टैक्स जनता पर क्यों लादे गए हैं तो फिर यह बजट किसलिए है। इस बजट में कोई टैक्स घटाया या बढ़ाया नहीं गया है मगर दूसरे अनेक प्रकार के टैक्स तो सरकार ने लगाए हैं। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि उसको इन टैक्सिज के बारे में विचार करना चाहिए। इसी तरह से इंडस्ट्रीज की बात है। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हरियाणा में इंडस्ट्रीज दिल्ली से आएंगी। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि दिल्ली से बहुत इंडस्ट्रीज हरियाणा में आ सकती हैं अगर हमारी सरकार की पोलिसी ठीक हो। लेकिन हमारी सरकार की इस बारे में पोलिसी ठीक है क्योंकि यहां पर रोज बिजली के रेट बढ़ते हैं, रोज जमीनों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। मेरी दिल्ली में जब इस बारे में मीटिंग होती है तो वे लोग कहते हैं कि हम तो हरियाणा में अपनी इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं मगर हरियाणा में हालत इतने खराब हैं कि हम हरियाणा में इंडस्ट्रीज लगाने नहीं जाएंगे। हरियाणा में जो आलरेडी इंडस्ट्रीज चल रही थीं वे भी या तो बंद हो गयी या फिर वे शिफ्ट हो गयी। सरकार इस बारे में भी बता सकती है कि कितनी इंजस्ट्रीज बंद हो गयी या कितनी शिफ्ट हो गयी? अकेले हिसार में ही आठ या दस इंजस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज के बिजली के कनैक्शंज कटवा दिए हैं और वे अब हरियाण से बाहर जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रीज के बगैर कोई भी स्टेट प्रगति नहीं कर सकती। क्योंकि इनसे टैक्स आएगा, सेल्स टैक्स आएगा, एक्साइज ड्यूटी आएगी, इंकम टैक्स आएगा लेकिन जब इंडस्ट्री नहीं होगी, तब टैक्स किस चीज से आएगा। किसान आज बहुत दुखी है, बहुत चिल्ला रहा है किसान को बोला गया कि हम महीने में 15 दिन पानी देंगे जबकि पानी महीने में तीन दिन दिया जाता है किसान ने शुरू-शुरू में लीडरों का विश्वास करके खेती की, बीज डाला, हल चलाया। उसके बाद तीन दिन के बाद 27 दिन तक पानी नहीं आया। खेती सूख गई, किसान चिल्ला रहा है, रो रहा है और यह सरकार किसान की हम-दर्द बनी हुई है। ये कहते हैं कि हम किसान के लिए बहुत कुछ करेंगे। आज हरियाणा में चारों तरफ रास्ते ब्लॉक पड़े हैं किसान अगर रास्ते जाम करते हैं तो हवालात में जाते हैं वहां उनकी पिटाई होती है बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं व्यापारी तबके की बात कहना चाहूंगा। मंडियों में व्यापारियों के पास टेलीफोन जाते हैं फिरौती मांगी जाती है फिरौती न देने पर उनको धमकी दी जाती है कि अगर फिरौती नही दी तो उनका मर्डर कर दिया जाएगा और ऐसे वाक्य हुए हैं क्या यह सरकार की नॉलेज में नहीं है। जब वे लोग पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस रिपोर्ट लिखने के लिये तैयार नहीं होती है क्या यह सरकार के आदेश हैं। हम इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। अब में लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में कहना चाहता हूं। ये कहा करते थे कि हरियाणा में पूरे हिंदुस्तान से अच्छा लॉ एण्ड ऑर्डर है। आज हालात यह हैं कि हरियाणा में कोई कार के अंदर सफर करता है तो अपने आपको सेफ नहीं समझता है। यह

[श्री ओम प्रकाश जिन्दल]

बहुत भारी समस्या है। यही बातें मैं कहना चाहता था, आप ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अब जीतेन्द्र मलिक बोलेगें । चूंकि जीतेन्द्र मलिक बैठे नहीं है इसलिए श्री कृष्ण पाल गुज्जर बोलेंगे।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से जो नाम आपको लिखकर भेजे हैं मेहरबानी करके उसके हिसाब से बुलाएं। हमारी पार्टी की तरफ से शुरू में हमने मांगे राम गुप्ता जी का नाम दिया है।

Mr. Speaker : When I called Shri Mange Ram Gupta at 2.00 P.M., he was not present in the House. (Noise and interruption) No, No he was not present in the House at that time. (Noises) No. one, from Congress Party was present in the House.

अब आप सभी बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) कैप्टन अजय सिंह आपकी तसल्ली कराएंगे। अच्छी तरह से बुलाएंगे।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर सर, आप बगैर मतलब की बदमगजी क्यों करते हैं****?

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी जो कुछ कह रहे हैं उसे रिकार्ड न किया जाए। चौधरी भजन लाल जी जब गुप्ता जी का नाम मैंने पुकारा उस समय ये हाऊस में मौजूद नही थे। अब हम उनको बाहर से थोड़ी बुला कर ला सकते है। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री कृष्ण पाल (मेवला महाराजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल 12 मार्च को माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उस बजट के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। कल जो बजट पेश हुआ है वह कर रहित बजट है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ-साथ जहाँ मैं बधाई देता हूं दूसरी तरफ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बजट कर रहित पेश हो और बजट से पहले एक साल में लगातार अन्य तरह के टैक्स लगा दिये जायें यह ठीक बात नहीं है (विघ्न) क्योंकि मैं सहयोगी पार्टी से संबंधित हूं इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बातें किसानों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, मजदूरों और कर्मचारियों की हमें रोजाना सुनने को मिलती हैं अगर उन बातों को हम सदन में नहीं रखेंगे और जनता की भावनाओं को सरकार तक नहीं पहुचायेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा जनता से चुनकर आने का कोई मायना नहीं रहता है। अगर समय रहते हम जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुंचा दें और सरकार समय रहते उन समस्याओं पर उचित कार्यवाही कर दे तो हमारी सरकार अलोकप्रिय होने से बच सकती है और लोकप्रिय बन सकती है। इसलिए सरकार को मैं अपना एक सुझाव देना चाहता हूं (विघ्न) क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में अलोकप्रिय बने। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि बजट को सार्थक मान लिया जाये और जितने टैक्स बढ़ें वे बजट पेश होने के समय ही बढ़ें। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाये तो दूसरी बात है। माननीय वित्त मंत्री जी का ब्यान अखबार में आया है उसके बारे में बताता हूँ। उनसे जब किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या हरियाणा सरकार बजट पेश होने के बाद हरियाणा की जनता पर कोई टैक्स नहीं लगायेगी तो माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि इस बारे में अभी से कुछ नहीं

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

कहा जा सकता। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक आश्वासन इस सदन में चाहूंगा कि इस बजट और अगले साल के लिए बजट पेश होने से पहले हरियाणा की जनता पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस प्रकार का आश्वासन माननीय वित्त मंत्री जी ने हरियाणा की जनता को देना चाहिये। क्योंकि पिछले साल इतने टैक्स सरकार ने लगाये हैं कि उनको मैं गिनाने लगूंगा तो काफी समय लगेगा। पिछले साल फरीदाबाद में हाऊस टैक्स, पाँच गुणा से दस गुणा बढ़ा दिया गया। इसके अलावा एस्टिबलिशमेंट टैक्स चार प्रतिशत, लोकल एरिया डिवलैपमेंट टैक्स, फायर टैक्स, सैनिटेशन टैक्स, प्रोफैशनल टैक्स, इस प्रकार के कई तरह के टैक्स हरियाणा की जनता पर इस सरकार ने लगाये थे इसलिए अगर बजट में कोई टैक्स नहीं लगायें तो यह बात कोई मायने नहीं रखती। इसलिए मैं समझता हूं कि जो पिछली सरकार ने टैक्स लगाये हैं उन टैक्सों में सरकार कुछ राहत दे। क्योंकि हर वर्ग में, चाहे वह किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग हो या व्यापारी वर्ग हों, उद्योगपति हों, कर्मचारी हों या छात्र हों सभी वर्गों में सरकार के प्रति आक्रोश प्रकट हो रहा है। इसलिए समय रहते उनके आक्रोश को कम किया जाये। इसलिये टैक्सों में राहत देने का काम यदि सरकार करे तो उचित होगा। इसके साथ-साथ गुजरात में भूकम्प की आपदा में राहत देने के लिए जो हरियाणा सरकार ने कदम उठाये हैं वे बहुत ही सराहनीय हैं और उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। क्योंकि ऐसे समय में जब किसी प्रदेश के नागरिक सहायता के लिए दूसरे प्रदेश की तरफ देखते हैं तो मै समझता हूँ कि ऐसी आपदा के समय सहायता करना, एक अच्छा कदम है। लेकिन इसके बारे में मैं सरकार के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि ऐसा न हो कि इस अच्छे काम के बदले हरियाणा सरकार पूरे देश में उपहास का कारण बन जाये जहां इस राहत के काम की हरियाणा सरकार की तारीफ की गई वहां दस मार्च के ट्रिब्यून में जो है मैं आपको पढ़कर बताता हूं उसमें लिखा है कि जो डाक्टरों की टीम, अधिकारियों की टीम, कर्मचारियों की टीम यहां से गई थी उसके बारे में अखबार में हैडिंग आया है कि टीम बेक विद इम्पोर्टिड गुडीज़ अब यह कितना सत्य है कितना असत्य है। इसके बारे में मै कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं तो अखबार की रिपोर्ट सदन के सामने रख रहा हूं। इसी तरह से दूसरी अखबार दैनिक भास्कर के 12 मार्च के ऐडीटोरियल में लिखा है " हरियाणा की जनता का सरकार के साथ धोखा"। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि ये सारी बातें सच्ची हैं लेकिन अगर ये सच्ची हैं तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि इसकी जल्दी से जल्दी उचित जांच करके परसों तक सदन के सामने सच्चाई रखनी चाहिए जिससे मैं समझता हूं कि सरकार का नाम होगा और यह सरकार के लिए अच्छा भी होगा और हरियाणा के लोगों के लिये भी अच्छा होगा। उपाध्यक्ष महोदय,मैं एक सुझाव देना चाहता हूं बिजली के बारे में जो लोग महसूस करते हैं वह मैं बताना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि बिजली के रेट नहीं बढ़ने चाहिएं, बिजली के रेट बढ़ें। हमारे सदन के नेता मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि बिजली के रेट बढेंगे लेकिन 24 घण्टें बिजली देने के बाद बढ़ाएं जाएगें। मै समझता हूं कि हरियाणा को 24 घण्टे बिजली नहीं मिलती। किसानों को मुश्किल से दिन में केवल 4 या 5 घण्टे ही बिजली मिलती है। उद्योगपतियों को भी पूरी बिजली नहीं मिलती। उपाध्यक्ष महोदय, पूरी बिजली न मिलने के बावजूद भी बिजली के रेट में पिछले एक साल से जो बढ़ौतरी हुई है वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। जब हरियाणा बना है तब से कभी भी इतने रेट नहीं बढ़े। इस एक साल के पीरियड में किसानों को, उद्योगपतियों को और घरेलू उपभोक्ता को किसी को भी नहीं बक्शा है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि बिजली के रेटों में बढ़ौतरी हो लेकिन 24 घण्टे बिजली देने के बाद। पिछले एक साल में जो बिजली के रेटों में बढ़ौतरी हुई है वह मैं सदन के सामने रख रहा हूं। 1-7-96 को बिजली का डोमेस्टिक रेट एक रुपये 91 पैसे प्रति यूनिट था, नान डोमैस्टिक यानि कॉमर्शियल बिजली का रेट 3 रु० 41 पैसे प्रति यूनिट था,

[श्री कृष्णपाल]

छोटे उद्योगों पर भी 3 रु० 41 पैसे प्रति यूनिट था तथा बड़े उद्योगों पर भी 3 रु० 41 प्रति यूनिट था। किसानों को बिजली 50 पैसे प्रति यूनिट मिलती थी। लेकिन 16.68 को जो डौमैस्टिक रेट था उसमें 40 यूनिट तक का स्लैब था उसमें कोई रेट नहीं बढ़ाया गया। छोटे उद्योगों पर 3 रु० 41 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 3 रु० 92 पैसे कर दिया गया यानि 51 पैसे प्रति यूनिट बिजली के रेट बढ़ाए गए। कॉमर्शियल बिजली पर भी 51 पैसे बढ़ाकर 3 रु० 92 पैसे कर दिया गया। बड़े उद्योगों पर भी 51 पैसे बढ़ाकर 3 रु० 92 पैसे कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इसके इलावा 1.8.2000 को जो बिजली के फ्यूल चार्जिज बढ़ाए गए हैं वे इस प्रकार हैं – डौमैस्टिक पर 13 नए पैसे प्रति यूनिट, कॉमर्शियल पर 21 नए पैसे प्रति यूनिट, छोटे उद्योगों पर 21 नए पैसे प्रति यूनिट, बड़े उद्योगों पर 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए गए। इसके साथ किसानों को जो बिजली दी जाती है इसमें हार्स पावर का रेट 65 रु० से बढ़कर 74 रु० कर दिया गया। इसी तरह से यूनिट शड्यूल चार्जिज के नाम पर 3 नए पैसे यानि 50 पैसे से 53 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया। लेकिन अभी-अभी, उपाध्यक्ष महोदय, 1-1-2000 को नए बिलों में जो बिजली के रेट्स में बढ़ौतरी हुई है, उसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो सबसे छोटा डौमैस्टिक कंज्यूमर है, जो 40 यूनिट बिजली उपभोग करता है उसका रेट 2 रुपये 4 पैसे प्रति यूनिट था जिसको बढ़ाकर 2 रु० 88 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है यानि 84 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया गया है। इसी तरह 41 यूनिट से 300 यूनिट तक कंज्यूम करने वाले पर बिजली का रेट 2 रुपये 60 पैसे प्रति यूनिट था लेकिन यह अब बढ़ाकर 3 रुपये 88 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है यानि एक रुपये 28 पैसे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह 300 यूनिट से ऊपर जो बिजली कंज्यूम करता है उस पर बिजली का रेट 3 रुपये 10 पैसे की जगह 4 रुपये 53 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, उसी तरह से जो उद्योगपति हैं जिनको पहले 70 होर्स पावर तक सरकार की तरफ से ट्रांसफार्मर लाईन और केबल दी जाती थी लेकिन अब इसे घटाकर यह सुविधा 50 होर्स पावर तक के उद्योगों के लिए ही कर दी गई है। इससे ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार उद्योगों को बढ़ावा नहीं देना चाहती। इसके अतिरिक्त जो 50 या 70 किलोवाट बिजली की क्षमता वाले जो छोटे उद्योग हैं जिनसे पहले 1996 में 3.92 रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल लिया जाता था अब बढ़ाकर 4.44 रुपये प्रति यूनिट कर दिया है और जो उससे और बड़ा उद्योग है उसका 4.32 रुपये कर दिया गया है। जो 66 के.वी.ऐ. से 132 के०व०ऐ० की क्षमता के थे जिनसे पहले 3.92 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल लिया जाता था इसे भी बढ़ाकर 4.20 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है तथा जो 220 के०वी०ऐ०से उपर की क्षमता के हैं उनका रेट भी प्रति यूनिट 3.92 पैसे से बढ़ाकर 4.61 प्रति यूनिट कर दिया गया है। मौजूदा सरकार ने घरेलू उपभेक्ता या बड़े उद्योगों के ही बिजली के रेट नहीं बढ़ाये बल्कि किसानों को भी नहीं बख्शा। मौजूदा हरियाणा सरकार आपने आप को किसानों की सरकार कहती है। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है अगर यहां किसान बचेगा तो हरियाणा बचेगा यदि किसान नहीं बचेगा तो हरियाणा भी नहीं बचेगा। लेकिन इन्होंने किसानों को भी बिजली से रेट में राहत नहीं दी। पहले किसानों को जहां 69 रु० प्रति होर्स पावर के हिसाब से फलैट रेट पर जो बिजली दी जाती थी उसमें 35 रुपये की बढ़ोतरी करके 104 रुपये प्रति होर्स पावर कर दिया गया है जो 38 से 40 फीसदी की बढ़ोतरी है। इससे किसानों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। समय रहते मौजूदा सरकार को इस आक्रोश को कम करना चाहिए ताकि सरकार की किसानों में अच्छी छवि बने और सरकार लोकप्रिय हो। इसी तरह किसानों को जहां पहले मीटर के हिसाब से 53 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती थी उसका रेट भी 1-1-2000 को बढ़ाकर 65 पैसे

प्रति यूनिट कर दिया गया है । अभी जैसे भाई धर्मबीर जी ने कहा था कि फ्लैट रेट को समाप्त करके मीटर के आधार पर किसानों को बिजली दी जायेगी, अगर ऐसा हो गया तो किसानों को कोई नहीं बचा सकेगा। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए और किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जहां तक मौजूदा सरकार हरियाणा में उद्योग लाने की बात कर रही है और कह रही है कि हरियाणा में उद्योगों की बढ़ौतरी हो रही है तो मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा में बिजली मंहगी होने के कारण उद्योगों में बढ़ौतरी नहीं हो रही । क्योंकि पहले जहां छोटे उद्योगों से मिनिमम 60 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से बिजली के बिल लिये जाते थे वे रेट अब बढ़ाकर 200 रुपये प्रति किलोवाट कर दिए गये हों जो कि 333 प्रतिशत की बढ़ौतरी है। जहां बड़े उद्योगों से 120 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से लिये जाते थे उनका रेट मिनिमम 400 रुपये प्रति किलोवाट कर दिया गया है। इन उद्योगों में फैंसीज और स्टील रोलिंग मिल्ज आदि आते हैं। इसी तरह से जो घरेलू उपभोक्ता हैं जिनसे पहले 20 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से बिल लिये जाते थे उनके रेट बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलोवाट कर दिए गए हैं और जिन से 40 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से लिए जाते थे उनके 120 रुपये प्रति किलोवाट मिनिमम कर दिए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अगर बिजली के रेट इसी तरह बढ़ते रहे तो हरियाणा से उद्योग प्लायन कर जायेंगे। अगर उद्योग यहां बढ़ेंगे तो उससे कृषि पर भी भार कम होगा क्योंकि उद्योग बढ़ने से लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन मौजूदा हालत में हरियाणा में उद्योग कैसे आयेंगे यह एक सोचने का विषय है। इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बिजली के रेट बढ़ाने से सरकार को केवल फायदा ही नहीं है बल्कि राष्ट्रीय लोस भी हो रहा है। इसको मैं उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि जो उपभोक्ता पहले मिनिमम 1935 यूनिट बिजली उपयोग करता था उसका बिल 60 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक आता था अब उनका मिनिमम बिल 13500 रुपये आने लगा है। इसलिए अब उपभोक्ता सोचता है कि जब 13500 रुपये मिनिमम बिल आना ही है तो क्यों न वह अपना ऐ०सी०, पंखा आदि चीजें हमेशा चलाये। इसलिए वह बिजली का गलत यूज करता है जिससे राष्ट्रीय लौस होता है और यह किसी के भी फायदे की बात नहीं है। इसलिए इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो मिनिमम चार्जिज लगाये हैं उन पर पुनर्विचार किया जाये। अकेला ऐसा यही एक उदाहरण नहीं है और भी ऐसे उदाहरण हैं जो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। जहां तक उद्योग बढ़ाने की बात है एक तरफ कह रहे हैं कि हरियाणा में उद्योग बढ़ाये जा रहें हैं लेकिन जो बजट का आर्थिक सर्वेक्षण है पेज न० 24 पर वह बताता है कि 1997-98 में हरियाणा में 78847 उद्योग थे जबकि 2001 के आंकड़ों में 71880 उद्योग दर्शाये गये हैं यानि तकरीबन 7000 उद्योग हरियाणा से चले गये। उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कह रही है। इसी तरह से किसानों को बिजली देने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि किसानों को नलकूपों के लिये बिजली के नए कनैक्शन दिये गये हैं लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि आज अगर कोई किसान ट्यूबवैल के लिये बिजली का कनैक्शन मांगता है तो उसे नहीं मिलता है। किसानों ने कनैक्शन के लिये चालीस हजार से साठ हजार रुपये तक दिये हुए हैं। अगर कहीं से तत्काल कनैक्शन लेना हो और उसके लिए जो तार लगाई जाती है उसके लिये तत्काल सेवा सुविधा स्कीम के तहत किसानों से चालीस हजार रुपये से साठ हजार रुपये लिये जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले किसान से कनैक्शन के लिये 10000/- रुपये लिये जाते थे इसलिये अब भी वही अमाउन्ट रहना चाहिए। (विघ्न)

12-00 बजे

श्री रामपाल माजरा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय साथी जो बता रहे हैं कि तत्काल सेवा सुविधा योजना के तहत किसान से कनैक्शन के लिये चालीस हजार रुपये से साठ हजार रुपये लिये जाते हैं वह गलत बात है। एक पोल या दो पोल लगाकर जो 30 मीटर की केबल लगाई जाती है उस हिसाब से तत्काल सेवा में किसान से 10000/- रुपये या अधिकतम 20000/- रुपये जमा कराये जाते हैं और इसी तरह के 9111 कनैक्शन किसानों को दिये गये हैं।

श्री कृष्ण पाल : उपाध्यक्ष महोदय, ये भी किसान के बेटे हैं और मैं भी किसान के घर ही पैदा हुआ हूं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार के हित की कोई बात नहीं है जो लोकप्रिय सरकार है उसे मैं, सुझाव दे रहा हूं। जो जनता की सोच या भावना है वही मैं कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं वह रिकार्ड की बात है। मैं कोई असत्य बात नहीं कहता। जैसा कि माजरा साहब 10000/- रुपये में कनैक्शन देने की बात कहते हैं उस सम्बन्ध में, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि जब किसान अधिकारी के पास कनैक्शन के लिये जाते हैं तो अधिकारी उनसे कहते हैं कि इसमें हमारी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते। कनैक्शन के लिये 40,000/- रुपये से 60,000 रुपये तक जमा तो कराने पड़ेंगे। (विघ्न)

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय साथी बजट के ऊपर बोलते हुए अपनी स्पीच में यह बात कह रहे हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि तत्काल योजना का जो उद्देश्य था, यह इनको पता होना चाहिए। (विघ्न) चौधरी भजन लाल जी भी मुख्य मंत्री रह गये, उसके बाद चौधरी बंसी लाल भी मुख्य मंत्री रहे। पिछले साढ़े आठ साल में किसान बार-बार इनके चेहरों की तरफ देखते रहे लेकिन कोई कनैक्शन जारी नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, तत्काल योजना का मतलब है कि अगर किसी का नम्बर कट जाएगा तभी सुविधा प्राप्त होगी तत्काल योजना के तहत यह सुविधा किसानों तक पहुंची है और इसके लिये समय निर्धारित किया गया था। पता नहीं, ये कहां से रिपोर्ट लेकर आये हैं।

श्री कृष्ण पाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ जनता की भावनाएं प्रकट कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, रामपाल माजरा जी बैठे बैठे कह रहे हैं कि चौधरी बंसी लाल जी ने आपके सुझाव मान लिए होंगे हमारी सरकार आपके सुझाव नहीं मानेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि चौधरी बंसी लाल जी हमारे दिए हुए सुझाव इसलिए मान लेते थे क्योंकि हमारे सहारे इनकी सरकार चल रही थी लेकिन आज के मुख्य मंत्री जी को हमारे सुझाव शायद इसलिए मंजूर नहीं क्योंकि उनका पूर्ण बहुमत है। (शोर)

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वाइंट औफ आर्डर है। इन्होंने चौधरी बंसी लाल जी के सामने जो सुझाव रखे वह उन्होंने मान लिए होंगे। अगर इनके सुझाव अच्छे होंगे तो हम भी मानेंगे। हम चौधरी बंसी लाल जी की तरह इनके गलत सुझाव मानने वाले नहीं हैं। (शोर)

श्री कृष्ण पाल : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि यदि मेरे अच्छे सुझाव होंगे तो ये मानेंगे अगर सही नहीं होंगे और अच्छे नहीं होंगे तो नहीं मानेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस सरकार के सामने जनता की भावनाएं रख रहा हूं और वह मानना न मानना सरकार की मर्जी है। उपाध्यक्ष महोदय बजट के बारे में रूलिंग पार्टी की तरफ से जो मेजें थपथपाई जा रही हैं उस बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर समय रहते जनता की भावनाओं के बारे में नहीं सोचा गया तो

जनता के थपेड़े हमारे मुंह पर पड़ेंगे। उपाध्यक्ष महोदय,बिजली के कनैक्शन के बारे में कहना चाहूंगा। अभी चौधरी धीर पाल जी ने कहा था कि इनकी सरकार ने किसानों को बिजली के नए कनैक्शन दिए हैं। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि अगर कोई तत्काल सेवा सुविधा लेना चाहेगा तो उसको एक से चार पोल तक के दस हजार रुपए देने होंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, चार पोल से भी आगे ट्रांसफारमर लगाने को किसानों ने इच्छा जाहिर की तो वह भी लगा दिया जाएगा क्योंकि कई जगह चार पोल से आगे भी ट्रांसफरमर ओवर लोडिड थे। किसानों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हमने ट्रांसफारमर की जो आवश्यकता है उसको हमने अलग से दर्शाया है और जहाँ चार पोल तक की आवश्यकता है उसको अलग से दर्शाया हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि रुटीन के कितने बिजली के कनैक्शन इंक्रीज हुए हैं ?

श्री धीरपाल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, तत्काल सेवा सुविधा के अन्तर्गत जो बिजली का कनैक्शन लेना चाहेगा उसको बिजली का कनैक्शन मिल जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी भजन लाल जी जितने बिजली के कनैक्शन पैंडिंग छोड़ कर गए थे उनको हमने बिजली देने की पूरी कोशिश की है। (शोर)

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई मैम्बर बोल रहा हो तो मुख्य मंत्री और इनके मंत्री बीच में ही खड़े हो कर जवाब देना शुरू कर देते हैं। इस तरह से बीच में खड़े हो कर जवाब देने का कोई कायदा नहीं हैं। इनको मैम्बर की बात का बाद में जवाब देना चाहिए। इस तरह से बीच में मैम्बर को टोकने से उसके बोलने की स्पीड कम हो जाती है और मैम्बर अपनी बात भूल भी जाता है। इसलिए ये किसी मैम्बर को बीच में न टोकें। (शोर)

श्री कृष्ण पाल : उपाध्यक्ष महोदय,बजट का एक एहम् मुद्दा है। इस पर पूरे हरियाणा की प्रतिक्रिया आनी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बजट पर मैं अकेला बोलूंगा। हमारी पार्टी के और सदस्य बजट पर नहीं बोलेंगे क्योंकि वे गवर्नर एड्रैस पर बोल चुके हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि किसानों के बिजली के कनैक्शन कितने इन्क्रीज हुए हैं। इस सरकार के आने के बाद किसानों के ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन इंक्रीज नहीं हुए बल्कि घटे हैं। आपके सवाल में भी इन्होंने माना है कि कनैक्शन घटे हैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कृष्णपाल जी आप गलत कोट कर रहे हैं। मैंने यह पूछा था कि किसानों के ट्यूबवैल्ज के रूटीन के कितने कनैक्शन इंक्रीज हुए हैं।

श्री कृष्ण पाल : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया कि 1-2 पोल तक 10 हजार रुपये खर्च करने होंगे और चार पोल से ऊपर तक किसानों के 40 हजार से 60 हजार रुपये तक खर्च होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरे सवाल को गलत कोट कर रहे हैं। मैंने केवल यह पूछा था कि किसानों के ट्यूबवैल्ज के रूटीन के कितने कनैक्शन इंक्रीज हुए हैं।

श्री कृष्ण पाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वर्ष 1997-98 में ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन 3 लाख 92 हजार थे जो अब घटकर 3 लाख 57 हजार रह गए हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। इन द्वारा टैक्स बढ़ाए

[श्री कृष्णपाल]

जाने के कारण ही यमुनानगर-जगाधरी के मैटल युनिट्स चौपट हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इन्होंने यानि हुड्डा ने जो सरकार के विभाग का हिस्सा है उसने अपने काफी रेट्स पहले से कई गुणा बढ़ा दिए हैं। हुड्डा ने मकान/प्लाट ट्रांसफर फीस एडमिनिस्ट्रेशन चार्जिज व डैथ केसिज में जो पहले 100 रुपये फीस थी उसको 100 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया है यानि 50 गुना रेट्स बढ़ा दिए हैं। (शोर एवं विघ्न) इसी प्रकार से नलवा सिक्योरिटी की फीस जो पहले 200 रुपये थी उसको भी बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है यानि 10 गुणा वृद्धि कर दी है। जो चैकिंग फीस पहले 1 रुपया प्रति मीटर थी अब 20 रुपये प्रति मीटर कर दी है। यानि इस की भी 20 गुणा वृद्धि कर दी है इसी प्रकार से माइनर चेंजिज के लिए जो 50 फुट तक 200 रुपये और 50 फुट से ऊपर 400 रुपये थे उसके रेट्स भी बढ़ाए गए हैं। इसी प्रकार से जोनिंग वायलेशन की फीस भी पहले से काफी अधिक बढ़ा दी गई है। (शोर एवं विघ्न)

श्री धीर पाल सिंह : आन ए प्वाइंट ऑफ आर्डर सर।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, पहले आप मेरी बात तो सुनें। धीरपाल जी कौन से तरीके से बीच में बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं। (शोर एवं विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : मुझे क्या बोलने का तरीका आपसे सीखना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने जा रहा हूं कि सरकार के पास कुछ ऐसी जानकारियां आई थीं कि जो पहले नोटिस वगैरह भेजे जाते थे उनमें बड़ी वाइलेशन होती थी। सरकार ने अब अधिकार सीमित कर दिए हैं। यदि अब किसी को अगर 200 रुपये का नोटिस भेजा गया है तो उससे 200 रुपये ही लिए जाएंगे और 200 रुपये की ही रसीद सम्बन्धित व्यक्ति को काट कर दी जाएगी। ये सारी बातें बकायदा हुड्डा विभाग के साथ बैठकर तय की गई हैं। अब यदि किसी ने कोई अपील करनी है तो वह सीधा कमिश्नर को अपील कर सकता है। बीच में जो समय खराब होता था यानि दूसरे अधिकारी के पास अपील होती थी अब उसको खत्म कर दिया है। अब एक अधिकारी द्वारा फैसला दिए जाने के बाद उसकी अपील सीधे कमिश्नर के पास की जा सकेगी। इससे लोगों को फायदा ही हुआ है। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं कि रेट्स बढ़ाए गए हैं। भजन लाल जी, आपके समय में जो लेन-देन का मामला बीच में चलता था उसको समाप्त कर दिया है।

श्री कृष्ण पाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह जो नाजायज बढ़ौतरी की है उस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि लोगों को हुड्डा की तरफ से राहत मिलनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि कितने टैक्स पिछले साल में लगाए गए हैं, कितने टैक्स इस साल में लगाए हैं, किस दर पर टैक्स लगाए हैं और सरकार ने कितने टैक्स वसूल किए हैं इस बारे में रिप्लाई के समय बताने का कष्ट करें। उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़े वर्ग के लोगों को प्राइवेट इंजिनियरिंग कॉलेजिज में आरक्षण मिलता था जो माननीय हाईकोर्ट ने समाप्त कर दिया था जिसके कारण हरियाणा प्रदेश के ओ.बी.सी. छात्रों में बहुत आक्रोश है। उस आक्रोश को कम करने के लिए हम चाहेंगे कि सरकार कुछ कार्यवाही करे। सरकार द्वारा इस बारे में तरह तरह के बिल विधान सभा में और सदन में लाए जाते हैं। पिछड़ी जाति के छात्रों को प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेजिज में दाखिला मिल सके इस प्रकार का बिल सदन में आना चाहिए ताकि पिछड़ी जाति के छात्रों को कुछ राहत मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं सिंचाई की बात कहना चाहूंगा। आज हरियाणा की नहरों में 40-40 दिन तक पानी नहीं आता है और दक्षिणी हरियाणा में नहरों की क्या स्थिति है वह सब जानते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि पानी

का बंटवारा बराबर निश्चित होना चाहिए। इसके साथ ही सरकार ने ग्रामीण विकास समितियां बनाने का जो काम किया है उसमें पंचायती राज एक्ट की घोर उलंघना की है। उससे पार्टीबाजी और गुटबाजी को बढ़ावा मिला है और लड़ाई झगड़े बढ़े हैं। अगर इस प्रकार का काम किया जाना है तो फिर पंचायतों और जिला परिषदों के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे और ग्रामीण विकास समितियां बनाने का काम रोके। उपाध्यक्ष महोदय, इस के अतिरिक्त मैं एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हरियाणा में जो माइनिंग हो रही है सरकार उस पर एक श्वेत पत्र जारी करे कि जब से हरियाणा बना है तब से लेकर अब तक किन-किन लोगों को खानें दी गई हैं, किस-किस तरह की नीति किस काम के लिए होती है, जो खान माइनर मिनरल्ज के लिए दी गई हैं क्या वही निकाली जा रही है या कि उसकी आड़ में दूसरे खनिज वहां से निकाले जा रहे हैं। सरकार अगर चाहे तो इस सदन की एक कमेटी बना सकती है और उस समिति से रिपोर्ट मंगवा सकती है आज जिस चीज के लिए माइन पट्टे पर दी जा रही है उसकी एवज में क्या दूसरी चीजें तो वहां से नहीं निकाली गई हैं ? लीज होल्डर पर सरकार का कितना बकाया दिखाया है और उसकी उगाही के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है वह इस सदन को अवगत करवाने की कृपा करें। उपाध्यक्ष महोदय, खतरनाक बात यह है कि लीज होल्डर जमीन के नीचे 500 फुट तक चले गए हैं और जमीन में से पानी आना शुरू हो गया है जिसके कारण जमीन के नीचे पानी धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। । बड़े-बड़े पाइपों से पानी जमीन में से निकाला जा रहा है जो कि पर्यावरण के लिए खतरा बन रहा है क्योंकि आस पास के गांवों का वाटर लैवल बहुत नीचे जा रहा है। उस पानी को वहां से निकालने से रोकना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि ये सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए। वे जो पानी निकाल रहे हैं उससे आने वाले समय में आस पास के गांवों में पानी की विकराल समस्या पैदा हो जाएगी। इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है ? एच.एम.एल. की खानें किस-किस को दी गई हैं और उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके बारे में भी सरकार को बताने की कृपा करें। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं सदन का ध्यान केन्द्र सरकार की योजनाओं की तरफ भी दिलाना चाहूंगा जो कि हरियाणा सरकार के माध्यम से चलाई जा रही हैं। सरकार यह बताने का कष्ट करे कि इन पर क्या कार्यवाही की गई है। फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना है, आवास योजना है, ग्रामीण जल योजना है, सड़क निर्माण योजना है, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो तीन करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने दिए हैं उसका हरियाणा सरकार क्या कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ ''सरकार आपके द्वार'' जो कार्यक्रम मुख्य मंत्री जी ने शुरू किया है मैं उसका बहुत ही स्वागत करना चाहता हूं उससे जनता और सरकार के बीच की दूरी समाप्त हो गई है। यह बहुत ही बढ़िया कदम है लेकिन मैं इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि ''सरकार आपके द्वार'' कार्यक्रम आने से जो लैजिस्लेशन सिस्टम है वह हरियाणा में समाप्त हो रहा है। इसके कारण आज एम०एल०ए० की हालत क्या हो गई है गांव का पंच और सरपंच अपने गांव में काम करवा सकता है, जिला परिषद अपने ऐरिया में कोई भी काम करवा सकती है लेकिन एक एम०एल०ए० अपने क्षेत्र में कुण्डा तक नहीं लगवा सकता है। धीरे-धीरे विधायक सिस्टम चकनाचूर हो रहा है।

श्री रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। मैं माननीय कृष्ण पाल जी से पूछना चाहूंगा कि जब ये बंसी लाल जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे उस समय इन्होंने मन्त्री होते हुए इस बात को क्यों नहीं उठाया था?

श्री कृष्ण पाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रणबीर सिंह जी ने जो सवाल किया है तो मैं

[श्री कृष्णपाल]

इनको बताना चाहूंगा कि हम उस समय क्या किया करते थे। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि एच.आर.डी.एफ.सी. से जो रूलिंग पार्टी के विधायक ग्रामीण विकास के लिए जितना पैसा चाहते थे वह ले जाते थे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अपोजिशन का मैम्बर कोई घोषणा तो अपने हलके में कर सके। चाहे कोई कम्यूनिटी सैंटर बनवाना हो या दूसरा कोई काम करवाना हो तो कोई भी विधायक या मंत्री इसका उद्घाटन नहीं कर पाता है। आज जो सत्ता का केन्द्रीयकरण हो रहा है वह हरियाणा के हित में नहीं है। आज जो भी विधायक चुन कर आता है उसके मन में बहुत आशाएं होती हैं कि मैं अपने हल्के में यह काम करवाऊंगा वह काम करवाऊंगा लेकिन आज छोटे से छोटा काम भी '' सरकार आपके द्वार'' कार्यक्रम के तहत हो रहा है। अगर यह सिस्टम इस तरह से लगातार टूटता रहेगा तो यह बहुत ही गम्भीर विषय है और इस बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृष्ण पाल जी आपको बोलते हुए 40 मिनट हो गए हैं आप पांच मिनट में वाईंडअप करें।

श्री कृष्ण पाल : उपाध्यक्ष महोदय, ''सरकार आपके द्वार'' में मुझे पता नहीं मुख्य मंत्री जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। मैं वह बात कहने जा रहा हूं जो समाचार पत्र में पढ़ी है और जो उसमें छपी है। उसमें कितना सच है कितना असत्य है यह मुझे नहीं पता है। कई बार लोगों को बहुत ही अपमानित होना पड़ता है। पलवल में मुख्य मंत्री जी किसी गांव में ''सरकार आपके द्वार'' के कार्यक्रम में गए हुए थे और कुछ लोग इनसे मिलने के लिए आए और कहा कि हमारे यहां पर पोल वगैरह लगवा दें तो मुख्य मंत्री जी ने पूछा कि इनके बिजली के कितने बिल बकाया हैं। जब उनको बिल के बारे में बताया गया तो इन्होंने कहा कि इनके जितने भी पोल हैं उनको उखाड़कर किसी दूसरी जगह पर लगवा दो। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह कहना है कि यह व्यवहार ठीक नहीं है। इसके साथ मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि सरकार आपके द्वार में मुख्य मंत्री जी ने कितने स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की है और उनमें से कितने स्कूल नार्म्ज पूरे करते थे और कितनों को अपग्रेड किया गया है इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितने स्कूल नार्म्ज पूरे नहीं करते थे और उनके दोबारा से नार्म्ज पूरे किए गए थे और नार्म्ज पूरे करने के बाद ऐसे कितने स्कूलों को अपग्रेड किया गया है।

इसके साथ ही मैं कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे-जैसे आबादी बढ़ती है वैसे-वैसे कानून व्यवस्था और खराब होती रहती है। अगर उसमें सुधार किया जाए तो हरियाणा के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा। लेकिन आज कहीं पर अगर डकैती, हत्या, फिरौती और बलात्कार की घटनाऐं होती हैं तो सरकार को इसके लिए अपना शिकंजा कसने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, इस्माइलपुर में 138 एकड़ जमीन है वहां पर ग्रीन एस्टेट नाम की सोसाइटी है और उसमें 1580 मैम्बर्ज हैं उसमें प्रशासन के लोग गरीबों की जमीन काटकर प्लाट बेच रहे हैं। और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वहां पर मिलीभगत से सारे प्लाट्स बेच दिए गए और उन पर मकान बना दिए गए। वे लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं उन भू-माफियों में से चार की हत्या हो चुकी है और अब भी वहां पर जमीन लगातार बेची जा रही है। उस सोसाइटी के सदस्य अपने आपको असहाय महसूस कर रहे हैं इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इस तरफ ध्यान दिया जाये। सरकार ने अभी तक वहां पर सैक्शन चार लगाया है लेकिन वहां का भू-माफिया उन लोगों

से कह रहा है कि चिंता मत करो हम यह सैक्शन चार भी हटवा देंगे। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार ने जो सैक्शन चार लगाने की नोटिफिकेशन जारी की है उसको वापिस न लिया जाए और जिन लोगों की वहां पर जमीनें एक्वायर की गई हैं उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वहां के गरीब लोगों की जमीनों को भू-माफिया खा जाएंगे। इसी तरह से गुड़गांव में जो भूकम्प आया था उसकी वजह से वहां पर कई मंजिली इमारतों में दरारें आ गई हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इनको गिराना चाहती है या इनकी मुरम्मत करवाना चाहती है? सरकार को इस बारे में तुरंत फैसला करना चाहिए क्योंकि यह लोगों के हित की बात है। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया और अगर कभी कोई प्राकृतिक प्रकोप आ गया तो वहां पर जान माल का बहुत नुक्सान हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बुढ़ापा पेंशन की बात है सरकार ने इसे सौ रुपये से बढ़ाकर दो सौ रुपये किया है जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बारे में भी व्यक्तियों की पहचान के बारे में एक प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि सौ रुपये से दो सौ रुपये करने के बाद कितने लोग पेंशन पाते हैं और पहले कितने लोग पेंशन पाते थे? सरकार यह भी बताए कि अब भी कितने लोग यह पेंशन पाने से वंचित हैं। मैं चाहूंगा कि जो लोग अभी भी यह सुविधा पाने से वंचित रह गये है उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। सरकार को इस बारे में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। इसी तरह से एस.वाई.एल. का जिक्र आता है मैं चाहूंगा कि सरकार को इस बारे में एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि आज तक इस पर कितने करोड़ रूपया खर्च हुआ और जो इसके लिए हजारों एकड़ भूमि आर्जित की गयी उसका क्या लाभ हुआ? अगर सरकार ऐसा करेगी तो इससे सभी को लाभ होगा। उपाध्यक्ष महोदय,विभिन्न निगमों की प्रशासनिक रिपोर्ट पांच छः साल तक नहीं आती है हम चाहेंगे कि इनकी प्रशासनिक रिपोर्ट 6 महीने के अंदर-2 सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए। अगर सरकार ऐसा करेगी तो मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिए भी और निगमों के लिए भी अच्छा होगा। इसी तरह से आडिट विभाग से जो नोटिस आते हैं उन पर भी कुछ कार्यवाही नहीं होती है मैं चाहूंगा कि इस बारे में भी सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए और जो सहकारिता विभाग है उसका आडिट भी ए०जी०आफिस से ही करवाया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आगरा कैनाल के बारे में एक क्वैश्चन पूछा था लेकिन वह नहीं लगा। । इस कैनाल के ऊपर पल्ला पुल और एतमादपुर दो पुल हैं ये दोनों ही पुल वर्षों पुराने होने की वजह से टूट चुके हैं जिससे वहां पर लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। चूंकि अब वहां पर कार, ट्रक या बस से लोग अपना सामान नहीं ले जा सकते इसलिए उनकी परेशानी और बढ़ रही है। अब वहां लोग साईकिलों से आ जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार को इन पुलों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का और सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। हरियाणा में एक चौकसी ब्यूरो बना हुआ है। मैं चाहूंगा कि इस चौकसी ब्यूरो का सदुपयोग हो। चौकसी ब्यूरो को अपने राजनैतिक विरोधियों के पीछे लगाने के बजाए अगर निगमों और सरकारी विभागों की जांच पर लगाया जाए तो यह ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि इससे बड़े-2 घपले पकड़े जाएंगे। लेकिन आज इस चौकसी ब्यूरो का इस्तेमाल कभी कृष्णपाल की चौकसी करने पर, कभी जय प्रकाश गुप्ता की चौकसी करने पर, कभी मान की चौकसी करने पर और कभी दलाल साहब की चौकसी करने पर हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह प्रथा सही नहीं है। अगर यह काम चौकसी ब्यूरो से करवाना है तो मैं चाहूंगा कि जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक जितने भी सदस्य विधान सभा में चुनकर आए हैं या अब तक जितने भी मंत्री और मुख्य मंत्री हुए हैं, सबकी जांच एक बार ही सी.बी.आई से हो जाए तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उपाध्यक्ष

[श्री कृष्ण पाल]

महोदय, मैं इसलिए चौकसी ब्यूरो की बात कर रहा था कि सन् 1995 में करोड़ों रुपये का घोटाला चौधरी भजन लाल जी के राज में हुआ। उस घोटाले के खिलाफ 26.11.96 को एफ.आई.आर. संख्या 621 सिरसा थाने में दर्ज हुई और मैं उस बारे में यहां प्रूफ दिखाना नहीं चाहता। उस बार में सारे प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं कि उसमें एम.डी. ने क्या लिखा, सैक्रेटरी ने क्या लिखा। उसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि यह कपास का घोटाला हुआ है। सरकार की निगम की नीति थी कि कोई भी कपास बेचने से पहले उसके ऐवज में अग्रिम भुगतान करना होगा या कोई पे-आर्डर देगा या चैक देगा और चैक कैश होने के बाद ही कपास की सप्लाई दी जाएगी। लेकिन बोगस चैक ले लिया और चैक क्लीयर होने से पहले ही सारा कपास यहां से भेज दिया गया और चैक डिसऑनर हो गया। (शोर एवं विघ्न) सारे विभाग ने इस मामले के खिलाफ लिखा लेकिन उसमें एक उच्चाधिकारी का रिश्तेदार इन्वोल्व था इसलिए वह केस अब ड्रॉप कर दिया गया है। मैं अगर असत्य बोलूं तो मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं कभी असत्य नहीं बोलता। मैं बताना चाहता हूं कि ये चीजें हो रही हैं अगर चौकसी ब्यूरो ईमानदारी से इन विभागों के पीछे लगाया जाए, और जो अवैध काम हो रहे हैं, उनका पता लगाया जाए तो सरकार व हरियाणा के लोगों को लाभ होगा। यह पता लगाया जाए कि यह केस क्यों ड्राप हुआ? अगर पांच-पांच करोड़ के घोटाले के केस ड्राप होंगे तो भगवान ही मालिक है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह आपके ध्यान में पानीपत नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव के बारे में लाना चाहता हूं। पानीपत नगर परिषद का चुनाव हुए एक साल हो गया है लेकिन यह समझ में नहीं आता कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा यह कैसा लोकतंत्र है लेकिन हमें इस बात में नहीं जाना चाहिए, लोकतंत्रीय व्यवस्था में जिसके साथ बहुमत हो, उसको बन जाना चाहिए।

श्री कृष्ण लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। कृष्ण पाल गुज्जर जी जो पानीपत नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव के बारे में जो बात कह रहे हैं यह बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद बात है उसके अंदर जो इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुनकर आए थे। मुख्य मंत्री जी ने हमें आदेश दिया था कि दोनों पार्टी मिलकर अपना कैंडिडेट बनाएंगे, हमने भारतीय जनता पार्टी को ऑफर किया था लेकिन ये तय नहीं कर पाए कि उनका कैंडिडेट कौन है इसमें इनकी पार्टी का कसूर है, हमारा कसूर नहीं है

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्ण पाल जी अब आप वाइंड करें। जब आप मंत्री थे, पुन्हाना ब्लॉक समिति की क्या पोजीशन थी, यह भी बता दें।

श्री धीर पाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री कृष्ण पाल पंवार जी यह कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी की और हमारी सरकार की पानीपत नगर परिषद के चुनाव में कोई दखल अंदाजी नहीं थी। हमने भारतीय जनता पार्टी को सारे अधिकार दिये हुये थे।

श्री कृष्ण पाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने कहा है मैं उससे सहमत हूं। हमारी पार्टी किसी भी उम्मीदवार को तय करे यह हमारी पार्टी की मर्जी है लेकिन लोकतंत्र में किसी की मर्जी का उम्मीदवार हो यह नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, नगर परिषद का चुनाव न हो और नगर परिषद विकास के लिए तरस रहा हो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। अगर हमारी पार्टी का उम्मीदवार वहां चुनना था तो यह बात हमारे ऊपर छोड़ देनी चाहिए थी। (विघ्न) इसलिए मैंने ये कुछ सुझाव सरकार को दिये हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि आज विकास के कामों में भेदभाव हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : कृष्णपाल जी आपने 11.43 बजे बोलना शुरू किया था और अब आपको

बोलते हुए एक घंटा होने वाला है इसलिए आप 12.43 बजे तक पांच मिनट में कंक्लूड करें।

श्री कृष्ण पाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि विकास के कामों में भेदभाव हो रहा है मुझे मालूम है कि इन सब बातों को बोलने के बाद मेरे हल्के में जो विकास का काम हो रहा है वह और ज्यादा होने लगेगा। यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी की मुझ पर पूरी कृपा है और मेरे बोलने के बाद इनकी कृपा और ज्यादा हो जाएगी यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जिस काम के लिए मेरे हल्के मेवला महाराजपुर के लोगों ने मुझको चुनकर भेजा है और उन लोगों की भावनाओं को सरकार के सामने रखना मेरी जिम्मेवारी है और उन बातों पर अमल करना सरकार का काम है। अगर सरकार उन कामों को पूरा करने में कोई कोताही करेगी तो लोकतंत्र में यह ठीक बात नहीं होगी। इसलिए जनभावनाओं को सरकार के सामने रखना हमारा फर्ज है इससे सरकार लोकप्रिय बनती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से और सभी मंत्रियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार राजा विक्रमादित्य के राज में राजा विक्रमादित्य भेष बदल कर अपनी जनता के दु:ख-दर्द सुनने के लिए जाया करते थे उसी प्रकार इन मंत्रियों को भी जनता के बीच में जाना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी को तो मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि इनको तो जनता पहचान लेगी क्योंकि ये अक्सर 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में जनता के बीच में जाते रहते हैं। लेकिन मंत्रियों को कोई नहीं पहचानेगा। जब मंत्री लोग जनता के बीच में ईमानदारी के साथ जायेंगे तो इनको जनभावनाओं के बारे में पता चलेगा। अगर जनता की अनेक भावनायें उनके सामने आयेंगी तो सरकार उनको दूर करने करने का प्रयास करेगी। इसलिए मैंने जो सुझाव सरकार के सामने रखे हैं मुझे आशा है कि सरकार इन सुझावों पर पूरा अमल करेगी। ताकि हमारे हल्के के लोग जो यहां चुनकर भेजते हैं वे हमारे से उम्मीद और भरोसा रखते हैं कि हम उनकी समस्यायें सरकार के सामने रखें। इसलिए मुझे सरकार से आशा है कि वह मेरे सुझावों पर अमल करेगी। इसके साथ ही मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

Shri Karan Singh Dalal : Sir, this member may be declared the man of the day.

सरदार निशान सिंह (टोहाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2001-2002 के बजट के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। 2001-2002 का बजट पूर्णतया कर रहित बजट है, इसमें कोई नए टैक्स नहीं लगाए गए हैं। सारे हरियाणा प्रान्त और पड़ौसी राज्यों में इस बजट की सराहना की गई हैं। मीडिया ने भी इस बजट की सराहना की है और कहा है कि हरियाणा विधान सभा में हरियाण सरकार द्वारा बड़ा संतुलित बजट पेश किया गया है। पिछले डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में इस सरकार को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने पूर्णतया कर रहित बजट प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि शायद ऐसा कोई सरकार नहीं कर पाई होगी। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों गुजरात त्रासदी के बारे में पहले भी जिक्र आया। गुजरात में जो भूकम्प आया उसके कारण काफी नुक्सान हुआ और जितनी जानें गई, उस बारे में हरियाण सरकार ने सराहनीय कार्य किए हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने शिष्टाचार को निभाते हुए गुजरात में अपनी टीमों को भेजा, जिन्होंने लोगों की सेवा की और कई राहत कैम्प लगाए। इस बात की हरियाणा की जनता ने, गुजरात के लोगों ने, दूसरे देशों से आए लोगों ने, समाजसेवी संस्थाओं ने सराहना भी की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब कोई ऐसी त्रासदी आती है या परमात्मा की मार पड़ती है तो हम सभी लोग इकट्ठे होकर उसका सामना करने की कोशिश करते हैं। गुजरात त्रासदी में भी हरियाणा सरकार ने

[सरदार निशान सिंह]

अपने दायित्व को पूरी तरह से निभाने का काम किया है लेकिन मेरे सम्मानित साथी कृष्ण पाल गुर्जर जी इस मामले में भी सरकार की निंदा करने से नहीं चूके। आज सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष के सामने बिजली की समस्या बनी हुई है। बिजली किसान, उद्योगपति और हर वर्ग के लिए अहम मुद्दा बन चुकी है। अभी बिजली के कनैक्शनों का यहां सदन में जिक्र आया था तो मैं कहना चाहूंगा कि चौ० भजनलाल जी की सरकार 1991 से 1996 तक रही, उसके बाद चौ० बंसी लाल जी की सरकार रही, किसी भी सरकार ने बिजली के नए कनैक्शन देने की सोच नहीं रखी और ना ही किसी सरकार ने बिजली के कनैक्शन दिए। लेकिन चौ० ओ३म प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में बनी डेढ़ वर्ष की सरकार ने उन किसानों का हित देखा जिनकी कृषि नीति की बात कृष्ण पाल गुर्जर कर रहे थे। ये अब कृषि को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और ये उस सरकार में शामिल थे उस समय इन्होंने किसानों के हित की बात नहीं की। लेकिन हमारी सरकार ने किसानो के हित को देखते हुए तत्काल स्कीम लागू की और इस स्कीम के तहत हजारों किसानों को ट्यूबवैल कनेक्शन दिए गए। इससे उन किसानों को फायदा हुआ जिनकी खेती बिना पानी के सूख जाती थी और 10-12 साल से कनेक्शन लेने के लिए महकमें में अर्जी दी हुई थी। हमारी सरकार ने तत्काल स्कीम के तहत लगभग 10,000 ट्यूबवैल के कनेक्शन दिए। अभी चौधरी बीरपाल जी ने बताया था कि तत्काल स्कीम के तहत किसान 10,000 रुपये केवल कनेक्शन के लिए और 20,000 रुपये तक एक से चार पोल के हिसाब से कनेक्शन लेने के लिए तैयार था और हमारी सरकार ने दिए भी तथा किसान इससे खुश भी हुआ। किसान बिजली महकमे की मदद करने के लिए भी तैयार हो गया और किसान 25 हॉर्स पावर का ट्रांसफार्मर भी अपने खर्च पर लाने के लिए तैयार हो गया। किसान तो केवल बिजली का कनेक्शन चाहते थे और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो तत्काल स्कीम लागू की वह बहुत लोकप्रिय हुई। इससे किसानों को बहुत लाभ हुआ और कृषि में बढ़ोतरी हुई। इसे देखते हुए मुख्य मंत्री जी ने निर्णय लिया कि एक पोल की बजाए ज्यादा पोलों की स्कीम लागू कर दी जाए और इसमें भी लोगों ने काफी रूचि दिखाई लेकिन सम्मानित साथी श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी को मुझे लगता है कि सिवाय क्रिटीसिजम के कुछ नहीं आता। वे पहले से ही सोच कर बोल रहे होंगे कि उन्हें तो क्रिटीसिजम ही करना है चाहे सरकार अच्छे कार्य ही क्यों न कर रही हो। इन्होंने किसानों के बारे में अपनी राय उस समय क्यों नहीं दी जब ये चौधरी बंसी लाल जी की सरकार में मंत्री थे। उस समय इन्होंने किसानों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? हमारी सरकार जन कल्याणकारी सरकार है और लोगों में लोकप्रिय है। जहां तक मेरे साथी बिजली के बारे में बात कर रहे थे इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने चाहे 8 घंटे बिजली सिंचाई के लिए किसानों को दी है। बिजली की कमी क्यों रही है, उसका कारण भी सभी लोग जानते हैं। सब जानते हैं कि पिछले साल बरसात कम होने के कारण पानी की बहुत दिक्कत रही और पानी की कमी के कारण हाईडल प्रोजैक्ट बिजली कम बना पाये। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने 8 घंटे बिजली सिंचाई के लिये दी और यह रिकार्ड की बात है कि इस बार महकमे के सबसे कम ट्रांसफार्मर जले और किसानों की मोटरें भी बहुत कम मात्रा में जलीं। इसका कारण यही है कि हमारी सरकार ने बिजली की वोल्टेज पूरी दी। पहले की तरह नहीं कि बिजली एक घंटे में तीन-चार बार ट्रिप कर जाए। चाहे घरेलू बिजली हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र को देने वाली बिजली हो या कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली हो, या किसी भी क्षेत्र में दी जाने वाली बिजली हो, हमारी सरकार ने पूरी वोल्टेज के साथ बिजली दी है। ऐसा नहीं हुआ कि बिजली आई और 20 मिनट में चली गई। जहां तक बिजली के बिलों की रिकवरी की बात है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पहली सरकारें बिजली के बिल की

रिकवरी करने के लिए लोगों पर लाठियां या गोलियां चलाती थी जिससे कई किसान मारे जाते थे। हमारे यहां टोहाना में भी ऐसा ही हुआ था। हमारी सरकार 93.58 प्रतिशत बिजली के बिलों की रिकवरी कर चुकी है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई है। लोगों को प्यार से समझाकर हम रिकवरी कर रहे हैं। हमारे मंत्री और विधायक जनता के बीच में जाते हैं और उन्हें समझाते हैं। हमारी सरकार ने उनको समझाया कि आपके बिल अदा करने से प्रदेश को क्या लाभ होगा। इससे बिजली पूरी मिलेगी और इन बिलों से प्राप्त होने वाली राशि से बिजली की जनरेशन बढ़ाने का काम किया जाएगा। सरकार को इसमें कामयाबी भी मिली है और सदन में इस बात को सराहा गया है। पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं पर एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जिससे किसानों के साथ ज्यादती हुई हो। पिछली सरकारों के टाइम में क्या-क्या हुआ और अखबारों में क्या-क्या खबरें आई थीं, इस बात को सभी जानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के रेट बढ़ाने की बातें की गई जिसके ऊपर एक सम्मानित साथी 20 मिनट तक जम कर बोले कि बिजली के रेट बढ़ा दिये गये। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा प्रदेश में बिजली के रेट पड़ोस के बहुत सारे राज्यों से कम हैं। बिना किसी मुद्दे के सदन में चर्चा करें तो कोई भी साथी खड़ा होकर कुछ भी कह सकता है लेकिन गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करनी चाहिए। आज के दिन भी आंकड़े उठा कर देख लो तो हरियाणा प्रान्त में बाकी राज्यों की अपेक्षा बिजली के रेट कम हैं चाहे डोमैस्टिक हो कृषि क्षेत्र में हो या फिर इण्डस्ट्रीज के क्षेत्र में हों। उपाध्यक्ष महेदय, पानी की कमी है इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पानी एक ऐसी चीज है जो भगवान की देन है, पानी को कहीं से ला नहीं सकते। अच्छी बरसात नहीं हुई जिसकी वजह से पानी कम आया। प्राकृतिक आपदा भी रही तो भी हरियाणा ने ऐसे क्रिटिकल माहौल के अन्दर जमकर मुकाबला किया। सिंचाई के लिये पानी का वितरण किया गया है। चाहे सरकार को सख्ती बरतनी पड़ी ताकि कहीं से कोई पानी को तोड़े नहीं और न ही कहीं इसका मिसयूज हो। इस काम के लिये पूरे प्रशासन को चौकस किया गया था। आंकड़े बताते हैं कि पिछली सरकारों के मुकाबले में खरीफ की फसल में कितनी बढ़ोतरी हुई है और कितनी यील्ड है। चाहे धान की बात हो, गेहूं की बात हो या फिर कपास की बात हो या अन्य किसी फसल की बात हो यह सब हरियाणा सरकार की देन है। इसके अलावा केन्द्रीय पूल में भी पहले से ज्यादा अनाज दिया गया जिसकी भूरी-भूरी प्रशंसा माननीय प्रधान मंत्री जी भी कुरुक्षेत्र में करके गये। उन्होंने हमारे मुख्य मंत्री जी की नीतियों की सराहना की है। प्रधान मंत्री जी यह बात भी कह कर गये कि हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री ही ऐसे मुख्य मंत्री है जो नदियों के पानी के बटवारे की समस्या को सुलझवा सकते हैं इसलिये हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री इसके लिये पहल करें। बार-बार उन्होंने यह बात की है। वे यह भी कह कर गये हैं कि हरियाणा के मुख्य मंत्री इस मामले में पहल करने के लिये समृद्ध है इसलिये वे बाकी राज्यों की मीटिंग बुलायें जिसमें मैं भी आऊंगा ताकि पानी के इस विवाद का निपटारा हो और हरियाणा को पूरा पानी मिल सके। पता नहीं, गुजर साहब को किसने गाइडैंस दे दी जिसके कारण ये आपना भाषण जोड़-जोड़ कर बोल रहे थे। इनके नेता आदरणीय प्रधान मंत्री तो कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर हरियाणा सरकार के कार्यों की सराहना करके गये जबकि ये विरोध कर रहे हैं। पता नहीं ये झूठ का पुलन्दा कहां से उठा कर ले आये। सारी बातें इनके खिलाफ जाती हैं। पता नहीं, इसके क्या कारण हैं, इनकी अलग सोच है या फिर अपने नेता को नेता नहीं मानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं विकास के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। श्री कृष्ण पाल गुजर ने इस के बारे में यहां जम कर चर्चा की और कहा कि हरियाणा में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। विकास के काम हो नहीं रहे हैं। मैं समझता हूं कि पिछली सरकारों के समय में सड़कों का क्या रूप था जिसके कि हम स्वयं भुगत भोगी

[सरदार निशान सिंह]

हैं। हर गांव, गली और मोहल्ले के मामले में जब हमारे मुख्य मंत्री जी ने देखा कि कितनी बुरी हालत है तो उन्होंने सत्ता संभालते ही चौधरी देवी लाल जी द्वारा दिखाये गये रास्ते पर चल कर हरियाणा प्रदेश के विकास कार्य शुरू किये। गुजर साहब कह रहे थे कि कहीं काम नहीं हो रहा है, एम०एल०ए० की पूछ नहीं है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि पिछली सरकारों के समय में एम०एल०ए० की जो पूछ होती थी उससे कहीं ज्यादा एम०एल०ए० की पूछ इस सरकार में है। पिछली सरकार के दौरान जो विकास के काम ठप्प हो चुके थे या बन्द हो चुके थे उनकी हालत को देखते हुए और लोगों की जरूरत के हिसाब से हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने ''सरकार आपके द्वार'' कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश का भ्रमण करके प्रत्येक हलके में विकास के कार्य कराये हैं। किसी पंच ने, नम्बरदार ने या एम०एल०ए० ने अपने हलके की बात उनके सामने रखी तो उन्होंने उसे माना है।

यह भी पहला मौका है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान जो भी घोषणाएं हुई उन घोषणाओं के बारे में टाईम पीरियड फिक्स किया गया। समय की हदबंदी कर दी गयी कि 6 महीने के अन्दर ये विकास कार्य हो जाने चाहिएं। वे सारे के सारे विकास कार्य पूरे हो गए हैं। प्रश्नकाल के दौरान बहुत से साथियों ने कहा था कि मेरे यहां तो 1991 का पत्थर लगा है उस पर कालिख पोत दी गई है। आप सभी को पता है कि पिछली सरकारों के समय में किस तरीके से प्रदेश के अन्दर विकास के कार्य होते थे। उन सरकारों के समय में विकास कार्यों के पत्थर लगा दिए जाते थे और उनकी गिनती की जाती थी। आज की हरियाणा सरकार ने उन प्रथाओं को बदला है। हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी की ये हिदायतें हैं कि मैं जो भी विकास की घोषणाएं करके जा रहा हूं वे सारी घोषणाएं इतने समय में कम्पलीट हो जानी चाहिएं। मैं उसके बाद फिर आऊंगा और फिर विकास कार्यों की घोषणाएं करके जाऊंगा। मैं समझता हूं कि ''सरकार आपके द्वार'' कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने अब तक प्रदेश के 40-50 हलकों का दौरा किया है। उस दौरान आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने यह नहीं देखा कि यह कांग्रेस के विधायक का हलका है या बी०जो०पी० के विधायक का हलका है या यह लोकदल के विधायक का हलका है या यह इन्डिपैंडैंट विधायक का हलका है आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने हर हलके में विकास कार्यों की घोषणा की। वहां का जो जन प्रतिनिधि था चाहे वह गांव का सरपंच था, चाहे वह गांव का नम्बरदार था चाहे वह नागरपालिका का आदमी था चाहे वह जिला परिषद का मैम्बर था चाहे वह पंचायत समिति का मैम्बर था और चाहे वह ग्राम विकास समिति का मैम्बर था। सबको अपने साथ बैठा कर उनकी मांगों के अनुसार हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने विकास कार्यों की घोषणाएं कीं। हमारे कुछ साथी सड़कों की बात कर रहे थे। हरियाणा प्रान्त के अन्दर जो सड़क जरूर हालत में थी उन सभी सड़कों पर कारपैट बिछाया गया है ताकि सड़कें चलने के लायक हों। इसके अलावा गांवों के अन्दर आम विकास के कार्य, चाहे वह बैकवर्ड भाईयों की चौपाल बनाने का हो, चाहे वह हरिजन भाईयों की चौपाल बनाने का हो, चाहे गांव के जोहड़ की रिटेनिंग वाल बनाने का हो। सभी कार्य बहुत तेजी से साथ किए गए हैं। मुझे रोड़ी हलके के चुनाव के दौरान वहां पर जाने का मौका मिला था। वहां का मैं एक दिन चक्कर लगा कर आया था। वहां पर लोग कह रहे थे कि सरकार ने यह जो जोहड़ के चारों तरफ रिटेनिंग वाल बनाई है अगर इसमें कोई भैंस धंस गई तो उसको कैसे निकालेंगे। गांव के लोग आपस में इस तरह का मजाक कर रहे थे। जैसे स्वीमिंग पूल होता है उस तरीके से पशुओं के लिए जोहड़ के चारों तरफ रिटेनिंग वाल बना करके जोहड़ के पानी को स्वच्छ रखने के लिए ऐसा किया गया। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) गांवों के अन्दर चाहे स्कूलों के कमरे बनाने का काम हो चाहे पंचायत घर बनाने का काम हो, चाहे गांव

का गलियाँ पक्की करने का काम हो और चाहे गांव के नाले पक्के करने का काम हो माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद वहां जा करके इन विकास कार्यों को शुरू करवाया है। अध्यक्ष महोदय, चाहे आप इस बारे में पता करवाने के लिए पांच स्वच्छ छवि के मैम्बर्ज़ की एक कमेटी बना दें और पता करें पिछले डेढ़ साल के दौरान हरियाणा प्रदेश की जनता की कायाकल्प हुई है या नहीं। मैं कहता हूं कि पिछले डेढ़ साल के दौरान हरियाणा प्रदेश के लोगों की कायाकल्प हुई है इतने विकास के कार्य किसी भी सरकार के समय नहीं हुए जितने इस सरकार के समय में हुए हैं। यह एक रिकार्ड की बात है। अध्यक्ष महोदय, ग्राम विकास समितियों के बारे में भी क्रिटिसिजम किया गया। जहां तक ग्राम विकास समिति की बात है हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने चौधरी देवी लाल जी की इच्छानुसार इस बात को देखा है कि हरियाणा के ग्राम वासियों का हरियाणा के आम आदमी का सरकार में हिस्सा होना चाहिए ताकि लोग यह महसूस करें कि वे भी सरकार के एक हिस्सेदार व्यक्ति हैं और वह यह महसूस करें कि उसे सरकार एक जिम्मेदार व्यक्ति मानती है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने हर वर्ग से एक एक व्यक्ति ले करके ग्राम विकास समितियां बनाई हैं, चाहे वह हरिजन बिरादरी का मैम्बर है, चाहे वह बैकवर्ड बिरादरी का मैम्बर हो, चाहे वह भूतपूर्व सैनिक मैम्बर हो और चाहे वह महिला मैम्बर हो, उनको ग्राम विकास समितियों में भागीदार बनाया है। उसमें सरपंच को इग्नोर नहीं किया गया है। सरपंच उस ग्राम विकास समिति का चेयरमैन होगा उसको साथ ले करके, चाहे कोई भी मैम्बर किसी पार्टी का है उसको ग्राम विकास समिति का भागीदार बनाया है। इस तरह से ग्राम विकास समिति बनाने से गांवों का विकास होगा। यह नहीं होगा कि कोई गलत आदत का आधिकारी अपनी मर्जी से विकास का पैसा बीच में खा जाए। ऐसा करके सरकार ने लोगों में विश्वास दिलाने की बात की है। अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा प्रदेश में 36 बिरादरी के लोग यह महसूस करेंगे कि सरकार ने ग्राम समितियां बना कर उनको मान सम्मान दिया है। लोग यह महसूस करेंगे कि उनके गांवों में जो विकास के कार्य होंगे वह उनकी देख रेख में होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इतनी बढ़िया सोच शायद पहले किसी भी सरकार की नहीं रही होगी। मैं मान कर चलता हूं कि पिछले डेढ़ साल के अर्से के दौरान से जिस तरीके से सरकार ने प्रदेश में विकास के कार्य किए हैं वह पहले शायद किसी दूसरी पार्टी की सरकार ने नहीं किए होंगे। जहां तक कृषि की बात है, खेती के मामले में पिछले डेढ़ साल के दौरान में भगवान की मार पड़ी है क्योंकि बरसात नहीं हुई लेकिन फिर भी सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को बहुत सहायता मिली है।

13.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, यदि बरसात ठीक समय पर ठीक हो जाये तो उससे बिजली की कमी काफी हद तक दूर हो सकती है। हमारे यहां पर काफी खराब टाईम रहा है जब बारिश न होने की वजह से बिजली की मांग अधिक बढ़ गई थी। ऐसे क्रिटिकल समय में सरकार ने उचित कदम उठाते हुए इस समस्या का समाधान किया और किसानों को पूरी बिजली देने की भरपूर कोशिश की। ऐसा काम एक अच्छे नेता के नेतृत्व में ही हो सकता था। वह अच्छा नेतृत्व हमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के रूप में मिला है। हमारे यहां पर अच्छी फसल पैदा हुई जिस कारण हमने केन्द्रीय पूल में पहले से अधिक उपज दी। हमारे यहां पर सरकार की अच्छी नीति के कारण धौरी और गेहूं की दोनों फसलें बहुत अधिक पैदा हुईं। फसल इतनी अधिक आई कि देश के जो मौजूदा भण्डार हैं उनमें उनको रखने को जगह नहीं मिली जिसके कारण अतिरिक्त शैड बनाकर फसल को रखा गया ताकि किसान की मेहनत से तैयार की गई फसल खराब न हो। इनकी पैदावार अधिक होने के कारण हमारे नेता ने किसान का ध्यान इन फसलों से डाईवर्ट करते हुए कोआप्रेटीव शूगर मिल की तरफ करते हुए, गन्ने की फसल को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया है। इसी बात

[सरदार निशान सिंह]

को देखते हुए हमारी जिन शूगर मिल्ज, जिनकी माली हालत ठीक नहीं थी उनकी आर्थिक मदद की ताकि वे किसानों की गन्ने की फसल का मूल्य ठीक समय पर दे सकें। किसानों की इस फसल को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने गन्ने का भाव सारे भारतवर्ष में हरियाणा के किसानों को अधिक दिया ताकि किसान भाई अधिक से अधिक गन्ने की फसल की बिजाई करें और अब पहले कि अपेक्षा किसान भाई गन्ने की फसल की बिजाई अधिक कर रहे हैं। गन्ने की फसल एक ऐसी फसल है जो सूखे को भी सहन कर लेती है और अधिक बरसात आ जावे तो उसको भी सहन कर लेती है। हम समय समय पर मुख्य मंत्री जी से मिलते रहते हैं और हमने मुख्य मंत्री जी को सुझाव दिया कि तिलहन, दलहन, फलोरी कल्चरल व बागवानी की तरफ भी किसानों का ध्यान डाईवर्ट किया जाये। मुख्य मंत्री जी ने इस बात को माना है कि इस तरफ भी हम पूरा ध्यान देंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री जी ने किसानों का एक डेलीगेशन कृषि मंत्री जी की अगुवाई में इज़राईल भेजा था। उस डेलीगेशन में मुझे भी जाने का मौका मिला था। हमारे मुख्य मंत्री जी की सोच थी कि किसानों को इज़राईल की खेती के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके इसलिए यह डेलीगेशन वहां पर भेजा गया था। इसको वहां पर भेजने का कारण यह था कि इज़राईल का वातावरण हमारे हरियाणा की तरह का है। जब वह एक छोटा सा देश खेती की उपज करने में सारे देशों में सबसे आगे है तो हमें भी उसका अनुसरण करना चाहिए और जो तरीके फसल उगाने के उन्होंने एडोप्ट किए हुए हैं, हमें भी उन्हे एडोप्ट करना चाहिए ताकि हमारे किसान भी अधिक से अधिक फसल पैदा कर सकें। जब हम इज़राईल गए तो वहां पर हमारा बहुत बिजी शिड्यूल था। हमारा यह शिडयूल प्रातः 8 बजे शुरू होता था और रात 8 बजे खत्म होता था। यह बिजी शिड्यूल इसलिए बनाया गया था ताकि जो किसान लोग साथ गए थे वे उसका पूरा सदुपयोग कर सकें यानि पूरी जानकारी हासिल कर सकें। हमारे साथ जो अधिकारी गए थे उनको मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि वे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट इस बारे में दें और जो किसान भाई साथ गए थे उनकी राय लेकर दें ताकि हम उसको एडोप्ट करके उस पर आगे की कार्यवाही कर सकें और हमारे किसान भाई खुशहाल हो सकें। हरियाणा में पानी की काफी दिक्कत है। यहां पर काफी गहराई के बाद पानी मिलता है। माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच कृषि को बढ़ावा देने की है। अध्यक्ष महोदय, गवर्नरज् एड्रैस पर भी बहस में भाग लेते हुए साथियों ने कहा हमारे यहां पर धान की फसल अधिक हुई है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने किसानों की धान की पूरी खरीद की। सभी एजेंसियों ने चाहे वह एफ०सी०आई० थी या हरियाणा की कोई और एजेंसी थी, खरीद की। इसी प्रकार से व्यापारियों को भी धान की खरीद करने का पूरा मौका दिया गया ताकि वे भी उचित मूल्य पर किसानों की फसल खरीद कर सकें और उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत न आये। पिछले दिनों केन्द्रीय फूड एण्ड सप्लाई मिनिस्टर हमारे मुख्यमंत्री जी की कोठी पर आये और घोषणा करके गए कि जो व्यापारी यानि राईस शैलर सरकारी धान की सैलिंग करते थे उनको पहले एक क्विंटल के पीछे 67 किलो चावल वापस करना पड़ता था लेकिन अब उन्होंने उनको यानि शैलरों को 67 किलो चावल वापस करने की बजाये 64 किलो चावल वापस करना होगा। इससे सारे राईस शैलर व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ी है क्योंकि इससे उनको लाखों का फायदा होगा।

हमने देखा है पंजाब राज्य का धान, उत्तर प्रदेश का धान, राजस्थान का धान तथा दिल्ली का धान हमारे राज्य में आ रहा है। किसान अपना अनाज बेचने के लिए वहां ले जाता है जहां खरीद अच्छी हो और मूल्य अच्छा मिले। हमारे प्रांत की तरफ अनाज बिकने के लिए आ रहा था और सरकार को

इसको रोकना पड़ा ताकि हमारे प्रदेश के किसानों के माल की दुर्गति न हो और उसका माल सही तरीके से बिक सके। हमारी सरकार ने अपने किसानों का माल भी खरीदा और पड़ोसी राज्यों के किसानों का माल भी खरीदा और जाहचाही हुई। इतनी बढ़िया प्रोक्योरमैंट हुई कि मैं समझता हूं कि उससे किसान तो खुशहाल हुआ ही है उससे राईस मिल्ज को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। कोई भी साथी जाकर उनसे पूछ सकता है। यहां पर सदन के अन्दर सम्मानित साथी बैठे हैं और कुछ साथियों का राईस मिल्ज के साथ ताल्लुक भी होगा और कुछ साथी इस ट्रेड से जुड़े हुए भी होंगे वे उनसे पता कर सकते हैं कि सरकार की नीतियों की वजह से किसान कितना खुशहाल हुआ है और राईस मिल्ज को कितना मुनाफा हुआ है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि वित्तमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें हमारी सरकार की जो पिछले डेढ़ साल से नीति रही है उसके द्वारा वह पिछले 9 सालों की जो बेकायादगियां थीं उन सबका सामना किया। अध्यक्ष महोदय, बिजली का उत्पादन बढ़ाने की बात कई बार यहां पर चलती है। माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं देखता हूं तो मैंने नोटिस किया है कि कोई भी मुख्य मंत्री किसी भी प्रांत का मुख्य मंत्री हो, इतना ज्यादा काम नहीं करते। किसी के भी इतने वर्किंग ऑवर्ज नहीं रहे हैं। रात को एक-एक बजे तक अधिकारियों के साथ मीटिंगे करते हैं। दिल्ली जाकर केन्द्र सरकार से निवेदन करते हैं कि हरियाणा की वे मदद करें ताकि हरियाणा में बिजली का उत्पादन बढ़े। अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों की बात नहीं करता। आंकड़े सब के सामने सभी की टेबल्ज पर पड़े हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति क्या है। सरकार की नीति इतनी बढ़िया रही है लेकिन जिसने क्रिटिसिज्म करना है तो उसने क्रिटिसिज्म ही करना है। लॉबी में जाकर के और साथियों से बात करके इन्होंने कहा होगा कि हम मेजें थपथपाएंगे, गुरजर साहब आप दो-चार बातें कह देना। अध्यक्ष महोदय, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज जनता जो कह रही है यह सबके सामने है। अखबार में कोई बात लिखवा कर कोई साथी यह कहे कि अखबार ने लिखा है, इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह जो गुजरात त्रासदी की बात है वहां पर बहुत बढ़िया ढंग से कार्य किया गया और बड़ी सेवा भावना से किया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जनता का आह्वान किया और जनता ने पूरा सहयोग भी दिया। जनता का पैसा था उसका पूरा उपयोग हुआ और बढ़िया तरीके से हुआ। मैं यह बात किसी मान के साथ नहीं कह रहा हूं। ऐसे दुःख के समय में मदद करना हर व्यक्ति का फर्ज है। हमारी सरकार ने और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बढ़िया तरीके से काम किया है और उनका काम करने का ढंग बहुत ही बढ़िया था। आज कई बार विकास की बात चलती है । खेती की बात, सिर्फ बिजली की बात ही विकास नहीं है। आज विकास को अपनो लोगों तक पहुंचाना और उसमें उनकी भागीदारी बनाने की तरफ भी हमारी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। जिला परिषद्, पंचायत समितियां, पंचायतें और नगर पालिकाएं जो हमारे चार स्तंभ हैं। शहरी और देहाती विकास में उन लोगों को विकास में हिस्सेदार बनाने की तथा उनमें कॉफिडेंस पैदा करने की कोशिश की गई है। उनको पावर और ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी व सरकार को इस कदम से लोगों में विश्वास पैदा हुआ है और सरकार की इन नीतियों से गांव और शहर का ज्यादा विकास होगा। (विघ्न)। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जहां हम विकास की बात करते हैं वहीं हम चाहते हैं कि नैशनल स्तर पर और इंटरनैशनल स्तर पर अपना प्रदेश नाम रोशन करें। किसी भी क्षेत्र की बात हो यह प्रयास हमें करने चाहिएं। पिछले सालों में हमारा स्पोर्ट्स बहुत पीछे चला गया है। चाहे वह हरियाणा ओलम्पिक संघ की बात हो चाहे सरकार की नीति की बात हो, हरियाणा के लोग अपने मातृ खेलों को भी भूल चुके थे। कबड्डी जैसा खेल जो हमारे बच्चे आम खेलते थे उसको भी छोड़कर हमारे बच्चे गलियों में क्रिकेट खेलने लग गए। आज हमारी सरकार ने ऐसी खेल पॉलिसी

[सरदार निशान सिंह]

बनाने की कोशिश की है जिससे प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके। यहीं से शिक्षा का विकास शुरू होता है और वहीं से बच्चा सीख कर बाहर आता है। हरियाणा ओलम्पिक संघ के तहत सारे हरियाणा प्रदेश के लोगों में इस खेल को पुनर्जीवित किया गया है। यह खेल पहले बिल्कुल मर चुका था। हरियाणा ओलम्पिक संघ को श्री अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोबारा जीवित करने की कोशिश की है। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, स्कूल स्तर पर स्पोर्ट्स टूर्नामैंट कराए गए हैं और लोग जिन खेलों को भूल चुके थे उनमें फिर से उनकी रुचि बढ़ी है। पिछली सरकार ने लोगों को ड्रग्ज, क्राईम तथा नशे की तरफ प्रेरित किया था। आज ये साथी लॉ एण्ड ऑर्डर की बात करते हैं मैं कहता हूं कि लॉ एण्ड आर्डर को बिगाड़ने का काम किया किसने था? इस सरकार और मानीय मुख्य मंत्री जी ने इसके सुधार का काम किया है। बिगाड़ने का काम तो इन साथियों ने किया था। युवकों को ड्रग्ज में लगाकर क्राईम को बढ़ावा दिया था इन लोगों ने लेकिन हमारी सरकार ने बच्चों को यह बताया है कि आपका काम पढ़ना है आपका काम खेलना है ताकि वे बच्चे सही क्षेत्र में अपनी योग्यता दिखा सकें और वे नैशनल और इंटरनैशनल लैवल पर खेलने के लिए आएं। जैसाकि हरियाणा के लिए यह बात मशहूर है कि यहां के बच्चों को दूध दहीं खाने को मिलता है उसको सच्चा साबित करने के लिए मुख्य मंत्री जी ने ऐसी पालिसी बनाई है कि यहां के बच्चे कहीं पर भी जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां पर ट्रांस्पोर्ट के बारे में बातें की जा रही थीं तो हमारी सरकार ने इस तरफ भी बहुत अच्छा काम किया है। हमारी सरकार के आने से पहले परिवहन की बसों की क्या हालत थी। कोई भी बस ठीक तरह से चलती नहीं थी और उनके भी शीशे टूटे हुए थे। पिछली सरकार ने जो प्राईवेट बसों के रूट दिए थे उनकी पालिसी ऐसी बना दी थी कि सभी प्राईवेट बसों वाले अपनी बसों को बेचने लग गए थे। उनका बहुत ही बुरा हाल हो गया था। हमारी सरकार आने के बाद परिवहन की बसों की हालत में बहुत सुधार आया है। इसका एक उदाहरण यह है कि हमारी सरकार ने 450 नई बसें खरीदी हैं और वे आज सड़कों पर चल रही हैं। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं अपने एरिये के बारे में भी कुछ बातें कहना चाहूँगा। टोहाना शहर की 40-50 हजार की आबादी है। जब मुझे वहां से लोगों ने नुमायदा चुन कर यहां पर भेजा तो मैंने देखा कि वहां पर चाहे गलियों की नालों की, सीवरेज की, ड्रिंकिंग वाटर की और सटोर्म वाटर की बात हो, सभी जर्जर हालत में थे। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के दो गांवों में दो बार "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उसके बाद ही वहां पर विकास का काम हुआ है जोकि पिछले 40 सालों में नहीं हुआ था। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे गलियों, सड़कों, सीवरेज, ड्रिंकिंग वाटर या सटोर्म वाटर की समस्या हो उनको दूर करने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, रामनगर में सीवरेज का पानी भर जाता है और वह पानी लोगों के घरों में भी भर जाता है। मुख्यमंत्री जी कृपा करके इस तरफ भी ध्यान दें और इस समस्या को दूर करने की कृपा करें। इसी के साथ मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूँगा कि यह बजट बहुत ही अच्छा है और इस सरकार के द्वारा किए गए कामों की हमें सराहना करनी चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा इस बजट को पास करने के पक्ष में समर्थन दें। धन्यवाद।

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कल हाउस में अपना दूसरा बजट पेश किया है। इस बजट में उन्होंने 54 प्वार्यट कुछ करोड़ का डैफिशिट दिखाते हूए टैक्स फ्री कहकर बजट पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, आप इस बजट को देखेंगे तो पाएंगे कि 14 हजार करोड़ रुपये आज तक इस सरकार को कर्ज के रूप में देने हैं और इस साल में जब बजट खत्म करेंगे तो उस समय 16-17 हजार करोड़ रुपये हरियाणा सरकार को कर्ज देना पड़ेगा। वित्त मंत्री जी

ने जो बजट टैक्स फ्री के नाम से पेश किया उसमें टोटल 288 करोड़ रुपये का घाटा एवं कर्जा 17 हजार करोड़ रुपये का हो गया है। जबकि ये टैक्स फ्री बजट की तालियां पीटते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने कल हमारे आब्जैक्शन पर अपनी रूलिंग दे दी कि बजट की कोई लीकेज नहीं हुई है। हमने आपकी रूलिंग मान भी ली। आपकी रूलिंग फाइनल है। लेकिन मैं एक बात वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि यह जो बजट की कापियाँ सील करके रखी गयी थीं फिर इसका क्या फायदा है। कल ही आपकी इजाजत से ये बड़े-बड़े बंडल खोलकर हमें दिए गए थे। अगर आप मानते हैं कि टैक्स फ्री बजट कहना कोई लीकेज नहीं है तो फिर इसमें ऐसी कौन सी सीक्रेट चीज थी जिसकी वजह से यह बंद करके रखे गये थे। वित्त मंत्री जी यह बताने का जरूर प्रयास करें। अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग टैक्स का क्या मतलब समझते हैं। मैं तो इस बारे में यह समझ पाया हूँ कि प्रदेश के नागरिक पर किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से बोझा डाला जाये वह टैक्स होगा। चाहे वह सेल्ज टैक्स के रूप में हो, एक्साइज ड्यूटी के रूप में हो या चाहे रेल या बसिज के किराये बढ़ाने के रूप में हो, जिस रूप में भी सरकार की तरफ से जनता पर बोझ पड़े वह टैक्स ही कहलाता है। मैं अपने साथी कृष्ण पाल गुर्जर को भी बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार के सहयोगी होते हुए भी उन्होंने थोड़ा सा सरकार को चेताने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात याद आती है हमारे जींद में एक डॉ० साहब जो कि बहुत बढ़िया आदमी हैं, अपने मरीजों द्वारा यह पूछने पर कि खान-पान का क्या परहेज है, यह जरूर कहते हैं कि भाई मुझे छोड़कर तेरी जो भी मर्जी हो वह खा लेना। अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूँ कि इस बजट में वित्त मंत्री जी ने मुख्य मंत्री जी को जरूर बचाने की कोशिश की है। इनके अलावा बाकी कोई हरियाणा का नागरिक नहीं बचा है जिस पर बोझ न पड़ा हो। मैं यह बात चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। हरियाणा का प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसान हो, कर्मचारी हो, छोटा व्यापारी हो, छोटा उद्योगपति हो या बड़ा उद्योगपति हो यानी कोई भी ऐसा नहीं बचा है जिस पर सरकार के द्वारा टैक्स का बोझा न लादा गया हो। वित्त मंत्री जी ने जो पिछला बजट पेश किया था उसमें भी यही बात थी कि वह टैक्स फ्री बजट होगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ती है कि शायद हरियाणा के इतिहास में जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक जितने भी बजट पेश हुए हैं, उनमें ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा इस बजट में हुआ है। मैं तो थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मैं इनको यह समझता था कि ये ही केवल फाईनांस को संभाल सकते हैं। यह जो ऐनुअल प्लान बजट के अन्दर पेश की उसमें 2530 करोड़ रुपये के ऐनुअल प्लान पर बजट पेश किया था। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बड़े नंबर बनाए। पिछली योजना 1811 करोड़ की थी उसमें 39.07 परसैंट की इन्क्रीज कर दी और बजट टैक्स फ्री-ये तो जादू हो गया। 1800 करोड़ की योजना 2500 करोड़ की योजना बन जाए और कोई टैक्स न लगे हरियाणा के ऊपर, ऐसा वित्त मंत्री तो बहुत अच्छा है। अध्यक्ष महोदय ये मुझे नहीं समझ आता। सरकार योजना पर 40 परसैंट इन्क्रीज कर दे और खर्च भी न घटाए और टैक्स भी न लगाए तो फिर रेवेन्यू कहां से आए? बजट बना तो दिया, फिगर भी दे दी इसमें 54.6 परसैंट पैसे इन्होंने सिर्फ चार चीजों पर अलॉट किए थे। वित्त मंत्री जी ने ये पैसा पॉवर, इरीगेशन और रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए दिए। कुल 2530 करोड़ की योजना थी, रेवेन्यू आया नहीं, खर्च घटा नहीं, जनाजा निकाल दिया। वह प्लान 1815 करोड़ पर रह गई। ऐसा हरियाणा के इतिहास में नहीं मिलेगा कि 2530 करोड़ की योजना 30 से 35 परसैंट कम हो जाए और 1815 करोड़ की रह जाए। अब इन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें 2150 करोड़ की योजना रखी है। इस पर विश्वास कौन करेगा? इसमें रिसोर्सिज के बारे में ढंग से नहीं बताया और टैक्स फ्री बजट कह दिया। अब की लगता है कि 2150 करोड़ की योजना कहीं 1500 करोड़ पर न पहुंच जाए। क्यों लोगों को

[श्री मांगे राम गुप्ता]

मिसगाइड करते हैं? मैं समझता हूँ कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की नीति सामने आ जाती है कि सरकार पावर पर, इरीगेशन पर या ट्रांसपोर्ट पर क्या चाहती है। इन्होंने गवर्नर ऐड्रस में पूरी रूपरेखा तैयार कर दी थी। बजट जो पेश होता है बजट की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। बजट स्पीच से पूरा नहीं हो सकता उसके अंदर साधन चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, फंड चाहिए। सभी चाहते हैं कि 24 घंटे किसान को बिजली मिले, बढ़िया सड़कें हों, स्कूल गांव-गांव में हों, सारे यही चाहते हैं लेकिन सारी बात तो साधन की है। आज मैं सुन रहा था एजुकेशन मिनिस्टर बार-बार कह रहे थे कि नॉर्म्स पूरे करेंगे और अगर बजट में प्रोविजन होगा तो यह काम कर देंगे। यह ठीक कह रहे हैं नार्म्स तो पूरे कर देंगे लेकिन जब तक बजट नहीं होगा, फंडस् नहीं होंगे, कोई भी योजना कागजों में तो बना दोगे लेकिन सिरे नहीं चढ़ सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह बजट जो पेश किया गया है यह बिल्कुल कोरा ढकोसला है। मुझे एक बात बड़े दुख के साथ कहनी पड़ती है कि वित्त मंत्री जी ने विकास के गीत इस बजट में गाये हैं कि इस सरकार ने बड़ा भारी विकास किया है। पिछले बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि इरीगेशन, रोड्ज और ट्रांसपोर्ट पर सरकार 64.5 करोड़ रुपये खर्च कर रही है और इस साल के लिये इन तीनों हैडज में सिर्फ 54.6 करोड़ रुपये रखे हैं और कह रहे हैं कि विकास में प्रगति हुई है। माननीय वित्त मंत्री जी बता दें कि इसमें प्रगति हुई है या डिक्रिज हुई है। यह सरकार जनता को बताये कि टैक्स लगाने का क्या तरीका है। अध्यक्ष महोदय, सरकार का यह तरीका है कि पहले तो सेल्ज टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा कर लेती है जब सरकार के पास रेवेन्यू आ जाता है तो उस रेवेन्यू को अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को अलाट कर दिया जाता है। जैसाकि माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि पिछले साल नैशनल लेवल पर टैक्सिज के एकीकरण के लिए यह फैसला किया गया था कि सभी प्रदेशों में टैक्स की दर एक समान होगी किसी प्रदेश में यह दर ऊँची या नीची नहीं होगी। उस फैसले का फायदा माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां पर टैक्स फ्री बजट पेश करके उठाया। क्योंकि इन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि टैक्सिज का एकीकरण करने से हमारी सरकार को 75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फायदा हुआ है। क्योंकि जो 8 प्रतिशत टैक्स था वह दस प्रतिशत कर दिया और जो दस प्रतिशत था वह 12 प्रतिशत कर दिया गया इसलिए सरकार का 75 करोड़ रुपये टैक्स का बढ़ गया। हर डिपार्टमैंट को अपने लेवल पर टैक्स लगाने की छूट दे दी और इस तरह से टैक्स कलैक्शन का नया तरीका निकाल लिया। जैसा कि श्री कृष्ण पाल जी बिजली के बारे में कह रहे थे कि इस सरकार ने बिजली के रेट जितने बढ़ाये है इतने ऊंचे रेट तो किसी सरकार ने नहीं बढ़ाये। छोटे से छोटा कंज्यूमर चाहे वह डोमैस्टिक कंज्यूमर हो, चाहे धोबी, नाई, तेली या छोटे से छोटा दुकानदार के रूप में हो या छोटा उद्योगपति हो, जैसे किसी ने चक्की लगा रखी हो या किसी ने आरा लगा रखा हो या कोई छोटा उद्योगपति हो या बड़ा उद्योगपति हो, इनमें से कोई भी बिजली की मार से नहीं बचा। इसके बाद अब एक नया कर लोकल एरिया डिवैलपमेंट टैक्स और लगा दिया है। उसके बाद हलवाइयों पर टैक्स लगा दिया जब हलवाइयों ने दुकानें बंद करने के लिए कहा तो फिर शोर मचाने लग गये कि दुकानें बंद मत करो, बस दस प्रतिशत के हिसाब से टैक्स दे दो या नौ हजार रुपये भट्ठी के हिसाब से टैक्स दो। अब आप किस-किस के घर में जाकर भट्ठी देखते फिरोगे (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया

जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है सदन का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : मांगे राम जी आप जल्दी कंक्ल्यूड करें।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपने श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को पूरा एक घण्टा बोलने का समय दिया है जबकि उनकी पार्टी के केवल 6 सदस्य हैं परन्तु हमारी पार्टी के तो 21 सदस्य हैं इसलिए हमें ज्यादा समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मांगे राम जी जब आपका नाम बोला गया तब आप सदन में मौजूद नहीं थे। आप सदन से वाक आऊट कर गये थे।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, वाक आऊट करना मेरा अधिकार है मैंने कोई इललीगल काम नहीं किया। मैं सदन से बाहर नहीं गया था मैं इस सदन के अन्दर ही था।

श्री अध्यक्ष : जब आप अपनी चेयर पर नहीं बैठे हों तो किस का नाम पुकारें।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। बाकी बातों पर तो मैं बाद में जवाब दूंगा लेकिन जहां तक इन्होंने व्यवस्था की बात की है। अपोजीशन का आदमी गवर्नरज ऐड्रस पर और बजट पर बोलते हैं। गवर्नरज ऐड्रस पर जहां तक मांगे राम जी को पता है कि रूलिंग पार्टी का आदमी ही शुरू करता है अपोजीशन का नहीं करता है क्योंकि वह मूव करता है उसके बाद एक आदमी सैकिण्ड करता है उसके बाद फिर अपोजीशन बोलती है। दूसरी बात जहां तक बजट की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यह हमेशा से ट्रैडीशन रही है कि अपोजीशन का लीडर या लीडर द्वारा नोमीनेटिड पार्टी का कोई भी व्यक्ति बोलता है। अध्यक्ष महोदय, क्या हाउस की कार्यवाही को सस्पैंड किया जा सकता है, यदि अपोजीशन न हो? गुप्ता जी जब आपने वाक आउट किया उसके बाद सदन की टेबल पर पेपर ले हुए। अगर आप अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहते हैं तो आपने वाक आउट क्यों किया दैट वाज ए सिम्बोलिक वाक आउट। अगर आप वाक आउट करके उसी वक्त आ जाते और बैंचिंज पर बैठे होते तो हम चाहते थे कि यह आपसे शुरू किया जाता। विवश होकर हमें ट्रैजरी बैंचिंज से शुरू करना पड़ा। विधान सभा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि अपोजीशन अपनी भूमिका निभाने में फेल हो गई हो। सारे बैंचिंज खाली पड़े थे। बजट पर बहस शुरू होने पर ट्रेजरी के सारे लोग उपस्थित थे लेकिन अपोजीशन का कोई नहीं था। अगर कोई होता तो हमें खुशी होती, अगर ये शुरू करते। ये अपनी जिम्मेवारी को निभाते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि हमें बुलाया नहीं गया। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हम इनको अच्छी तरह समझते हैं, ये क्या कहते हैं और क्या करते हैं। हम इनसे पहले हाउस में आना शुरू हुये थे। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : गुप्ता जी, आप पैदा भी हमसे पहले के हुए हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं टैक्स की बात कर रहा था। इस सरकार ने राईस शैलर्स पर 65000 रुपये सालाना टैक्स बजट से पहले ही अनाउंस कर दिया है और बजट में कह दिया

[श्री मांगे राम गुप्ता]

कि हम टैक्स नहीं लगाएंगे। हर राईस शैलर्स जो सेला चावल बनाते हैं उन पर 65000 रुपये सालाना टैक्स लागू कर दिया। भाई निशान सिंह जी, जो बैठे नहीं हैं वे इस बारे में कह रहे थे कि राईस शैलर्स खुश हैं।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने ये 65000 रुपये किस चीज पर लगा दिए हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, 5000 रुपये तो पोल्यूशन पर लगा दिए गए हैं।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, पोल्यूशन के लिए जो लगाया है, वह टैक्स नहीं है (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, टैक्स किसी भी रूप में लगाया जाए लेकिन है तो आदमी पर बोझ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, 1.30 बज गए हैं, सभी ओफिसर्ज, प्रैस के लोग खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अब छुट्टी करें।

श्री अध्यक्ष : सिर्फ 15 मिनट की बात है। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी विपक्ष के नेता ने कहा कि बीच में बोलने से लय टूट जाती है। हम चाहते हैं कि आपके सुझाव आएं, हम लय नहीं तोड़ना चाहते हैं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, लंच का टाइम हो गया है।

प्रो० सम्पत सिंह : गुप्ता जी अच्छा बोल रहे हैं इसलिए उनकी लय न टूटे, उनके सुझाव आने दो। भजन लाल जी, आप बीच में क्यों टोक रहे हैं। ये बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं इनके सुझाव आने दें नहीं तो हम इनके सुझावों से वंचित रह जाएंगे।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जो प्रोग्राम दिया गया है उसमें 1-30 से 2-00 लंच के लिए ब्रेक है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि गुप्ता जी की लय न टूटे ताकि ये हमें अच्छे सुझाव दें सकें क्योंकि ये काफी समय तक फाइनैंस मिनिस्टर रह चुके हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमने आपसे यह कहा था कि आप डबल सिटिंग करें। सुबह 9-30 से लेकर 1-30 बजे तक और दोपहर 2-00 बजे से लेकर शाम 6-30 बजे तक का समय रखें। यह न हो कि समय 6-30 बजे तक की बजाय बढ़ाकर पूरी रात हाउस चलता रहे जैसा कि चौधरी संपत सिंह जी ने कह दिया कि पब्लिक इंट्रैस्ट में तो पूरी रात बैठना पड़ेगा।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट में सुबह पांच बजे तक भी सदन चलता रहता है। वे लोग भी पब्लिक इंट्रैस्ट में पूरी-पूरी रात बैठते हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट में डबल सिटिंग नहीं होती। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली के रेट बढ़ाने की बात है इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मौजूदा सरकार ने बिजली के रेटों में काफी बढ़ोतरी की है। मौजूदा सरकार जनता और किसानों में कितनी लोकप्रिय है यह बात सब जानते हैं और जहां तक वसूली की बात कर रहे हैं इस बारे में

मैं बताना चाहूँगा कि वसूली उन लोगों से ही हो रही है जो लोग हमेशा पैसे देते हैं। मौजूदा सरकार अगर बिजली के बिलों की रिकवरी करना चाहती है तो उन लोगों से करे जिनको चुनाव के वक्त मौजूदा सरकार कहती थी कि बिजली के बिल मत भरो, हमारी सरकार आने दो उनके बिजली के बिल माफ कर दिए जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमें बतायें कि उन लोगों से कितनी रिकवरी हुई है। ऐसे कई गांव हैं जहां से एक भी पैसा रिकवर नहीं किया गया है।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथी की बात को काटना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने बात ही ऐसी कर दी है। रिकवरी के बारे में माननीय साथी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का प्रश्न लगा था उस समय वे थे नहीं। अगर वे होते, तो गुप्ता जी को भी पता लग जाता कि कितनी रिकवरी हो रही है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहीं था लेकिन मेरा प्रश्न आखिर में लगा था।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि प्रश्न आखिर में लगा था तो उसका जवाब हर सदस्य की टेबल पर सर्कुलेट हुआ था और यदि गुप्ता जी उसे पढ़ते तो ऐसी बात ये नहीं करते और इनको जवाब मिल जाता।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के विधायक चाहे जितने मर्जी प्रश्न दें लेकिन उनमें से एक या दो ही प्रश्न लगते हैं या अगर लगते हैं तो अंत में लगते हैं। पता नहीं आप किस हिसाब से प्रश्न लगाते हैं यह बात हमारी समझ से बाहर है।

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार) : अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी भजन लाल जी को बताना चाहूंगा कि आज के दिन भी पहला प्रश्न कांग्रेस के विधायक का ही लगा था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी प्रोसीजर के हिसाब से प्रश्न लगाये जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड देखकर बतायें कि आज के दिन पहला प्रश्न कौन सी पार्टी के विधायक का लगा था।

श्री अध्यक्ष : रिकार्ड के मुताबिक आज पहला प्रश्न कांग्रेस के विधायक का ही लगा था।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के भाइयों को बताना चाहूंगा कि कल भी प्रश्न काल के दौरान कांग्रेस के विधायकों के कई प्रश्न लगे थे लेकिन इनके विधायक उस समय सदन में नहीं थे। राव दान सिंह जी का प्रश्न लगा था लेकिन ये उस समय हाउस में नहीं थे इसी तरह से दूसरे विधायक भी नहीं थे। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्य सवाल लिखकर दे देते हैं और हाउस में आते नहीं, फिर कहते हैं कि इनके सवाल नहीं लगते। यह तो बड़े गजब की बात है। प्रश्न काल में सवाल रखे हुए हों तो इनको सदन में आना चाहिए। विपक्ष के लोग तो इस बात का इंतजार किया करते हैं कि कब इनके सवाल लगें और वह प्रश्न पूछ सकें। यहां इनके सवाल लगते हैं और ये लोग आते नहीं। (शोर)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, आज पहले चार प्रश्नों में से तीन प्रश्न कांग्रेस पार्टी के हैं। (शोर) ये अगर गैर हाजिर रहें तो इसका क्या ईलाज है। जिनके प्रश्न थे मैं

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

उनके नाम भी बता देता हूँ। पहला प्रश्न डॉ० जय प्रकाश का है, तीसरा प्रश्न श्रीमती अनिता यादव का है और चौथा प्रश्न श्री रघुबीर सिंह कादियान का है। पहले चार प्रश्नों में से तीन प्रश्न कांग्रेस पार्टी के हैं फिर भी इनको दिक्कत है। (विघ्न) कल भी राव नरेन्द्र सिंह का क्वैश्चन आया, दान सिंह का क्वैश्चन आया। अगर कोई सदन में हाजिर न रहे तो हम क्या कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, अब आपको खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए। (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, माफी किस बात की मांगनी चाहिए। (शोर)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आपने ये ऐलीगेशन कैसे लगा दिये। माफी तो आपको मांगनी चाहिए। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये बैठे-बैठे तो कह रहे हैं कि भूल हो गयी।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे कहने का मतलब है जो अहम् सवाल हैं उसको आपने लास्ट में रख दिया। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, भजन लाल जी बैठे-बैठे तो कह रहे थे कि भूल हो गई तो फिर खड़े होकर कह दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, हमारे लिये सभी मैम्बरों के क्वैश्चन अहम् हैं लेकिन जो जैसा प्रश्न लिख कर देगा उसी हिसाब से क्वैश्चन लगते हैं। आपको पता भी है कि अहम् की परिभाषा क्या होती है। (शोर)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी बीच में उठकर बोलें तो हम उन्हें रोक नहीं सकते। मैं आपके माध्यम से टैक्स के बारे में सम्पत सिंह जी के नोटिस में लाना चाहूंगा कि पब्लिक हैल्थ में सीवरेज चार्जिज 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिये। ये चार्जिज इतने ज्यादा बढ़ा दिये कि 100 रुपये से सीधे 1000 रुपये हो गये। इसी तरह वाटर कनैक्शन फीस 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी। इसके अलावा 20 रुपये महीना अलग से देने पड़ते हैं। ये टैक्सिज नहीं है तो क्या चीज है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने ट्रेड टैक्सिज लगा दिये है, उसमें छोटा दुकानदार चाहे वह नाई हो, तेली हो, धोबी हो या और कोई छोटा-मोटा काम करने वाला दुकानदार हो उसके ऊपर 1000 रुपये साल का टैक्स लगा दिया। उससे थोड़ा ऊपर का दुकानदार है तो उसको 1500/- रुपये साल के देने पड़ेंगे। इसी तरह से उससे भी बड़ा दुकानदार हो तो उसे 2500 रुपये साल के देने पड़ेंगे। इसी प्रकार से इन्होंने हाउस टैक्सिज में किया। जैसे इन्होंने ट्रेड टैक्स में तीन तरह के टैक्स रखे हैं। वैसे ही हाउस टैक्स के बारे में भी इन्होंने बड़ी अजीब प्रणाली अपनाई है। पता नहीं किसने इनको सलाह दी है। अब ये सर्वे करा कर देख रहे हैं कि मकान कितने साल पुराना बना हुआ है उसमें छत जो है वह कड़ियों की है या फिर लैंटर डला हुआ है। फर्श बजरी का है या ईंटों का है। अगर घरों में इस तरह से कोई अधिकारी या क्लर्क जाएंगे तो झगड़े होंगे। उसके बाद भी ये मकान का टैक्स लेने के लिए कीमत फैलाएंगे, लगाएंगे, कलैक्टर रेट लगाएंगे, कोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लगाएंगे। इस तरह से तो एम्पलाइज सारा दिन उसी हिसाब-किताब में ही घुसे रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो हाउस टैक्स आज के दिन आलरेडी असैस करके लगाये हुए हैं उनको भी ये पूरी तरह से रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज के दिन लगे हुए हाउस टैक्स कम समझते हैं और वही वसूल नहीं कर पा

रहे हैं तो फिर नयी प्रणाली के तहत तो 10 गुना टैक्स हो जाएंगे। उसे कैसे वसूल कर पाएंगे इस राज में तो मैंने यह देखा है कि टके सेर भाजी, टके सेर खाजा वाली बात है। चाहे बिजली की बात है या हाउस टैक्स की बात हो, जो देना चाहते हैं उनकी गर्दन पर तो छुरी फेरते रहो और उन्हीं लोगों के ऊपर और टैक्स बढ़ा दो। जो अपनी इज्जत के खातिर देना चाहते हैं उनके ऊपर तो और टैक्स बढ़ाये जाओ और जो नहीं देना चाहते हैं उनके लिये तो आप कितने ही बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों ने तो कमा के खाना नहीं और ले के देना नहीं। अध्यक्ष महोदय, 1987 में भी इन्होंने इसी तरह की नीति बनाई थी और सत्यानाश हुआ था। अब भी ये उसी तरह की नीति पर जोर दे रहे हैं। इसलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि लोगों को कमा के खाना सिखायें, लेकर देना सिखायें। यह गलत बात है कि जो लोग टैक्स देना चाहते हैं उनके ऊपर और टैक्स लगाये जाएं। उन लोगों पर पहले तो इतना भारी टैक्स लगायेंगे उसके बाद फिर जुर्माना भी ठोकेंगे।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो सदन का समय पांच मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय पांच मिनट के लिये बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मलबे की बात है वह भी एक अजीब बात कर रहे हैं कि 100 गज पर 1200 रुपये मलबा चार्ज लेंगे, 200 गज पर 1800 रुपये मलबा चार्ज लेंगे और 300 गज पर 4800 रुपये तथा उससे अधिक हो तो 6000 लेंगे। अब अगर कोई आदमी मोटर साइकिल या स्कूटर शहर में लाएगा तो उसको आर०सी० के 100 रुपये देने पड़ेंगे। अगर कोई आदमी कार या जीप शहर में लाएगा तो उसको आर०सी० के 500 रुपये देने पड़ेंगे। यह मैं म्यूनिसिपल कमेटीज की बात बता रहा हूँ। ड्राइविंग लाइसैंस के लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ कि टैक्स से आदमी बचेगा या नहीं बचेगा यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। ऐसे हालात में यह कहने से बात नहीं बनती कि यह बजट टैक्स फ्री बजट है। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जब आपसे अखबार वालों ने पूछा कि आप इस बजट को टैक्स फ्री बजट तो कह रहे हैं अगर आगे जाकर यदि आपको टैक्स लगाने पड़ गए तो आप क्या करेंगे? वित्त मंत्री जी ने कहा कि यह बात वित्त मंत्री के हाथ में थोड़े ही है यो बैठा मुख्य मंत्री यह अगर * * * पकड़ कर कहेगा तो टैक्स लगाना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो शब्द इस्तेमाल किया है वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि अगर कोई नैचुरल कलैमिटी आ जाए तो उसके लिए टैक्स लगा सकते हैं। यह नहीं कि नार्मल हालात में भी यह कहें कि कल को क्या पता क्या कुछ करना पड़ जाए। फिर आप टैक्स फ्री बजट की बात क्यों कर रहे हैं? आपने टैक्स के बगैर

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री मांगे राम गुप्ता]

तो प्रदेश में कोई आदमी छोड़ा ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी बहुत काबिल हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि यह जो बजट की कापी है, यह जो पौथा हमारे पल्ले बांध रखा है और भी किताबें आप हमें देंगे, यह तो एम०एल०ए० तक ही रह जाएगा या अधिकारी इसको पढ़ लेंगे लेकिन आम लोगों तक वही बात जाएगी जो आपने कल अखबार में दी है। यह बजट की कापी आम आदमी के पास नहीं जाएगी। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी की काबलियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं और इसी बात से स्टेट की परफोरमैंस का पता लगता है। दूसरा कोई डाकूमेंट लोगों के हाथ में नहीं जाएगा। अध्यक्ष महोदय, या तो इस कापी में से वह पेज निकल गया या कोई सीक्रेट बात है जिसको वित्त मंत्री जी बताना नहीं चाहते या फिर ये उन महकमों को जरूरी नहीं समझते क्योंकि उन महकमों की कोई बात इसमें मुझे नहीं मिली। कहीं मेरी गलती न हो या मेरे पास यह बजट की कापी दूसरी न हो। मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट में पुलिस विभाग के बारे में कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने कई महकमों का इस बजट में कोई जिक्र नहीं किया है। आज हरियाणा प्रदेश में ला एंड आर्डर की व्यवस्था खराब होने के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है। अध्यक्ष महोदय, पानीपत के बारे में आपको अच्छी तरह से पता ही है, किसी की कोठी पर कब्जा हो जाता है, किसी फैक्टरी से पैसा लूट लिया जाता है। आज सड़क पर चलते हुए किसी का मर्डर हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, पानीपत ही नहीं सारे हरियाणा में ऐसा हो रहा है। अभी पिछले दिनों मुख्य मंत्री जी जींद में गए थे। अध्यक्ष महोदय, जींद में दिन दहाड़े एक डाक्टर को गोली मारी गई। शायद वह बच तो गया है लेकिन होस्पीटल में है। इस तरह से क्राईम इस प्रान्त में एक जगह नहीं अपितु अनेकों जगह हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी गवर्नरज़ साहब के एड्रैस पर हुई बहस का जवाब देते हुए कह रहे थे कि क्राईम कहीं भी हो सकता है। मैं मानता हूं कि क्राईम कहीं भी हो सकता है सरकार उसका पहरा नहीं दे सकती। सरकार उसकी रखवाली करने के लिए नहीं बैठ सकती। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के क्राईम को रोकने के लिए सरकार की प्रोग्रैस क्या है? उस पर सरकार क्या कंट्रोल कर रही है? अध्यक्ष महोदय, जहां पर उस डाक्टर को गोली मारी गई वह जगह थाना सदर से 10 कदम की दूरी पर है, वहां से 10 कदम की दूरी पर पुलिस चौकी है और वहां से 10 कदम की दूरी पर बैरियर है इसलिए पुलिस वहां पर तैनात रहती है। जहां पर खुला बाजार है इसलिए वहां पर भीड़ रहती है। उस डाक्टर को दिन के 11.00 बजे गोली मारी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे क्राईम को रोकने के लिए सरकार ने क्या इंतजाम कर रखे हैं? अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने इस बजट में तो पुलिस विभाग के लिए पैसे का कोई प्रोविजन नहीं रखा है। इस बजट की कापी में यह शो ही नहीं किया कि प्रोविजन है भी या नहीं। फिर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा कैसे होगी? आप सड़कें बनाने के नाम पर लोगों को खुश कर देंगे, स्कूलों के कमरे बनाने के नाम पर लोगों को खुश कर देंगे, स्कूल अपग्रेड करने के नाम पर लोगों को खुश कर देंगे और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से लोगों को खुश कर देंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश के अन्दर ला एंड आर्डर के हालात ऐसे हैं कि प्रदेश का कोई भी नागरिक दिन के समय भी अपने घर से बाहर नहीं जा सकता। अध्यक्ष महोदय, गन्नौर में दो बार रेल के अन्दर डकैती हुई। तिवाड़ी के पास बस की सवारियों को लूट लिया गया। रेल में सफर करना सुरक्षित नहीं, बस में सफर करना सुरक्षित नहीं।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपने लंच ब्रेक तो खत्म कर दिया है और मुख्य मंत्री

जी भी कह रहे थे कि लगातार बोलते रहें।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर हाऊस की सहमति हो तो समय 5 मिनट बढ़ाया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है हाउस का समय 5 मिनट और बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि पुलिस एक बहुत ही जरूरी महकमा है। इसको इस बजट में कुछ नए हथियार और नई तकनीक देने के बारे में पैसे का प्रोविजन करना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पुलिस की भर्ती में जो बच्चे भर्ती होने के लिए खड़े होंगे उनके फार्म के नाम पर 500 रुपये लिये जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बजट में इन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया कि ये पुलिस के लिए क्या करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने लोकल बाडीज डिपार्टमैंट का नाम बदल दिया है और अब उसका नाम नगर विकास विभाग रख दिया है। सरकार ने म्युनिसिपल कमेटी के नाम पर टैक्स तो लगा दिए लेकिन जो नया नाम इन्होंने नगर विकास रखा है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। इसी प्रकार से इन्होंने कई महकमे तोड़ दिए। फोरेस्ट, लेबर एण्ड एम्पलाएमेंट, एक्साईज एण्ड टैक्सेशन, हरिजन कल्याण निगम आदि विभागों का नाम भी इस बजट में से गायब हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने महिला डे पर महिलाओं के बड़े गुणगान किये थे लेकिन इस बजट में महिलाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं, कोई जिक्र नहीं है। वित्त मंत्री जी मैं इस बात को आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि आपका जो गवर्नर एड्रैस था वह आपके बजट से कहीं बहुत बढ़िया था, यह मैं मानता हूं।

हरियाणा में पीछे काफी सूखा पड़ा। सूखा पड़ना किसी के बस की बात नहीं है। इसी प्रकार से हम यह भी नहीं कह सकते कि बाढ़ नहीं आ सकती। बाढ़ कभी भी आ सकती है। इस बजट में बाढ़ की क्या रोकथाम सरकार की तरफ से की जायेगी, कोई जिक्र नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर एस०वाई०एल० नहर के बनाये जाने के बारे में भी इस बजट में कोई जिक्र नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी यहां पर सैशन होता है तो हमारे तीनों मुख्य मंत्री, श्री बंसी लाल जी, भजन लाल जी, चौटाला साहब कहते हैं कि मैंने इतना काम इस नहर का करवाया है दूसरा कहता है कि मैंने इतना काम इस नहर का करवाया है लेकिन नहर तो आज तक बन नहीं सकी। इस बारे में मेरा आपसे सुझाव है कि जब भी एस०वाई०एल० मुद्दे पर चर्चा हो तो इन तीनों मुख्य मंत्रियों को एक कमरे में बैठा दिया करें और दूसरे विधायक साथी भी अपनी बात अच्छी तरह से एस०वाई०एल० के बारे में कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पर गंगा का पानी भगीरथ जी लेकर आये थे। उसको आज तक सभी याद करते हैं। इस एस०वाई०एल० के बारे में मेरा कहना है कि जो भी मुख्य मंत्री इस एस०वाई०एल० का पानी लेकर आयेगा वह भी भगीरथ की तरह याद किया जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी मैं विरोधी पक्ष के नाते नहीं कह रहा बल्कि एक सुझाव मैं आपको दे रहा हूं। चूंकि आज आप मुख्य मंत्री के पद पर हैं और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है इस एस०वाई०एल० नहर को बनवाने की। क्योंकि

[श्री मांगे राम गुप्ता]

पंजाब में जब कोई उद्घाटन होता है तो वहां के चीफ मिनिस्टर आपको बुलाते हैं या आप उनको यहां पर बुलाते हैं। रिश्ते में वे आपके अंकल लगते हैं। यदि आप अब भी इस नहर को नहीं बनवा पायेंगे तो फिर ये हरियाणा के लोग आपको माफ नहीं कर पायेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस नहर को जितना जल्दी हो सके बनवाने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय के जवाब के दौरान मुख्य मंत्री ने एक जो बात कही थी वह मुझे बहुत अखर रही है। क्या इनकी काबलियत है, इन्होंने जनता की क्या नब्ज पकड़ी है मुझे पता नहीं। इन्होंने राष्ट्रपाल महोदय का जवाब देते हुए बड़े घमण्ड के साथ कहा कि मैं आजीवन मुख्य मंत्री रहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं क्या इनको किसी ज्योतिषी ने बताया है कि ये आजीवन मुख्य मंत्री रहेंगे। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बजट पर बोलें।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, 1977 में इनके पास 82 एम०एल०एज० थे और बाद में फिर इनके पास 87 एम०एल०एज० थे। तब भी ये अपनी सरकार पूरे समय नहीं चला पाये।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी आप बजट पर बोल चुके हैं। अब आपका समय समाप्त होता है।

Now, the House stands adjourned till 2-00 P.M. today, the 13th March, 2001.

*13-55 hrs. (The Sabha then *adjourned till 2-00 P.M. today, the 13th March, 2001)

33157—HVS—H.G.P., Chd.